PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

दिसंबर 2021 / Issue-1

भारत में एग्रो-टेक स्टार्टअप्स

सीओपी-26 में भारत की उद्घोषणाएँ : वादा या वास्तविकता

उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवादी गतिविधियाँ : समाधान की राहे

प्राचीन भारतीय मूर्तियों की विदेश से वापसी

स्कूली शिक्षा पर असर की रिपोर्ट

अंतरजातीय विवाह

ग्लोबल ग्रीन ग्रिड

COP26
Glasgow 2021

dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

OFFLINE & ONLINE

COMPREHENSIVE ALL INDIA IAS PRELIMS TEST SERIES 2022

TOTAL TESTS - 27

STARTED ON
28th NOV AND ONGOING

DHYEYA POWER

Phase	Features
Period : Nov. 2021 to Feb. 2022 **Autumn Phase** **Total 13 Tests** (Sectional + Current Affairs)	• Focused development to ensure achievements. • NCERT revision test. • Theme based test. • Segment wise test of GS. • Test of Current Affairs and miscellaneous.
Period : March 2022 to May 2022 **Knock out** **Total 14 Tests** (3 Sectional + 6 GS Full Test + 4 CSAT+ 1 Full Current Affairs)	• Power packed Programme created for cracking UPSC/IAS Exam. • Provide real feeling of UPSC/IAS Preliminary Exam. • Full GS and CSAT tests.

Full Package (Autumn Phase +Knock Out)
Offline: Rs. 14,000/-
Online: Rs. 8,000/-

Autumn Phase
Offline: Rs. 8,000/-
Online: Rs. 5,000/-

Knock Out Phase
Offline: Rs. 8,000/-
Online: Rs. 5,000/-

DHYEYA ADVANTAGE

- 20% for non Dhyeya students who have cleared UPSC Prelims at least once.
- 20% for Dhyeya Students.
- 40% for Dhyeya Students who have cleared UPSC Prelims at least once.

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | **LAXMI NAGAR :** 9205212500, 9205962002 | **RAJENDRA NAGAR:** 9205274743 | **UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ:** 0532-2260189, 8853467068 | **LUCKNOW** (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | **LUCKNOW** (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | **GREATER NOIDA:** 9205336037, 38 | **KANPUR:** 7887003962, 7897003962 | **ODISHA BHUBANESWAR:** 9818244644/7656949029

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DSC
DHYEYA SCHOOL OF COMPETITION
A unit of Dhyeya IAS

COMPREHENSIVE

UP-PCS MAINS KNOCK OUT PHASE

TEST SERIES PROGRAMME

STARTS FROM

6th DECEMBER, 2021

TOTAL TEST

08

ENROLL NOW
www.dhyeyaias.com

DHYEYA EDGE

- ☑ Time bound (12 Days) evaluation by experts close to real evaluators of UPPSC.
- ☑ Personalised interactive discussion by subject experts on one-on-one basis through online mode.
- ☑ Bilingual Model answer of each question would be provided after the test .
- ☑ To develop the understanding of current UPPSC pattern and coverage of entire syllabus.
- ☑ To develop Answer-Writing Skills among candidates.

Fee Structure

OFFLINE: 6,000/-
ONLINE: 5,000/-
Inclusive of all taxes

DHYEYA ADVANTAGE

- 20% for those who have cleared UPSC/UPPSC Mains, at least once.
- 10% for those who have cleared UPSC/UPPSC Prelims.
- 10% for Dhyeya Students.

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | **LAXMI NAGAR :** 9205212500, 9205962002 | **RAJENDRA NAGAR:** 9205274743 | **UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ:** 0532-2260189, 8853467068 | **LUCKNOW** (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | **LUCKNOW** (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | **GREATER NOIDA:** 9205336037, 38 | **KANPUR:** 7887003962, 7897003962 | **ODISHA BHUBANESWAR:** 9818244644/7656949029

PREFACE

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाय। परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, 7 मॉडल प्रश्नोत्तर, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिकाओं, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर है। मध्यकालीन भारत से पूछे जाने वाले शब्दावली और अन्य आयामों एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा. विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टर्स और 7 ग्राफिक्स के जरिये किसी विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहेगी। परफेक्ट 7 मैगजीन में हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशन्स ट्रैकर नामक एक नया खंड शुरू कर रहे हैं जिसमें सभी परीक्षोपयोगी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी खबरों को ट्रैक किया जाएगा। जैसे यूएनडीपी, यूनेस्को, यूनिसेफ, एफएओ, आईएलओ, आईयूसीएन, आईपीसीसी, यूएनएफसीसीसी इत्यादि क्योंकि इस खंड से सिविल सेवा परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न वैश्विक पहलों, अभियानों पर पूछे ही जाते हैं.

इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नही बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। हमें उम्मीद हैं कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा

विनय कुमार सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

संपादक	• विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	• क्यू. एच. खान
सहसंपादक	• गौतम तिवारी
उप–संपादक	• आशुतोष मिश्र
	• सौरभ चक्रवर्ती
संपादकीय सहयोग	• मनीष सिंह
	• गौरव
	• शिवांगी वर्मा
मुख्य लेखक	• विवेक ओझा
मुख्य समीक्षक	• ए.के श्रीवास्तव
	• विनीत अनुराग
	• बाघेन्द्र सिंह
आवरण सज्जा एवं विकास	• प्रगति केसरवानी
	• पुनीष जैन
टंकण	• सचिन
	• तरून
कार्यालय सहायक	• राजू
	• चन्दन
	• अरुण

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR	: 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR	: 9205274743
LAXMI NAGAR	: 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD	: 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ)	: 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR)	: 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA	: 9205336037, 9205336038
KANPUR	: 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR	: 8599071555
SRINAGAR (J&K)	: 9205962002

PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

विषय सूची

समसामयिक लेख ———————————— 1-13

- भारत में एग्रो- टेक स्टार्ट अप्स
- सीओपी- 26 में भारत की उद्घोषणाएँ : वादा या वास्तविकता
- उत्तर पूर्वी भारत में उपवादी गतिविधियाँ : समाधान की राहे
- प्राचीन भारतीय मूर्तियों को विदेश से वापस लाना क्यों जरूरी
- स्कूली शिक्षा पर असर की रिपोर्ट
- अंतरजातीय विवाह
- ग्लोबल ग्रीन ग्रिड

संक्षिप्त मुद्दे राष्ट्रीय -------------------------------- 13-15

संक्षिप्त मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय ------------------------------ 15-17

संक्षिप्त मुद्दे पर्यावरण -------------------------------- 18-20

संक्षिप्त मुद्दे विज्ञान एवं तकनीक ----------------------20-21

संक्षिप्त मुद्दे आर्थिक -------------------------------- 21-22

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें -------23-27

ब्रेन बूस्टर --------------------------------------- 28-34

राजव्यवस्था तथा समसामयिक बहुविकल्पीय प्रश्न -------35-41

GS Paper IV के लिए हल केस स्टडी ------------------- 42

जयंती विशेष ------------------------------------- 43

आर्थिक शब्दावली ---------------------------------- 44

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES ©
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1 भारत में एग्री-टेक स्टार्टअप्स

- सन्दर्भ
- परिचय
- भारत में एग्री-टेक स्टार्टअप की संभावनाएं
- एग्री-टेक स्टार्टअप में भारत के सम्मुख चुनौतियाँ
- एग्री टेक -स्टार्टअप्स से लाभ
- निष्कर्ष

सन्दर्भः

भारत की एग्री-टेक कंपनियो को भारी मात्रा में निवेश प्राप्त हो रहे हैं. एग्रीटेक स्टार्टअप ग्रामोफोन ने सियाना कैपिटल से एक फंडिंग राउंड में 25 करोड़ रुपये जुटाए हैं इसके साथ ही एग्रीटेक स्टार्टअप वेकूल ने लाइटबॉक्स, एलजीटी लाइटस्टोन और अन्य जैसे निवेशकों से करीब 70.6 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. यह भारतीय एग्री-टेक स्टार्टअप्स पर निवेशकों के बढ़ते विश्वास को प्रदर्शित करता है.

परिचयः

एग्री-टेक स्टार्टअप से तात्पर्य कृषि की मूल्य वर्धित श्रृंखला के किसी भी चरण में तकनीक के प्रयोग सम्बन्धी नवीन उद्यम से है. आज देश में एक हजार से ज्यादा एग्रीटेक स्टार्टअप काम कर रहे हैं. वर्तमान में भारत एग्री- टेक स्टार्टअप स्पेस में अमेरिका तथा चीन का प्रतिद्वंदी बन कर उभरा है. ये स्टार्टअप कंपनियां कृषि के क्षेत्र में मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों का प्रयोग कर रही हैं. निंजाकार्ट देहात क्रो फार्म जैसी कई स्टार्ट कंपनियां है जिन्होंने भारतीय एग्रीटेक क्षेत्र को नया आयाम प्रदान किया है.

भारत में एग्री-टेक स्टार्टअप की संभावनाएं :-

- भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की 49% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है. भारत में कृषि क्षेत्र का आर्थिक विकास अपने चरम तक नहीं पहुंच सका है अतः इसमें आर्थिक वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं.
- भारत में कृषि उत्पाद से लेकर विपणन तक के मध्य एक लंबी मूल्य वर्धित श्रृंखला कार्य करती हैं. इन समस्त श्रृंखलाओं में तकनीकी की आवश्यकता है जिससे अधिकतम एफिशिएंसी प्राप्त की जा सके.
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार फसल कटाई के उपरांत भारतीय किसानों को लगभग 90000 करोड रुपए का नुकसान हो जाता है तथा इसका लाभ बिचौलिए उठाते हैं अथवा बुनियादी संरचना के अभाव में फसल खराब हो जाती है. एग्री टेक कंपनियां इस अंतर को कम करने में उपयोगी हो सकती हैं.
- भारत में सरकार निरंतर कृषि क्षेत्र में तकनीकी के प्रवेश को बढ़ावा दे रही है. हाल ही में सरकार द्वारा कृषि में डिजिटल प्रगति को बढ़ाने के संदर्भ में एक मसौदा जारी किया गया है. यह एग्रीटेक को समर्थन करता है.
- नास्कॉम द्वारा 2019 में जारी एग्री टेक इन इंडिया इमर्जिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुल 3000 के आसपास स्टार्टअप है जिनमें 450 से अधिक भारत में है. वर्तमान में यह संख्या 600 से 700 के आसपास पहुंच चुकी है.
- एर्नस्ट एंड यंग की 2020 की एक स्टडी के अनुसार भारत के एग्रीटेक बाजार में 2025 तक 24 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है. विभिन्न एग्रीटेक सेगमेंट्स में सप्लाई चेन की तकनीकी स्वयमेव 12.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है.
- 2014 में एग्रीटेक स्टार्टअप्स में सकल निवेश 162 मिलियन डॉलर का था वही अक्टूबर 2021 में देहात एक एग्री स्टार्टअप का अकेले नि. वेश 115 मिलियन डॉलर का है. जो अपने आप में एग्री टेक स्टार्टअप्स की वृद्धि को दर्शा रहा है. वर्ष 2021 के प्रथम अर्धवार्षिक में भारत ने 2 बिलियन डॉलर का एग्री स्टार्ट निवेश प्राप्त किया है भारत अमेरिका 9.5 बिलियन चीन 4.5 बिलियन के बाद रीस्टार्ट प्राप्त करने में तीसरे स्थान पर है.
- हाल ही में सरकार द्वारा लाये गए तीनो विधयेक कृषि को एक बिजनेस के रूप में परिवर्तित करने में सहायक होंगे जो एग्री-स्टार्ट. अप्स के लिए बेहतर होगा.

एग्री-टेक स्टार्टअप में भारत के सम्मुख चुनौतियाँ:-

- भारत के अधिकांश कृषक निरक्षर हैं. ऐसे में भारतीय कृषको से तकनीकी रूप से कृषि की उम्मीद नहीं की जा सकती. भारत में कृषि का मशीनीकरण मात्र 40% है (आर्थिक समीक्षा 2019-20)
- भारत में किसानो तथा सरकार के मध्य बिचौलियों की एक बड़ी कड़ी उपलब्ध है. जो किसान की तात्कालिक आवश्यकता को पूर्ण कर उसे अधिक लाभ से वंचित कर देते हैं.
- अधिकांश छोटे और सीमांत किसान प्रौद्योगि. की के प्रति अनुकूल नहीं होते हैं. अधिकांश किसान क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण से पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं जिसके फलस्वरूप कृषक एग्री-स्टार्टअप्स के प्रति अधिक जागरूक नहीं है.

जिनसे वे वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं कर पाते.

- भारत की डिजिटल डिवाइड तथा डिजि. टल निरक्षरता एग्री-स्टार्टअप्स की गति में बड़ी अवरोधक है.
- भारत का लगभग 65% से अधिक भूमि सिंचाई के स्थान पर मानसून पर निर्भर है. वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के उपोत्पाद के रूप में मानसून में विचलन भी देखा गया है.
- एक मजबूत डाटा संरक्षण अधिनियम के आभ. ाव में कृषक डाटा के दुरूपयोग की सम्भावना बढ़ सकती है. इसके साथ ही साथ साइबर सुभेद्यता भी इस समस्या को बढ़ा देती है. एग्री-स्टार्टअप्स के साथ भी यह समस्या जुडी हुई है.
- भारत में डाटा स्पीड , सस्ते नेट की कमी जैसी समस्याएं भी विद्यमान हैं. उत्तर पूर्वी क्षेत्रो में अभी तक 2G संचार तकनीकी नहीं पहुंच सकी है। यह स्थिति एग्री-स्टार्टअप्स की पहुंच को सीमित करती है.
- अधिकांश छोटे और सीमांत किसान प्रौद्योगिकी के प्रति अनुकूल नहीं होते हैं. अधिकांश किसान क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण से पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं और इस प्रकार के महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों में इन किसानों की अनदेखी कर दी जाती है.
- प्रारम्भिक अवस्था में ऑनलाइन विपणन तथा कृषि में तकनीकी उन्नयन के प्रति कृषको में विश्वास की कमी रहती है.

एग्री टेक -स्टार्टअप्स से लाभ:

- भारत में उत्पादन के उपरांत बाजार तक पहुंचने में लगभग 20 से 25% अनाज नष्ट हो जाते हैं। एग्री टेक स्टार्टअप्स इन आंकड़ों को कम कर सकते हैं.
- भारत में कृषि क्षेत्र अभी भी आर्थिक दृष्टिकोण से अनएक्सप्लॉरड है एग्री टेक भारतीय कृषि क्षेत्र के संपूर्ण आर्थिक विकास में सहयोगी हो सकते हैं.
- एग्री टेक स्टार्टअप्स के सहयोग से फसल उत्पादन से लेकर विपणन तक के मार्ग में तकनी. की का उन्नयन हो सकता है जिससे कृषि में रोबोटिक्स तथा ड्रोन जैसे तकनीक का प्रयोग बढ़ेगा। यह प्रेसीजन फार्मिंग को बढ़ावा देगा.
- भारतीय कृषि में वित्त की एक महत्वपूर्ण समस्या आ रही है एग्री टेक स्टार्टअप्स की बढ़ती हुई फंडिंग से यह समस्या समाप्त हो सकती है
- यह भारतीय कृषि की छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकता है.
- यह कृषक आय के दोगुने होने के लक्ष्य में सहायक हो सकता है.

निष्कर्ष-

निसंदेह एग्रीटेक का बढ़ना भारतीय कृषि के उन्नयन के लिए आवश्यक है. एग्री टेक स्टार्टअप्स की मौजूदा स्थिति यह दर्शाती है कि एग्रीटेक में अत्यंत संभावनाएं विद्यमान हैं जो कृषि आय को बढ़ा सकती हैं. नीति आयोग के @75 डॉक्यूमेंट में एग्रीकल्चर से एग्रीप्रेन्यूर की तरफ बढ़ने का सुझाव दिया है. जिसे एग्री स्टार्टअप्स वास्तविकता प्रदान कर रही हैं.

■■■■

2 सीओपी-26 में भारत की उद्घोषणाएं: वादा या वास्तविकता

- सन्दर्भ
- परिचय
- ग्लास्गो सम्मलेन में भारत की उद्घोषणाएं भारत के सन्दर्भ में
- भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर सुधार हेतु दिए गए अन्य महत्वपूर्ण सुझाव
- उद्घोषणाओं की पूर्ति के मार्ग में चुनौतियाँ
- भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए किये जाने वाले अब तक के प्रयास
- निष्कर्ष

संदर्भः

हाल ही में भारत द्वारा ग्लास्गो सम्मलेन (यू.एन.एफ.सीसी-सीओपी-26) में पंचामृत सिद्धांत सहित कई उद्घोषणाएं की गई. भारत की बढ़ती जनसँख्या हेतु ऊर्जा आवश्यकता तथा तकनीक व वित्त की कमी को ध्यान में रखते हुए इन उद्घोषणाओ के प्राप्तिकरण का मार्ग अत्यंत कठिन प्रतीत होता है.

परिचयः

जलवायु परिवर्तन पर आयोजित यूएनएफसीसी की कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26 वीं बैठक ग्लास्गो में आयोजित की गई. जलवायु परिवर्तन पर हो रहे गतिरोध , पेरिस सम्मलेन की अनिश्चितता तथा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों के मध्य सम्पूर्ण विश्व को इस सम्मलेन से उमीदें थीं. भारत इस सम्मलेन में पर्यावरण के प्रति अपनी सकारात्मक नीति लेकर प्रस्तुत हुआ. भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निदान हेतु "पंचामृत सिद्धांत" सहित कई मुख्य उद्घोषणाएं की गई हैं. वर्तमान में भारत की औद्योगिक प्रगति, आर्थिक विकास तथा बड़ी जनसँख्या की उच्च जीवन गुणवत्ता, की आवश्यकताओं की पूर्ण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रति तकनीक की कमी के द्वन्द्व के मध्य इन उद्घोषणाओ की पूर्ति कठिन प्रतीत हो रही हैं.

ग्लास्गो सम्मलेन में भारत की उद्घोषणाएं भारत के सन्दर्भ में -

- **पंचामृत की प्रतिबद्धताएं**

सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत रूपी 5 प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई हैं. इसके 5 प्रतिबद्धताएं निम्न हैं-

1. भारत 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावॉट तक पहुंचाएगा.
2. भारत 2030 तक अपनी समग्र ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूर्ण करेगा.
3. भारत 2030 तक अपने कुल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करेगा.
4. 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा.
5. वर्ष 2070 तक अर्थात अगले 50 वर्षों में भारत नेट जीरो लक्ष्य हासिल करेगा.

- इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने "संगछ्ध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम" के मंत्र की प्रासंगिकता को बताया है.

- प्रधानमंत्री ने भारत में नल से जल स्वच्छ भारत मिशन उज्जवला जैसी परियोजनाओं से प्राप्त अनुकूलन के लाभ को बताया है.
- उन्होंने पारंपरिक समुदाय में प्रकृति के सद्भाव को रहने की आवश्यकता तथा अनुकूलन नीतियों को उचित स्थान व स्कूल पाठ्यक्रम में जोड़े जाने की आवश्यकता को बताया है.
- उन्होंने कहा कि भारत ने आपदा प्रबंधन हेतु कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इन्फ्रास्ट्रक्चरल पहल की शुरुआत की है तथा विश्व से इस पहल से जुड़ने का अनुरोध किया है.

भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर सुधार हेतु दिए गए अन्य महत्वपूर्ण सुझाव -

- भारत ने इंगित किया है कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में किये गए अब तक के प्रयास मात्र नीतियों में रहे तथा धरातल पर परिलक्षित नहीं हुए. वित्त तथा तकनीकी हस्तांतरण का प्रावधान छद्मता से पूर्ण था. जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अब तक अनुकूलन पर प्रयास नहीं किये गए जो कि अति अनिवार्य थे.
- भारत ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध वैश्विक आंदोलन का प्रस्ताव रखा है तथा यह सुझाव दिया है कि शब्द लाइफ **(LIFE)** लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इस आंदोलन का आधार बने.
- विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संकटग्रस्त रहते हैं तथा किसानो पर जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है. अतः इन देशो को वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है. भारत ने सहयोग के रूप में मुक्त तकनीकी तथा वित्तीय स्थानांतरण के को आवश्यक बताया है.
- इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत द्वारा दिया गया पंचामृत सिद्धांत अत्यंत महत्वकांक्षी है. इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत के सम्मुख अनेकानेक चुनौतियाँ भी हैं.

उद्घोषणाओं की पूर्ति के मार्ग में चुनौतियाँ-

- नीति आयोग की @75 रिपोर्ट के अनुसार भारत के सकल ऊर्जा में कोयले की 49.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसके बाद तेल (28 प्रतिशत), बायोमास (11.6 प्रतिशत), गैस (7.3 प्रतिशत), नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा (2.2 प्रतिशत) और परमाणु ऊर्जा (1.2 प्रतिशत) है. इस प्रकार फॉसिल ऊर्जा 77. 6 % प्रयोग होती है. 2030 तक फॉसिल ऊर्जा को 27% कम करना कठिन है.
- जुलाई 2019 तक देश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 360456 मेगावाट थी. जिसमे तापीय विद्युत 63.2% जल विद्युत-परमाणु विद्युत 1.9% तथा नवीकरणीय ऊर्जा 22.0% का योगदान करती है. भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना आरम्भ करने के साथ साथ 2008 से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर कार्य प्रभावी रूप से आरम्भ हुआ है। पिछले लगभग 15 वर्षो में यह प्रगति 22% रही है ऐसे में मात्र अगले 8 वर्षो में इसे 50% पहुँचाना कठिन है.
- भारत में मेक इन इंडिया ,स्टार्टअप इन्डिया, डिजिटल इण्डिया जैसी योजनाओं की सफलता तथा अर्थव्यवस्था को निर्यातोन्मुख बनाने के लिए अधिशेष उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता है.
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु भारी निवेश की आवश्यकता होगी. कोरोना के उपरान्त निवेश परिदृश्य में अनिश्चितता की स्थि. ति है अतः निजी निवेशक नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश हेतु सशंकित रहेंगे. सरकार निरंतर घाटे में रहती है तथा कोरोना में राजकोषीय घाटा 12.34 लाख करोड़ के आस-पास पहुंच गया था अतः यह स्पष्ट है कि सरकारी निवेश से राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी.
- यह स्पष्ट है कि भारत को आर्थिक विकास की गति प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है. कोरोना के उपरांत बढ़ रही अर्थव्यवस्था में हाल ही में कोयले की कमी से एक आशंका का माहौल बन गया था जो ऊर्जा उत्पादन में भारत की कोयले पर निर्भरता को प्रदर्शित करता है। कोयले से उत्पादन में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है. तकनी. की के अभाव में ऊर्जा आपूर्ति को बिना रोके 2030 तक प्रायोजित कार्बन उत्सर्जन में एक बि. लियन टन की कमी करना कठिन कार्य है.ध्यातव्य है कि वर्तमान में भारत वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में तीसरे स्थान पर है.
- नेट जीरो का अर्थ यह है कि सभी देशों को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए कार्बन न्यूट्रैलिटी यानी कार्बन के उत्सर्जन में तटस्थता प्राप्त करना है।यह कार्बन उत्सर्जन की शून्यता न होकर किसी देश द्वारा वायुमंडल में उसकी ओर से भेजी जा रही ग्रीनहाउस गैसों के जमाव को स्थिरता है। वैश्विक स्तर पर 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है जबकि भारत ने 2070 तक. विकासशील देश होने की वजह से अभी भारत की निर्भरता जीवाश्म ईंधन पर अधिक है. विकसित देशों के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही हैअतः दो-तीन दशकों तक भारत के उत्सर्जन स्तर के नीचे आने की कोई संभावना नहीं है.
- असिंचित कृषि भूमि की सिंचाई में भारी मात्रा में डीजल का प्रयोग होता है जो एक प्रमुख जीवाश्म ईंधन है.
- वैश्विक स्तर पर वित्त तथा तकनीकी के हस्तांतरण का अनुचित प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है. इन चुनौतियों के साथ साथ भारत में अनेक नीतिगत समस्या यथा विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और कर ऊर्जा बाजार को विकृत करते हैं और कुशल ईंधन से अधिक अक्षम के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ व्यावहारिक समस्याएं यथा -कृषि सिंचाई में सब्सिडी प्राप्त विद्युत का अतिशय प्रयोग हैं जो इन लक्ष्यों को पूर्ण होने में बाधक हैं.

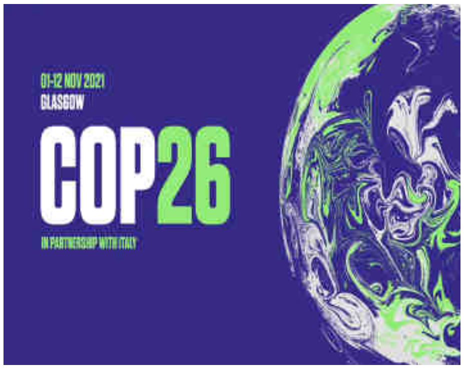

भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए किये जाने वाले अब तक के प्रयास-

- भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ाना भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन प्राप्त होना इसकी विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है.
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दिए गए आकड़ो से स्पष्ट है कि जुलाई 2018 तक 23.12 गीगावाट की सौर क्षमता स्थापित कर चुका है तथा निरंतर इस मार्ग में आगे बढ़ रहा है. 2018 में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में कहा गया कि स्थापित क्षमता के अतिरिक्त 24.4 गीगावाट सौर ऊर्जा के लिए निविदा जारी की जा चुकी है. अतः भारत भारत 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के पूर्व निर्धारित लक्ष्य तथा पंचामृत की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है.

- भारत निरंतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अन्य क्षेत्रो यथा पवन ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है. इसी क्रम में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रलय के तहत एकस्वायत्त संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी (एनआईडब्ल्यूई) ने गुजरात के तट के पास खम्बात की खाड़ी में अपतटीय पवन संसाधन के आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग उपकरण "लीडर" स्थापित किया है. भारत निरंतर तटीय क्षेत्रो में पवन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ा रहा है.
- भारत का निजी क्षेत्रक भी इसमें लगातार आगे बढ़ रहा है. भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ़्टवेयर सर्विसेज फर्म, इंफोसिस ने 2017/18 के दौरान अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अपनी 43 प्रतिशत बिजली आवश्यकताओं को पूरा किया. यह अन्य निजी क्षेत्रको के लिए एक प्रतिमान है.
- क्षेत्रीय स्तर पर कर्नाटक ,गुजरात जैसे राज्यों ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना आरम्भ किया है। कर्नाटक अपनी सकल ऊर्जा आवश्यकता का 27% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर रहा है.
- 2018 से 2022 तक में (मुख्यत: कोरोना काल के दौरान) दौरान विद्युत् निर्माण में कोयले से बनने वाला ईंधन 77 फीसदी से घटकर 66 फीसदी तक आ गया है. यह भारत के प्रयासों को स्पष्ट रूप से दिखाता है.
- पेट्रोल ,डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनके प्रयोग को कम करने के लिए सरकार सोलर पंप, बीएस-6 का प्रयोग, सोलर रूफटॉप, कुसुम तथा स्काई जैसी योजनाओ तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जैसे कदम उठा रही है. सरकार की नवीन वाहन स्क्रेप्पिंग नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किये गया है.• इसी वर्ष केन्द्र सरकार ने अपने बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की भी घोषणा की है, जो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिये एक रोडमैप तैयार करेगा. जिससे फॉसिल ऊर्जा के प्रयोग में कमी आएगी
- वर्ष 2020 में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा जारी साझा रिपोर्ट 'टूर्वाडस ए क्लीन एनर्जी इकोनॉमी' के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग से भारत का परिवहन क्षेत्र 1.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकता है. यह पंचामृत सिद्धांत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा.
- भारत की नल से जल, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओ की सफलता अनुकूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धंता को प्रदर्शित करती हैं.

निष्कर्ष:

यह सत्य है कि भारत के सम्मुख ग्लास्गो की प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में चुनौतियाँ हैं परन्तु जलवायु परिवर्तन की समस्या को देखते हुए इसकी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करना अनिवार्य हो जाता है. यदि वैश्विक स्तर पर तकनीक तथा वित्त का सहयोग मिल जाता है तो ये लक्ष्य आसानी से प्राप्त होंगे। यद्यपि भारत की प्रतिबद्धता यह प्रदर्शित करती है कि कि पेरिस उनके लिए एक समिट नहीं बल्कि सेंटीमेंट तथा कमिटमेंट है. वर्तमान में भारत अपनी क्षमता से जलवायु न्याय का मुख्य स्थापक बन कर उभरा है. अत: भारत की प्रतिबद्धताएं महज वादे नहीं हैं बल्कि भारत इन्हे वास्तविक बनाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील है.

■■■■

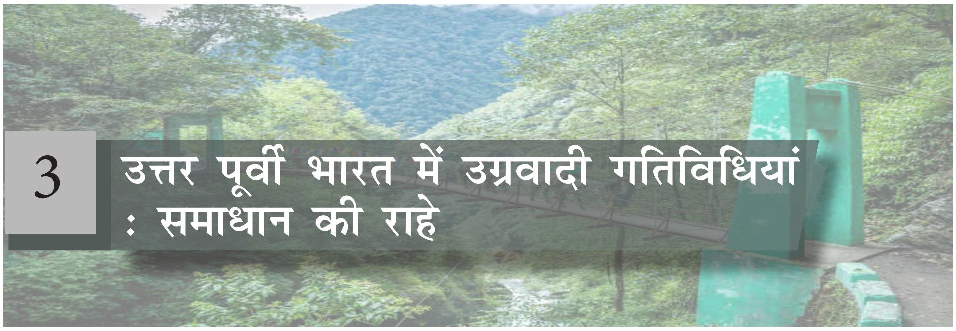

3 उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवादी गतिविधियां : समाधान की राहे

- **चर्चा में क्यों**
- **पृष्ठभूमि**
- **मणिपुर, म्यांमार, नशीले पदार्थों की तस्करी और हिंसक गतिविधियों**
- **पूर्वोत्तर में फिर से उग्रवाद का पनपना**
- **मजबूत इंटेलिजेंस की है आवश्यकता**
- **पूर्वोत्तर में उग्रवादियों का समर्पण**

चर्चा में क्यों?

उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवादी गतिविधियों, विप्लवकारियों द्वारा हिंसक अभियान, अलगाववादी आंदोलनों, नृजातीय हिंसा (एथनिक वायलेंस) लंबे समय से एक गंभीर चुनौती बना हुआ है. हाल ही में देश की सुरक्षा के लिए लगे अर्धसैनिक बल असम राइफल्स के 46वीं असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर(सीओ) कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनकी पत्नी, बच्चे समेत असम राइफल्स के चार जवान उग्रवादियों के हमलों में शहीद हो गए थे. वास्तव में, उग्रवादी हमलों में हुई मौत पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी हिंसा के नए सिरे से पनपने की मंशा को उजागर करता है. मणिपुर के चूरचंद्रपुर के सिंघट इलाके में उग्रवादियों ने घात लगाकर असम राइफल्स के जवानों की जिंदगियां छीन ली.मणिपुर में साथ ही पूर्वोत्तर के अन्य भागों में भी सक्रिय दो प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट (एमएनपीएफ) ने इस हिंसक जघन्य अपराध को अंजाम दिया. दरसअल मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम के बड़े हिस्से में बीते कुछ सालों से आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। इसे देखते हुए सेना ने 14 इनफैंट्री बटालियनों के साथ दो डिविजन हेडक्वॉर्टरों को इन राज्यों में चल रहे उग्रवादियों के खिलाफ अभियानों से हटा. कर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ एलएसी पर लगा दिया है। इसके बाद से एके-47 असॉल्ट राइफल, मशीन गन, एंटी-टैंक माइन और ग्रेनेड जैसे चीन के बनाए हथियार लगातार म्यांमार पहुंच रहे हैं, जहां से वे सीमा पार से भारतीय चरमपंथियों के हाथ में आ रहे हैं.

पृष्ठभूमि:

दरसअल मणिपुर समेत कई ऐसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जहां उग्रवादियों और अलगाववादी संगठनों ने भारत संघ की अखंडता को चुनौती देते हुए उससे बाहर निकलने के लिए स्थानीय जनजातीय लोगों को बहलाया फुसलाया उनका ब्रेन वाश किया और उन्हें अपनी हिंसक गतिविधियों का भाग बनाया. इनमें से कई उग्रवादी संगठनों ने माओवादी विचारधारा से प्रभावित होते हुए लगातार राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया है.

ऐतिहासिक रूप से देखें तो 21 सितंबर, 1949 को मणिपुर जो कि एक देशी रियासत थी, का भारतीय संघ में विलय हुआ था और विलय के

बाद स्वायत्तता की आकांक्षा रखने वाले विद्रोही समूह जैसे यूएनएलएफ, पीएलए, केसीपी, केवा. ईकेएल, और प्रेपक जैसे विप्लवकारी संगठनों ने मणिपुर में पृथकतावादी मांगों को बढ़ावा देते हुए भारतीय संघ से पृथक होने के लिए आंदोलन चलाया. भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई अवसरों पर मणिपुर को आंतरिक रूप से अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए वहां अफ. स्पा कानून के तहत अर्धसैनिक बलों की तैनाती की. उल्लेखनीय है कि जब भी किसी क्षेत्र में अफस्पा लगाया जाता है तो वहां राज्य सरकार की कानून व्यवस्था संबंधी अधिकारों को 3 माह तक अर्धसैनिक बलों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है. भारत सरकार ने समय-समय पर संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा कर भी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है.

मणिपुर, म्यांमार, नशीले पदार्थों की तस्करी और हिंसक गतिविधियों:

मणिपुर की म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और सीमा के आगे 16 किलोमीटर तक के क्षेत्र में मुक्त आवागमन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और यहां इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी हो जाता है कि म्यांमार नशीले पदार्थों की तस्करी वाले स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र का हिस्सा है, इससे मणिपुर में विप्लवकारी समूहों की हिंसक गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को भी समर्थन मिला है. म्यांमार के विद्रोही समूह और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले नगा विद्रोहियों ने गठजोड़ कर मणिपुर और म्यांमार के मध्य चलाई जाने वाली ऊर्जा और अन्य विकास परियोजनाओं को भी निशाना बनाया है. इनमें शामिल हैं - नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और म्यांमार का अराकान साल्वेशन आर्मी। मणिपुर में युवाओं का ड्रग्स की चपेट में आना भी आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है. ऐसे में भारत सरकार को म्यांमार,बांग्लादेश और चीन से कुछ कठोर शर्तों के साथ ड्रग स्मगलिंग, हथियारों की तस्करी, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए ठोस समझौता करने की भी जरूरत है. आतंकी गुटों और उग्रवादियों के खिलाफ सर्जीकल स्ट्राइक भी भारत के पास एक विकल्प के रूप में मौजूद है. सरकारों को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि समावेशी विकास, अवसंरचना निर्माण, कल्याणकारी कार्यों, पूर्वोत्तर के स्थानीय नागरिकों का अर्ध सैनिक बलों के द्वारा परसेप्शन मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करना ही काफी नही है, आक्रामक रणनीतियों पर भी काम करना जरूरी है.

पूर्वोत्तर में फिर से उग्रवाद का पनपना:

दरअसल आज जिस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के उग्रवादी अलगाववादी संगठनों से शांति वार्ता करने में, उनके कैडरों को आत्मसमर्पण कराने में भारत सरकारको पिछले दो सालों में जो सफलता मिली है, उससे कई अन्य विदेशी गठजोड़ वाले उग्रवादी संगठनों के मंसूबों पर पानी फिरने लगा जिससे उनमें सुरक्षा बलों के खिलाफ एक नई बौखलाहट भी पैदा हुई है. जिस तरह से भारत सरकार ने कुछ नागा विद्रोही गुटों, असम के बोडो कैडरों, त्रिपुरा के उग्रवादी गुटों के कैडरों को आत्मसमर्पण कराया है, उससे पूर्वोत्तर भारत के शांति की राह पर चलने के आसार बढ़ते नजर आने लगे थे। भारत सरकार ने बोडो एकॉर्ड, ब्रू एकॉर्ड के जरिये पूर्वोत्तर भारत में एक बेहतर शासन प्रणाली की नींव रखने की कोशिश की और समूचे पूर्वोत्तर भारत के समावेशी विकास के लिए जिस तरह की रणनीतियां बनाई गई हैं, उससे पूर्वोत्तर भारत के कुछ सर्वाधिक रेडिकल उग्रवादी संगठनों को यह लगने लगा है कि केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर भारत की राज्य सरकारें आपस में मिलकर उग्रवाद मुक्त उत्तर पूर्वी भारत का सपना शायद जल्द ही साकार कर लें. यहीं कारण है कि मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और असम के कई हिस्सों में कुछ उग्रवादी संगठन फिर से सिर उठाने लगे हैं। इन उग्रवादी संगठनों ने भारत सरकार को म्यांमार की धरती पर काम कर रहे भारत विरोधी गुटों और साथ ही पूर्वोत्तर भारत के म्यांमार की धरती पर सक्रिय उग्रवादी संगठनों के खिलाफ की गई कार्यवाहियों को काफी गंभीरता से लिया है.

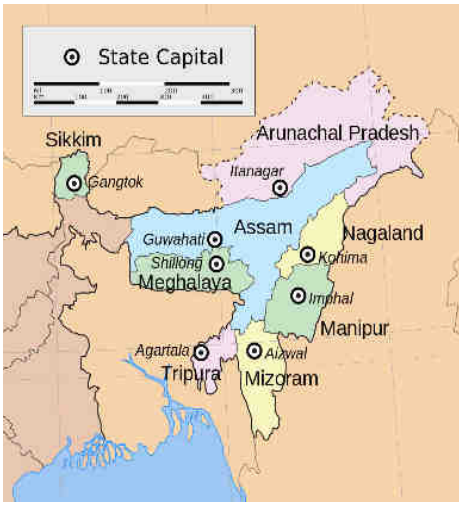

मजबूत इंटेलिजेंस की है आवश्यकता:

पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा बलों के जवानों को जिस तरह निशाना बनाया गया है उससे निपटने के लिए एक प्रभावी और निर्मम रणनीति की जरूरत है. काउंटर इंसरजेंसी अभियानों के समय इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि अर्ध सैनिक बलों में तार्किक समन्वय बना रहे. इसके अलावा जो सबसे बड़ी जरूरत समझ में आती है वो है एक मजबूत इंटेलिजेंस तंत्र का होना. उग्रवादियों, अलगाववादियों, माओवादियों, विप्लवकारियों के हमलों की योजनाओं, उनको हो रही हथियारों की आपूर्ति के स्रोतों, पूर्वोत्तर में टेरर फंडिंग के रास्तों, पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों के चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की धरती पर सक्रिय उग्रवादी विद्रोही संगठनों के साथ गठजोड़ की खुफिया जानकारी समय रहते मिलनी जरूरी है। ऐसे आसूचना तंत्र का कुशलता के साथ निर्माण करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना सुरक्षा बल या अर्ध सैनिक बलों की कार्यवाहियां प्रभावी नहीं हो पाएंगी। ऐसा नही है कि भारत सरकार और पूर्वोत्तर के राज्यों के पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन होने के बावजूद अगर सुरक्षा बलों के जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ती है और निर्दोष नागरिकों को भी उग्रवादी हिंसा का शिकार आये दिन बनना पड़ता है तो इसका साफ मतलब यही है कि चूक कहीं न कहीं तो है. सेना के मनोबल का भी आंकलन करते रहना चाहिए. मणिपुर की हालिया उग्रवादी हिंसक घटना इन्हीं जरूरतों पर फिर से एक नई बहस छेड़ती है.

पूर्वोत्तर में उग्रवादियों का समर्पण:

जनवरी, 2020 में ही पूर्वोत्तर भारत के 8 उग्रवादी समूहों उल्फा (आई), एनडीएफबी (एस), कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बंगालीज, राभा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी), नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी और आदिवासी ड्रैगन फाइटर के उग्रवादियों ने सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वर्ष कुल 2323 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह असम और उत्तर पूर्व की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम है. आत्मसमर्पण करने वालों को गृह मंत्रालय की आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना 2018 के तहत मिलने वाले लाभ भी मुहैया कराए जाएंगे. उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में भी मूल नागा विद्रोही समूहों के गुटों को विश्वास में लेकर उनके कैडरों से आत्मसमर्पण कराने में भारत सरकार और

संबंधित राज्य सरकारों ने इस कोरोना वर्ष में बड़ी सफलता पाई है. हाल ही में असम में भी चार बड़े विद्रोही समूहों युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (इंडिपेंडेंट), युनाइटेड पीपुल्स रेवोल्यूशन. री फ्रंट (यूपीआरएफ), दिमसा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए) पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी (पीडीसीके) के 62 विप्ल. वकारियों ने असम राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के समक्ष गोले बारूद, हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है. असम में उग्रवाद और विप्लवकारी समूहों की गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत और साथ ही देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रही है. उग्रवादी संगठनों ने अलगाववाद के आंदोलनों, नृजातीय पहचान और स्वायत्तता और पृथक राज्य या देश की मांगों के साथ भारतीय संघ के खिलाफ संघर्ष करने की रणनीति के साथ काम किया है. इसी क्रम में असम में उल्फा जैसे उग्रवादी संगठनों ने असम में आंतरिक अशांति को बढ़ावा दिया है.

हाल में असम में आत्मसमर्पण करने वालों में उल्फा (आई) के भूतपूर्व स्वघोषित डेप्युटी कमां. डर इन चीफ दृष्टि राजखोवा भी शामिल है. दृष्टि राजखोवा रॉकेट प्रापेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) में विशेषज्ञ रहा है और असम में हिंसक उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने में मास्टरमाइंड के रूप में अपनी भूमिका निभा चुका है. उल्फा (आई) के कमांडर इन चीफ परेश बरूआ के बाद दृष्टि राजखोवा इस संगठन का दूसरा सबसे प्रमुख व्यक्ति है। असम में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है. जनवरी , 2020 में बोडो पीस एकार्ड के तहत नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के तीन गुटों के 1615 कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया था.

इसके अलावा भारत सरकार, त्रिपुरा और साबिर कुमार देबबर्मा के नेतृत्व में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी-एसडी) के बीच 10 अगस्त, 2019 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. एनएलएफटी पर 1997 से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा हुआ है, यह संगठन अंतरराष्ट्रीय सीमापार स्थित अपने शिविरों से हिंसा फैलाने जैसी गति. विधियों में शामिल रहा है. एनएलएफटी वर्ष 2005 से 2015 की अवधि के दौरान 317 उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते हुए हिंसक का. र्रवाई की, जिसमें 28 सुरक्षा बलों और 62 नागरि. कों को अपनी जान गंवानी पड़ी. एनएलएफटी के साथ 2015 में प्रारंभ हुई शांति वार्ता के बाद से इस संगठन ने 2016 के बाद कोई हिंसक कार्रवाई नहीं की है। एनएलएफटी (एसडी) हिंसा के मार्ग को छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने और भारत के संविधान का पालन करने के लिए सहमत हो गया है. संगठन ने अपने 88 सदस्यों के हथियार सहित आत्मसमर्पण करने पर भी सहमति जताई है। आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को गृह मंत्रालय की आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना, 2018 के अनुसार आत्मसमर्पण लाभ दिया जाएगा। गृह मंत्र. ालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना "वामपंथी चरमपंथियों की आत्मसमर्पण-
सह-पुनर्वास योजना" के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 36 महीने की अधिकतम अवधि के लिए 6,000 रुपये मासिक वजीफे के लिए पात्र बनाया गया है.

■■■■

4 प्राचीन भारतीय मूर्तियों की विदेश से वापसी

- **सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है कला कृतियाँ**
- **सरकार के प्रयास से तस्करी के बाद वापस आई कला कृतियाँ**
- **कुछ अन्य प्रयास**
- **सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े**

सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है कला कृतियाँ:

भारत की प्राचीन मूर्तियां भारत के कलात्मक और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक हैं. विभिन्न प्राचीन साम्राज्यों के शासकों ने मूर्ति और मंदिर स्थापत्य कला के विकास के जरिये अपने लिए मजबूत सांस्कृतिक प्रतिमान गढ़े. देश की प्राचीनतम हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियां विशेष कलात्मक कौशल के साथ बनाई गईं थीं जो उस समाज की आस्था, विश्वास, धर्म, मत, अध्यात्म की विशेषताओं को उजागर करती हैं. यहीं कारण है कि आज भारत के देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियों की तस्करी को रोकने और तस्करी हो चुके मूर्तियों को देश वापस लाने के लिए विभिन्न देशों के साथ भिन्न भिन्न समझौते किये जा रहे हैं और कई देश सहर्ष इस बात के लिए राजी हो रहे हैं कि वे अपने देश में मौजूद भारत की मूर्तियों को वापस लौटा देंगे. इससे दो देशों के मध्य द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों में भी सुधार होगा। पिछले 5 वर्षों में मूर्तियों को देश में वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी आई है. गौरतलब है कि देश से हर साल औसतन 1000 प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां समुद्री रास्ते से दूसरे देश चली जाती हैं. भारत की प्राचीन मूर्तियों की लगातार चोरी होती रहती है. अब तक बहुत सी ऐसी कलाकृतियां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से देश में वापस लाई गई हैं.

सरकार के प्रयास से तस्करी के बाद वापस आई कला कृतियाँ :

हाल ही में कनाडा से प्राप्त देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति को काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर, 2021 को उनके सही स्थान पर स्थापित किया गया. इसके अलावा सितंबर, 2021 में ही भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 157 कलाकृति और पुरावशेष सौंपे गए थे और भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इन पुरावशेषों को भारत को वापस किए जाने के कदम की पुरजोर सराहना की थी. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडन ने सांस्कृ. तिक वस्तुओं की चोरी, अवैध व्यापार और तस्करी से निपटने के प्रयासों को और अधिक मजबूत करने के प्रति अपनी वचनबद्धता भी दोहराई थी. इन 157 कलाकृतियों की सूची में 10वीं सदी की बलुआ पत्थर से बनी रेवंत की डेढ़ मीटर लम्बी नक्काशीदार पट्टिका से लेकर 12वीं सदी की कांसे की 8.5 सेंटीमीटर उंची नटराज की उत्कृष्ट मूर्ति जैसी वस्तुओं का एक विविध सेट शामिल है.

अधिकांश वस्तुएं 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के काल की हैं. इसके साथ-साथ इनमें 2000 ईसा पूर्व की तांबा निर्मित मानववंशीय वस्तु या दूसरी सदी के टेराकोटा निर्मित फूलदान जैसे ऐतिहासिक पुरावशेष भी शामिल हैं. कोई 45 पुरावशेष ईसा पूर्व काल के हैं.

इनमें से आधी कलाकृतियां (71) जहां सांस्कृतिक हैं, वहीं बाकी आधी कलाकृतियों में हिंदू धर्म (60), बौद्ध धर्म (16) और जैन धर्म (9) से जुड़ी मूर्तियां शामिल हैं.

इन कलाकृतियों की निर्माण सामग्री में धातु, पत्थर और टेराकोटा शामिल हैं. कांस्य संग्रह में मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण, बुद्ध, विष्णु, शिव पार्वती और 24 जैन तीर्थंकरों की प्रसिद्ध मुद्राओं की अलंकृत मूर्तियाँ हैं तथा अन्य अनाम देवताओं और दिव्य आकृतियों के अलावा कंकलमूर्ति, ब्राह्मी और नंदीकेश हैं, जिनके बारे में कम लोग जानते हैं.

रूपांकनों में हिंदू धर्म से सम्बंधित धार्मिक मूर्तियां (तीन सिर वाले ब्रह्मा, रथ चलाते हुए सूर्य, विष्णु और उनकी पत्नी, दक्षिणामूर्ति के रूप में शिव, नृत्य करते हुए गणेश आदि), बौद्ध धर्म से सम्बन्धित (खड़ी मुद्रा में बुद्ध, बोधिसत्व मजूश्री, तारा) और जैन धर्म से सम्बन्धित (जैन तीर्थंकर, पद्मासन तीर्थंकर, जैन चौबीसी) के साथ-साथ ध र्मनिरपेक्ष रूपांकनों (समभंग में आकृतिहीन युगल, चौरी वाहक, ढोल बजाती महिला आदि) शामिल हैं.

कुल 56 टेराकोटा टुकड़ों में (फूलदान दूसरी सदी, हिरण की जोड़ी 12वीं सदी, महिला की आवक्ष मूर्ति 14वीं सदी) और 18वीं सदी की तलवार है, जिसके फारसी में लिखे आलेख में गुरु हरगोविंद सिंह का उल्लेख है.

यह भारत सरकार द्वारा दुनिया भर से हमारे पुरावशेषों और कलाकृतियों को वापस लाने के प्रयासों का प्रतिफल है.

कुछ अन्य प्रयास :

इसी कड़ीं में केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने सितंबर , 2020 में वर्चुअल माध्यम से भा. रतीय उच्चायोग, लंदन में 3 मूर्तियों के हस्तांतरण समारोह में भाग लिया था। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की तीन मूर्तियों को ब्रिटिश पु. लिस ने लंदन में भारतीय उच्चायोग को उसके बाद सौंप दिया था. इसके लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा ब्रिटिश पुलिस, स्पेशल आइडल विंग, तमिलनाडु सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं भारतीय उच्चायोग, लंदन का इन कीमती मूर्तियों को भारत वापस लाने के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया गया था. इसके अलावा भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की क्रमशः 90.5 सेमी, 78 सेमी तथा 74.5 सेमी ऊंची कांसे की प्रतिमाएं जो भारतीय धातु कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं , उन्हें भी वापस लाने में सफलता पाई गई है। ये मूर्तियां लगभग 40 साल पहले विजयनगर काल के एक मंदिर से चुरा ली गई थीं. शैलीगत दृष्टि से, इन मूर्तियों का संबंध 15वीं शताब्दी से है. इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट ने अगस्त 2019 में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को सूचित किया कि तमिलनाडु में विजयनगर काल में बने एक मंदिर से चुरायी गयीं चार प्राचीन मूर्तियाँ (श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान) भारत से तस्करी कर शायद ब्रिटेन लाया गयी थीं। इन तीन धातु की मूर्तियां का फोटो प्रलेखन जून 1958 में तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के आनंदमंगलम में स्थित श्री राजगोपाल विष्णु मंदिर (विजयनगर काल के दौरान बनाया गया था) में किया गया था. **इस चित्र में चार मूर्तियाँ थीं- श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की.** इसलिए, मूर्तियाँ कम से कम 1958 तक मंदिर में थीं और बाद में चोरी हो गयीं. संबंधित रिकॉर्ड के साथ मूर्तियों का सत्यापन करने के बाद यह मामला लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की कला और प्राचीन इकाई के साथ-साथ तमिलनाडु पुलिस की मूर्ति शाखा के सामने उठाया गया. तमिलनाडु पुलिस की मूर्ति शाखा ने एक व्यापक रिपोर्ट भेजी जिसमें पुष्टि की गई थी कि मूर्तियों की चोरी श्री राजगोपाल विष्णु मंदिर से 23/24 नवंबर 1978 को हुई थी और बाद में अपराधी भी पकड़े गए थे. तस्वीर के आधार पर, इन मूर्तियों की जांच की गयी और पाया गया कि ये सभी मूर्तियां श्री राजगोपाल विष्णु मंदिर से चुरायी गयी मूर्तियां ही थीं. तमिलना. डु पुलिस की मूर्ति शाखा ने आइएफपी फोटो संग्रह के साथ मूर्तियों का मैच करने को लेकर विशेषज्ञ राय भी प्रदान की. उचित जांच करने के बाद लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के पास एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी गयी.

लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की कला और प्राचीन इकाई ने मामले की जांच की और उन्हें प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर मूर्तियों के मालिक से संपर्क किया और मूर्तियों को वापस लौटाने के भारतीय उच्चायोग के अनुरोध से अवगत कराया, उन्हें बताया गया कि प्रथम दृष्टया

ये मूर्तियां भारत के एक मंदिर से चोरी की गयी मूर्तियां लगती हैं. इसके बाद, मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 15 सितंबर 2020 को भारतीय उच्चायोग को ये मूर्तियां सौंप दीं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तमिलनाडु सरकार की विशेष मूर्ति शाखा, और लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के निरंतर प्रयासों के कारणये मूर्तियाँ अब देश में वापस आ गयी हैं.

सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े :

संस्कृति मंत्रालय यह स्पष्ट कर चुका है कि आजादी के बाद से भारत में विदेशों से केवल 13 मूर्तियां मिलीं, लेकिन 2014 से अब तक देश को 40 से अधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और भारत सरकार आने वाले वर्षों में और अधिक मूर्तियां प्राप्त करने का प्रयास कर रही है. भारत के संस्कृति मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत वाग देवी की मूर्ति को भारत वापस लाने के लिए ब्रिटिश संग्रहालय से बात कर रहा है.

ऑस्ट्रेलिया ने भी घोषणा की कि वह कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी में रखे गए 14 कलाकृतियों को भारत को वापस करेगा. दरअसल लंबी जांच के बाद ऑस्ट्रेलिया को यह पता चला है कि इन कलाकृतियों को तस्करी के जरिए उनके देश में लाकर बेचा गया था.

इसके अतिरिक्त 12वीं शताब्दी ई.पू. की भगवान बुद्ध की 'भूमिस्पर्श मुद्रा' में बैठी हुई कांस्य प्रतिमा को 22 अगस्त, 1961 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के नालंदा संग्रहालय से चुरा लिया गया था और यह मॉस्ट्रिच में एक नीलामी (फरवरी 2018 में लंदन के एक डीलर रॉसी एंड रॉसी द्वारा आयोजित) के दौरान मिली थी. नीलामी की जानकारी मिलने के बाद, राजस्व सतर्कता निदेशालय (डीआरआई) के लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में पदस्थ अधिकारी ने मेट्रोपॉलिटन

पुलिस की आर्ट एंड एंटीक यूनिट से संपर्क किया. एएसआई ने यह भी प्रमाणित किया कि मूर्ति को पुरातत्व संग्रहालय, नालंदा से चुराया गया था। स्कॉटलैंड यार्ड ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2018 को ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त श्री वाई के सिन्हा को यह प्रतिमा सौंपी थी.

कलात्मक परिसंपत्तियों की तस्करी को रोकने का कानून :

पुरावशेष एवं कलाकोष अधिनियम, 1972, 9 सितम्बर, 1972 को कार्यशील हुआ था. इस अधिनियम के अनुसार, पुरावस्तुओं और कला-वस्तुओं में निर्यात व्यापार विनियमित है और पुरावस्तुओं तथा प्राचीन स्मारकों में अवैध तथा धोखाधड़ीपूर्ण व्यापार को रोका गया है.

देश में एंटीक चीजों की चोरी को रोकने के लिए यह कानून महत्वपूर्ण है. इसके तहत धातु से बनी मूर्तियां, पत्थरों से बनी मूर्तियां या दूसरे तरह के आर्ट वर्क, पेंटिंग्स, आभूषण, कागजों पर उकेरी कलाकृतियां, लकड़ी पर नक्काशी, कपड़े पर कलाकृति के साथ-साथ सैकड़ों साल पुरानी पांडुलिपियों को तस्करी से बचाने की बात की गई है. यह एक्ट ये भी कहता है कि इस तरह की प्राचीन कलाकृति अगर किसी निजी संग्रहकर्ता के पास हो तो उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इसे रजिस्टर करना होगा और अगर देश के भीतर भी किसी वजह से कलाकृति किसी दूसरे को बेची जाए तो उसे लाइसेंस लेना होगा. अगर कोई इसका पालन न करे तो उसे सजा का भी प्रावधान हैं. हालांकि कई वजहों से इस एक्ट का सही ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है. यही वजह है कि हर साल अरबों-खरबों कीमत की भारतीय कलाकृतियां दूसरे देशों में जा रही हैं.

इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 जो कि 29 अगस्त, 1958 को प्रवृत्त हुआ था, में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम के अनुसार प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, मूर्ति नक्काशियों तथा इसी तरह की अन्य वस्तुओं, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का संरक्षण एवं परिरक्षण किया जाता है. पुरातत्वीय उत्खननों को विनियमित किया जाता है और वे राष्ट्रीय महत्व के होते हैं.

पुरावशेष एवं कलाकोष और अन्य कलात्मक परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए देश में कुछ अन्य विधान भी हैं जिनमें शामिल हैं:

कोष निधि अधिनियम, 1878
प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904
पुस्तक एवं समाचार वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954
पुस्तक वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय) नियम, 1955
प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम, 1958
प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल अवशेष नियम, 1959
पुरावस्तु एवं कला कोष अधिनियम, 1972
पुरावस्तु एवं कला कोष नियम, 1973
सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993
सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997

■■■■

5 स्कूली शिक्षा पर असर की रिपोर्ट

- संदर्भ
- परिचय
- क्या है रिपोर्ट के मुख्य बिंदू
- ऑनलाइन शिक्षा पर प्रतिवेदन
- अधिगम की स्थिति पर प्रतिवेदन
- ट्यूशन के सन्दर्भ में
- नीतिगत निष्कर्ष
- असर 2021 से कुछ व्यापक नीतिगत निष्कर्ष

संदर्भ-

हाल ही जारी एनुअल स्टेटस आफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान स्कूल एनरोलमेंट में समग्र रूप से कमी आई है.

परिचय:

2005 से 2014 तक प्रत्येक वर्ष और फिर 2018 तक सभी वैकल्पिक वर्ष में, असर ने ग्रामीण भारत के 5-16 आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति उनकी पढ़ने और गणित की अधिगम क्षमता पर निरंतर अपने आकड़े प्रस्तुत किये थे. गत वर्ष कोरोना महामारी के फलस्वरूप ऐसा संभव न हो सका. परन्तु मार्च 2020 से महामारी फलस्वरूप विद्यालय बंद होने के कारण विद्यालयों, परिवारों और बच्चों पर हुए प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण था। इस प्रभाव को समझने हेतु राष्ट्रीय स्तर के डाटा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, असर ने 2020 में एक नवोन्मेषी फोन-आधारित सर्वेक्षण विकसित किया. इस सर्वेक्षण के मध्यम से असर ने यह जानने की कोशिश की कि बच्चे इस समय में कैसे पढ़ रहे हैं? इस वर्ष भी महामारी के कारण राष्ट्रीय स्तर पर गाँव-गाँव जाकर सर्वेक्षण करना संभव नहीं था। इसलिए, असर 2021 भी एक फोन-आधारित सर्वेक्षण के रूप में किया गया. इसमें महामारी के शिक्षा पर प्रभाव की चर्चा की गई.

रिपोर्ट का आधार:

यह रिपोर्ट 25 राज्यों व तीन केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई है. इस रिपोर्ट में 76,706 परिवारों के 5 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के 75234 बच्चों को सम्मिलित किया गया है.

क्या है रिपोर्ट के मुख्य बिंदू

स्कूल नामांकन पर प्रतिवेदन :-

- ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों के स्कूल एनरोलमेंट में समग्र रूप से कमी देखी गई है.
- रिपोर्ट में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश के अनुपात में वृद्धि हुई है. उत्तर प्रदेश और केरल के सर. कारी विद्यालयों में प्रवेश के सम्बन्ध में सर्वाधिक वृद्धि हुई है. उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 13.2 प्रतिशत और केरल में 11.9 प्रतिशत अधिक प्रवेश हुए.

- रिपोर्ट में यह इंगित किया गया कि 2006 से 2014 के मध्य निजी स्कूलों में प्रवेश में निरंतर वृद्धि हुई थी. पिछले कुछ वर्षों में यह औसतन 30% थी. 2020 तथा 2021 में निरंतर निजी स्कूलों के प्रवेश स्तर में गिरावट रही है. 2018 से 2021 में निजी स्कूलों में नामांकन 32.5 % से 24.4% तक हो गया है वहीँ सरकारी विद्यालयों में यह स्थिति 64.3% से 70.3% तक पहुंच गई है. परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह ट्रेंड स्थायी है अथवा महामारी के कारण है. असर की रिपोर्ट ने यह इंगित किया है कि ऐसा महामारी के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में आई कमी के फलस्वरूप हो सकता है.
- 2020 में प्रवेश नहीं लेने वाले बच्चों की संख्या 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई थी। 2021 में भी प्रवेश नहीं लेने वाले बच्चों की संख्या इतनी ही रही.

ऑनलाइन शिक्षा पर प्रतिवेदन :-

- रिपोर्ट ने ऑनलाइन शिक्षा पर भी आकड़े प्रस्तुत किये हैं। स्मार्टफोन के आने से ऑनलाइन शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है. यद्यपि 68 % घरो में स्मार्टफोन की उपलब्धता थी परन्तु उनमे से मात्र एक चौथाई घरो में ही बच्चो की आवश्यकता पर उन्हें ऑनलाइन क्लास हेतु मोबाइल उपलब्ध हो रहा था.
- 26 % बच्चो को मोबाइल तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो सकी वही 47 % बच्चो को कभी कभी मोबाइल प्राप्त हुआ.
- ऑनलाइन क्लास तक पहुंच के मामले में राज्यों में भी असमानता देखी गई है. केरल में 91 % तथा हिमांचल प्रदेश में 80 % बच्चो को ऑनलाइन क्लास उपलब्ध था जबकि बिहार में यह मात्र 10 % तथा पश्चिम बंगाल में यह मात्र 13 % रहा है.

अधिगम की स्थिति पर प्रतिवेदन:-

- स्कूलों में प्रवेश का अधिगम से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है जो कि इस प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से दिखता है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में सम्मिलित बच्चो में से 92 % बच्चे अपने सम्बंधित कक्षा की पुस्तकों को पढ़ने में असमर्थ थे.
- अधिकतम बच्चे शिक्षण हेतु संस्थान पर निर्भर हैं मात्र एक तिहाई बच्चे ही अपने अधिगम क्षमता को बढ़ाने के लिए अन्यत्र स्रोतों को प्रयोग में लाते हैं.

- रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 तथा 2 में पढ़ने वाले 37% बच्चे कभी भौतिक क्लासरूम में नहीं गए हैं। इसके साथ ही महामारी के कारण पारम्परिक शिक्षण पद्धति में अवरोध की स्थिति भी आई है.

ट्यूशन के सन्दर्भ में :-

- 2018 से 2021 में निजी शिक्षकों से ट्यूशन की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है. यह 2018 में 30 % था जबकि 2021 में यह 40 % हो गया है. यद्यपि ऐसी स्थिति विद्यालयों के बंद होने के कारण थी। केरल के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में ट्यूशन में वृद्धि हुई है.

अन्य महत्वपूर्ण विन्दु :-

- शिक्षा हेतु परिवार से मिलने वाले सहयोग में महामारी के दौरान गिरावट देखने को मिली है तथा यह गिरावट कक्षा 9 तथा 10 के स्तर पर सर्वाधिक थी.
- शैक्षिक सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता है। पढ़ने वाले लगभग सभी बच्चो (91%) के पास अपनी पुस्तकें हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त शैक्षिक सामग्री में भी वृद्धि देखने को मिली है.

नीतिगत निष्कर्ष :-

जब 18 महीने बंद रहने के बाद स्कूल फिर से खुल रहे हैं, तो इनके बंद होने के प्रभाव को समझना आवश्यक है जिससे उत्पन्न मुद्दों के समाधान हेतु व्यापक नीतियों का निर्माण किया जा सके.

असर 2021 से कुछ व्यापक नीतिगत निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

नामांकन:

- सरकारी विद्यालयों के नामांकन में पिछले दो वर्षों में वृद्धि हुई है. अत: सरकारी विद्यालयों की अवसंरचना तथा शिक्षकों की क्षमता को इस अनुरूप बनाना अनिवार्य है.

परिवार द्वारा बच्चों की पढ़ाई में सहयोग पर काम करना:

- विद्यालय खुलने के साथ बच्चों को मिलने वाला पारिवारिक सहयोग 2020 से कम हो गया है, परन्तु पारिवारिक सहयोग प्राथमिक कक्षाओं के लिए अभी भी महत्वपूर्ण है.
- शिक्षा की योजनाएँ बनाते समय बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी को ध्यान में रखना चाहिए, जैसा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित है.
- माता-पिता के साथ शिक्षा पर विचार-विमर्श कर यह समझना होगा कि वे अपने बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं?

"हाइब्रिड" लर्निंग:

बच्चे घर पर तरह-तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं. ऑनलाइन सामग्री, शिक्षण संसथान तथा ट्यूशन के समायोजन से हाइब्रिड लर्निंग बढ़ गई है. "हाइब्रिड" लर्निंग के प्रभावी तरीकों को विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे बच्चो का समग्र विकास हो सके.

ट्यूशन:

निजी ट्यूशन जाने वाले बच्चों का अनुपात 2018 के बाद स्कूल बंद होने के दौरान बढ़ गया है. यह ट्यूशन फीस की वहनीयता के आधार पर अमीर तथा गरीब बच्चो की क्षमता में असमानता उत्पन्न करेगा.

"डिजिटल डिवाइड" को कम करना:

- अपेक्षित रूप से ऐसे बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है जिनके परिवारों का शैक्षिक स्तर कम था तथा जिनके पास आधुनिक तकनीक से युक्त स्मार्टफोन नहीं थे. सभी यथासंभव इस स्थिति का सामना कर रहे हैं परन्तु यह डिजिटल डिवाइड को बढ़ा रहा है.
- इस सन्दर्भ में बच्चो के साथ साथ राज्यों में भी असमानता दिख रही है। अत: डिजिटल डिवाइड को कम करना होगा। ऑनलाइन शिक्षा न मिलने वाले बच्चों को विद्यालय खुलने पर दूसरे बच्चों की अपेक्षा अधिक सहयोग की आवश्यकता होगी.

स्मार्टफोन की उपलब्धि:

- असर 2021 इस बात को दर्शाता है कि परिवार में स्मार्टफोन होने पर भी वह अक्सर बच्चों के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होता। भविष्य में बनाई जाने वाली डिजिटल सामग्री और रिमोट लर्निंग की योजनाओं में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए.

असर रिपोर्ट के विषय में :

यह रिपोर्ट प्रथम संस्थान द्वारा जारी की जाती है। जिसका मुख्य विषय प्राथमिक शिक्षा की स्थिति रहती है.

प्रथम संस्थान के विषय में :

यह संस्थान भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाया गया एक अभिनव शिक्षण संगठन है.

मुंबई की मलिन बस्तियों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इसे 1995 में स्थापित किया गया था.

देश के सबसे बड़े गैर-सरकारी संगठनों में से एक के रूप में, प्रथम शिक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए उच्च-गुणवत्ता, कम लागत और अनुकरणीय हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करता है.

प्रथम के शिक्षण पर मानक (टीएआरएल) दृष्टिकोण ने बच्चों के सीखने के परिणामों पर प्रभाव को प्रदर्शित करता है जो नीति-निर्माण हेतु सहायक होती है.

■■■■

6 अंतरजातीय विवाह

- **चर्चा में क्यों**
- **पृष्ठभूमि**
- **अंतरजातीय विवाह का समर्थन करने वाले प्रावधान**
- **अंतरजातीय विवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व**
- **मनोनयन की प्रक्रिया**
- **भारत में मृत्युदण्ड**
- **विपक्ष में तर्क**
- **निष्कर्ष**

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु में अंतरजातीय विवाह के विरोध में 2003 में युगल की हत्या करने के जुर्म में अपराधियों को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गयी है.

पृष्ठभूमिः

भारत के कई क्षेत्रों(जैसे-हरियाणा,तमिलनाडु) में "ऑनर किलिंग" की घटनाएँ देखने को मिलती हैं.दलित वर्ग ऐसे अपराधों के विरुद्ध सुभेद्य होते हैं. यद्यपि एस.सी/एस.टी. एक्ट जैसे कठोर कानून मौजूद हैं फिर भी सामजिक प्रतिष्ठा के दबाव में ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता हैं. केवल तमिलनाडु में ही 2013 से 2019 के मध्य ऐसी 192 घटनाएँ दर्ज की गई. भारतीय समाज में जातियां, आर्थिक-सामजिक-राजनीतिक हैसियत निर्धारित करती हैं. जिसके कारण भारत में आज भी सामाजिक गतिशीलता काफी कम है. भारतीय संविधान में वर्णित बन्धुत्व की भावना को परम्परागत समाज में उस तरह की स्वीकार्यता नहीं मिल पायी है जैसी होनी चाहिए.परम्परागत समाज युवाओं विशेषकर महिलाओं में 'चयन की स्वतंत्रता' के अधिकार का सम्मान नहीं करता. आज भी भारतीय समाज में लड़कियों को पढ़ने, नौकरी करने, घर से बाहर भेजे जाने को लेकर नकारात्मकता विद्यमान है.समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति परिवार के मूल्यों को आत्मसात करता है. धीरे धीरे वो जिन मूल्यों / परम्पराओं के बीच रहता है वे उसके वक्तित्व के साथ सह-अस्तित्व बना लेती हैं. इसी कारण भारत में जाति व्यवस्था और मजबूती के साथ स्थायित्व बना रही है. अतः हम कह सकते हैं कि जाती व्यवस्था के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति सामाजिक, पारिवारिक स्वीकार्यता है.

अंतरजातीय विवाह का समर्थन करने वाले प्रावधान

1. संवैधानिक प्रावधान -

भारतीय संविधान समानता, स्वतंत्रता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा जैसे मूल्यों पर जोर देता है. संविधान राज्य (सरकार और संस्थाएं) और नागरिकों से इसी नैतिकता के अनुपालन की अपेक्षा करता है किन्तु परम्परागत समाज संवैधानिक नैतिकता को अपने जीवन में अंगीकृत नहीं कर पाया है.इसीलिए आज भी भारतीय समाज में जातिगत वैमनष्यता, लैंगिक भेदभाव, साम्प्रदायिकता देखने को मिलती है. जिसकी चरम परिणति अंतरजातीय विवाह/अंतरधार्मिक विवाह के नाम पर ऑनर किलिंग की घटनाओं में परिलक्षित होती है.

2. वैधानिक प्रावधान जैसे -एस.सी/एस.टी अधिनियम-

अनेक संवैधानिक/वैधानिक प्रयासों के बावजूद एस.सी./एस.टी. समुदाय इन अपराधों के प्रति सुभेद्य है. ऐसी परिस्थितियों में भारतीय संसद द्वारा 1989 में पारित किया गया एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत 22 कृत्यों को अपराध के रुप में सूचीबद्ध किया गया है. जो एस.सी./एस.टी. समुदाय के किसी व्यक्ति को अपमानित करता हो अथवा उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा सकता हो. किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग और किसी व्यक्ति के आर्थिक, लोकतांत्रिक एवं सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन करने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है. इसे संगीन अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है. और अपराधियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है. किन्तु अपराधियों में विशेष प्रकार का पूर्वाग्रह (जातिगत वैमनष्यता) व्याप्त होने के कारण एसे अपराधों की संख्या कम नहीं हो रही है.

यद्यपि अंतरजातीय विवाह करने वाले बालिग जोड़े को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने संबंधी प्रावधान किये गये हैं किन्तु इनका कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं हो सका है.

3. वैज्ञानिक आधार -

भारत में जीनोम फिंगर प्रिंट के जनक माने जाने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर लालजी सिंह के अनुसार एक ही जाति में विवाह करने से आनुवांशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसके लिए उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी जनजातियों का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि ये जनजातियाँ पूरी दुनिया से अलग-थलग रहकर एक सीमित क्षेत्र में रहीं. उनमें वैवाहिक संबंध भी आपस में ही बनें. इससे आनुवंशिक विकृतियाँ पैदा हुई और वे लगातार अनजानी बीमारियों से मर रहे हैं. आगे प्रो. सिंह ने कहा कि इसी कारण भारत में प्रारंभ से ही समगोत्र विवाह का विरोध

किया गया.

4. आधुनिक नैतिकता -

आधुनिक समाज की नैतिकता मानव केन्द्रित है. जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती है. वैवाहिक संबंधों के निर्माण में राज्य, समाज और परिवार की भूमिका और दबाव का विरोध करती है. मे. ट्रोपोलिटन शहरों में 'लिव-इन-रिलेशनशिप' की संस्कृति इसी आधुनिक नैतिकता की उपज है. हम कह सकते हैं कि आधुनिक समाज अंतरजातीय विवाह को नैतिक रूप से समर्थन देती है. साथ ही यह भी तर्क देती है कि विवाह दो व्यक्तियों का निजी मामला है और यह निर्णय उनकी स्वेच्छा पर निर्भर होना चाहिए.

अंतरजातीय विवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व

1. वैज्ञानिक चिंतन का अभाव

2. संवैधानिक नैतिकता को अंगीकृत न कर पाना

अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए किये जाने वाले प्रयास

बंद सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत शादी जैसे संस्कार जातियों में ही सम्पन्न होते हैं. यह व्यवस्था संविधान प्रदत्त 'चयन के अधिकार'

औरगरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का हनन करती है.

मनोनयन– जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करने के लिए, अंतरजातीय विवाह को सामाजिक स्वीक. ार्यता प्रदान करने के लिए समाज के द्वारा जाति प्रथा को मिल रही स्वीकृति को खत्म करना पड़ेगा इसके लिए मनोनयन द्वारा नकारात्मक

अभिवृति को शून्य और फिर शून्य अभिवृति को सकारात्मक अभिवश्ति में परिवर्तित करना होगा.

मनोनयन की प्रक्रिया -

1. **मनोनयन के लिए समाज को ऐसे रोल मॉडल के उदाहरण देने होंगे जिन्होंने 'अंतरजातीय विवाह' किया और समाज में विशिष्ट मुकाम अर्जित किया.**
2. **नागरिक समाज और एन.जी.ओ को बौद्धिक और भावनात्मक पहलुओं पर जोर देना चाहिए.**
3. **मीडिया, सेलिब्रेटी (क्रिकेटर, नेता और अभिनेता) को निरंतर इस दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए**
4. **आधुनिक चिंतन,तर्कवाद और मानवतावाद को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए**

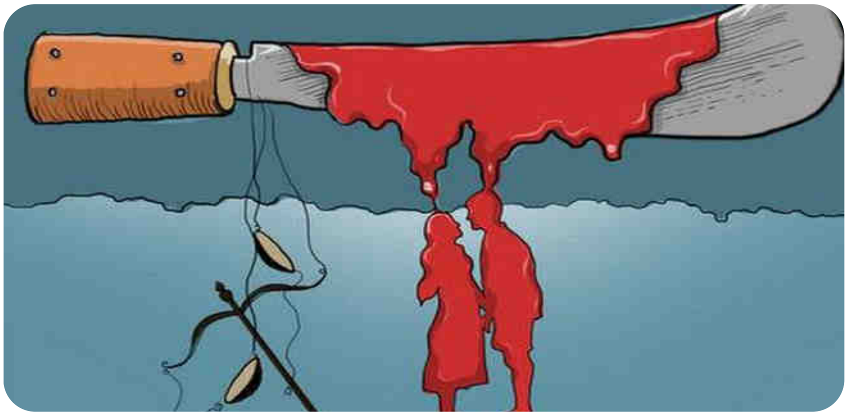

भारत में मृत्युदण्ड-

1. भारत में जघन्य अपराध के मामले में (रेयर एंड रेयरेस्ट मामले में) अपराधी को मृत्युदण्ड की सजा दिए जाने का प्रावधान है. इस विषय को लेकर विद्वान दो खेमों में बंटे नजर आते हैं. एक ओर जहाँ राष्ट्रवादी मृत्युदण्ड की वकालत करता है, वही मानवतावादी बुद्धजीवी वर्ग मृत्युदण्ड दिए जाने का विरोध करता है.
2. **मृत्युदण्ड के समर्थन में तर्क –** राज्य द्वारा विधि का शासन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के चलते अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करने के लिए.
3. संविधान ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को निरुद्ध करने का प्रावधान किया गया है. क्योंकि भारत में अलगाववाद, साम्प्रदायिकता और नक्सलवाद जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं.
4. विधि निर्माताओं पर पर दबाव होता है कि बनाये गये कानून समाज की सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते हो. दिल्ली में हुए निर्भया केस के बाद बलात्कार के मामले में मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान किया गया जिसके लिए जनता द्वारा मांग के गई थी.
5. भारत में मृत्युदण्ड की सजा पाने वाले अपराधी को सर्वोच्च न्यायालय में जाने और राष्ट्रपति के सम्मुख क्षमा याचना (अनुच्छेद-72) करने की सुविधा प्राप्त है.

विपक्ष में तर्क:

1. मृत्युदण्ड का प्रावधान संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमापूर्णजीवन जीने के अधिकार (अनुच्छेद-21) का उल्लंघन करता है.
2. ऐसा कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो प्रमाणित कर सके कि मृत्युदण्ड जैसी सजाओं से बलात्कार या घृणित अपराधों में कमी आई हो. विश्व के अधिकाँश देशों ने अपनी न्यायिक व्यवस्था से मृत्युदण्ड का प्रावधान हटा लिया है.
3. यदि मृत्युदण्ड के बाद मामले में ऐसा कोई नया तथ्य सामने आये जो अपराधी को निर्दोष साबित कर सकता हो या अपराध की भयावहता को कम करता हो.
4. कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता उसे अपराधी बनाने के लिए परिस्थियाँ जिम्मेदार होती है. जिनके लिए समाज भी उत्तरदायी है. ऐसे में मश्त्युदंड जैसी कठोर सजा सिर्फ अपराधी को ही क्यों मिले ?
5. सजा का उद्देश्य अपराधी से प्रतिशोध लेना नहीं बल्कि उसे सुधार करने हेतु अवसर देने से है. जबकि मृत्युदण्ड अपराधी को इस अवसर से वंचित करता है.

निष्कर्ष:– कानून का उद्देश्य अपराधी को सुधार का अवसर प्रदान करने के साथ ही लोक व्यवस्था को निर्बाध रूप से संचालित करना है. अर्थात अपराध के विरुद्ध न्यूनतम डिटरेंस उत्पन्न करने से है. इसलिए मृत्युदण्ड जैसे कानूनों का होना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के साथ ही लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक है. किन्तु इनका प्रयोग 'रेयर एंड रेयरेस्ट मामलों' में ही होना चाहिए. कोई भी कानून अपनी प्रकृति में उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना कि उसका क्रियान्वयन उसे साबित कर सकता है.

NOTES

7 ग्लोबल ग्रीन ग्रिड

- चर्चा में क्यों
- क्या है सौर ग्रीन ग्रिड
- प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के जरिए सधता भारतीय हित
- दक्षिण एशिया में रीजनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के मायन
- गीरन ग्रोथ इक्विटी कोष
- क्या है सौर ग्रीन ग्रिड
- प्रोजेक्ट का रोड मैप
- सौर ऊर्जा में भारत की राहें

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और ब्रिटेन के मध्य सौर ग्रीन ग्रिड पर जॉइंट डिक्लरेशन जारी करने पर बात हुई है. इसे ग्लोबल एनर्जी ग्रिड भी कहा जा रहा है. इस दिशा में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वन सन, वन वर्ल्ड,वन ग्रिड की धारणा का प्रतिपादन किया गया है. भारत इस वैश्विक ग्रिड को ठीक वैसे ही विकसित करना चाहता है जैसा कि उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लांच करने की दिशा में काम किया था.

क्या है सौर ग्रीन ग्रिड:-

ग्लोबल ग्रीन ग्रिड के तहत भारत सौर ऊर्जा के प्रयोग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक वैश्विक सौर ग्रिड निर्माण करना चाहता है. ताकि 2050 तक सभी महाद्वीपों से सम्बद्ध नवीकरणीय ऊर्जा का एक सिंगल पॉवर ग्रिड बन जाए जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में मदद मिल सके और जलवायु कि चुनौतियों से भी निपटा जा सके.

प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के जरिए सधता भारतीय हित:

गौरतलब है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत की कई अवसंरचनात्मक विकास और ऊर्जा परियोजनाएं चल रहीं हैं. ऐसे में जब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश चीन के अतिक्रमण राजनीति से परेशान है तो सौर ऊर्जा परियोजनाओं से आसियान देशों को जोड़ने का विचार भारत के लिए कई मायनों में सार्थक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है . इन स्थितियों में भारत अपनी प्रस्तावित ऊर्जा कूटनीति के जरिए आसियान के साथ अधिक मजबूत संबंधों के साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है.

इसी प्रकार भारत ने सौर ऊर्जा के मुद्दे पर अफ्रीकी देशों कोभी लामबंद करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. कई अफ्रीकी देश भारत के नेतत्त्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंसे के सदस्य हैं. वहीं दूसरी तरफ चीन ने अफ्रीकी देशों को अपने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के साथ जोड़ने में हाल के समय सक्रियता दिखाई है. ऐसे में इस ग्रिड के माध्यम से भारत अफ्रीकी देशों में अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को साध सकता है.

दक्षिण एशिया में रीजनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के मायने:

पड़ोसी देशों के साथ भी सीमापारीय ऊर्जा गलियारों के निर्माण पर भारत ने बल दिया है. बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, रामपाल पॉवर प्लांट , नेपाल और भारत के बीच मोतिहारी से अमलेखगंज तक सीमा पारीय तेल पाइपलाइन की शुरुआत इसी उद्देश्य से की गई है. भारत ने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के समान ही पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक रीजनल पॉवर ग्रिड पर भी योजना बनाई है और इसके जरिए भूटान , नेपाल , म्यांमार और बांग्लादेश के साथ श्रीलंका जैसे देशों को भी ऊर्जा आपूर्ति की जा सके. क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड भारत की विदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान पा चुका है. नवंबर 2014 में भारत ने सार्क देशों के साथ इस संदर्भ में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था और अगस्त, 2018 में बिम्सटेक देशों के साथ ऐसे ही इलेक्ट्रिक ग्रिड के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था. इसके अलावा अपनी सौर ऊर्जा कूटनीति को बढ़ाते हुए भारत सरकार ने अफ्रीका में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रियायती ब्याअज दरों पर दस अरब डॉलर की ऋण सुविधा का भी प्रावधान किया है. भारत का आयात निर्यात बैंक आईएसए के सदस्यी देशों के साथ मिलकर इस ऋण सुविधा को लागू कर रहा है. भारत ने 24 सितंबर 2019 को संयुक्तद राष्ट्रल महासभा के 74 वें सत्र के दौरान प्रशांत द्वीपीय क्षेत्र के विकासशील देशों को उनके यहां सौर ऊर्जा,नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु से संबधित परियोजनाओं के लिए 12 मिलियन अमरीकी डॉलर का अनुदान तथा रियायती दरों पर 150 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा की घोषणा की थी.

गीरन ग्रोथ इक्विटी कोष:

भारत और ब्रिटेन ने 120 मिलियन डॉलर कोष वाले ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड का भी निर्माण कर रखा है.जिसे अब बढ़ा कर 200 मिलियन डॉलर किया गया है. जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने वाले ग्रीन प्रोजेक्ट्स में अधिक से अधिक साझा निवेश करना है. लो कार्बन इकॉनोमी या ग्रीन अर्थव्यवस्था के विकास की दरुष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम है. सि. तंबर , 2021 ब्रिटेन ने भारत में ग्रीन प्रोजेक्ट्स में 1.2 बिलियन डॉलर के निवेश पर भारत के साथ सहमति बनाई है. 2022 से 2026 की अवधि के लिए भारत में यह निवेश किया जाएगा.

प्रोजेक्ट का रोड मैप:

भारत ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की संकल्पना को मजबूती देते हुए एक ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के निर्माण का प्रस्ताव किया है. इसके तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के 140 से अधिक देशों के मध्य सौर ऊर्जा संसाधनों के साझा करने के लिए वैश्विक सर्वसम्मति बनाने की योजना निर्मित की है. परियोजना के अगले चरण में इस ग्रिड को अफ्रीकी ऊर्जा केंद्रों से भी जोड़ने पर विचार किया गया है. भारत सरकार ने इस विषय पर सलाहकारी फर्मों के प्रस्तावों को हाल ही में आमंत्रित किया है ताकि एक दीर्घकालिक वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का रोडमैप समावेशी तरीके से तैयार किया जा सके. इस ऊर्जा परियोजना को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर शुरू कर

भारत वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में नेतश्त्वकारी भूमिका निभाने की मंशा रखता है. विश्लेषकयह भी मानते हैं कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचारभारत ने चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल के तर्ज पर कर चीन को इस महामारी के दौर में अपनी वैश्विक भूमिका की पहचान कराने के लिए की है. एक तरफ जहां चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल विश्व भर के देशों में अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं पर केंद्रित है वहीं भारत की यह योजना सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया भर के देशों के साथ सहयोग पर केंद्रित है.

सौर ऊर्जा में भारत की राहें :

भारत सरकार ने 2022 के आखिर तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संस्था4पित क्षमता का लक्ष्यी निर्धारित किया है. इसमें से 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से तथा 5 गीगावाट लघु पनबिजली से शामिल है. इस विजन को गति देने के लिए इस क्षेत्र में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल देना भारत की तार्किक सोच को दर्शाता है. ग्रिड कनेक्टेकड नवीकरणीय ऊर्जा के तहत पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान 27.07 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का क्षमता संवर्धन किया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा से 12.87 गीग. वाट, पवन ऊर्जा से 11.70 गीगावाट, लघु पनबि. जली से 0.59 गीगावाट तथा जैव ऊर्जा से 0.79 गीगावाट शामिल है. स्व च्छा ऊर्जा क्षेत्र की वश्द्धि दर से उत्साहित होकर भारत सरकार ने लक्षित राष्ट्री य निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) पर संयुक्तस राष्ट्र्जलवायु परिवर्तन संरचना सम्मेरलन को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में कहा है कि भारत प्रौद्योगिकी के अंतरण एवं हरित जलवायु निधि समेत निम्न् लागत अंतराष्ट्रीरय वित्तम की सहायता से 2030 तक गैर-फॉसिल ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40 प्रतिशत संचयी बिजली ऊर्जा क्षमता अर्जित करेगा.

■■■■

राष्ट्रीय

1 सब्ज बुर्ज

सन्दर्भ:

हाल ही में दिल्ली स्थित मुगलकालीन सब्ज बुर्ज के संरक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. इस कार्य को पूर्ण होने में लगभग 4 वर्ष का समय लगा.

सब्ज बुर्ज के विषय में:

- यह हुमायूँ के मकबरे (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन-यूनेस्को) की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल) में स्थिति एक ईमारत है.
- इसकी ऊंचाई लगभग 70 फीट है तथा इसका गुम्बद नीले रंग का है तथा यह अष्टकोणीय ईमारत है.
- इसमें "दोहरे गुम्बद" का प्रयोग हुआ है जिसे स्वर्ण रंगो से सजाया गया है. यह इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है.
- संरक्षणकर्ताओं का मानना है कि इसकी चित्र. कारी तात्कालिक मुगल चित्रकारी का अद्‌भुत नमूना है.
- इसका निर्माण 1530 में हुआ था. मुगल काल की इस ईमारत को 19वीं शताब्दी में निजामुद्दीन क्षेत्र के पुलिस थानों की तरह प्रयोग किया गया जाता था.
- इसके वास्तविक टाइल्स तथा प्रयक्त बहुमूल्य धातुओं को आक्रमणकारियों द्वारा निकाला भी गया है.

संरक्षण का कार्य:

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) द्वारा संरक्षित इस स्मारक के संरक्षण प्रयासों का श्रेय आगा खान सांस्कृतिक ट्रस्ट (एकेटीसी) तथा कारपोरेट कंपनी हावेल्स को जाता है.
- इसके संरक्षण का कार्य विश्व विरासत सप्ताह आरम्भ होने के पहले ही कर लिया गया है.

हुमायूँ का मकबरा:

- हुमायूँ का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है.
- गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकरी किले में हुआ करती थी तथा यह भूमि सुल्तान केकूबाद की राजधानी के रूप में प्रयुक्त हुई थी.
- 1562 में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में यह मकबरा हुमायूँ की विधवा बेगम हमीदा बानो की देख रेख में बना था.
- इस परिसर में सम्राट हुमायूँ का मकबरा सर्वाधिक प्रसिद्द मकबरा है इसके साथ ही यहां हमीदाबानों, दारा शिकोह, जहाँदार शाह इत्यादि के मकबरे भी स्थित हैं.
- यहाँ उद्यान हेतु चारबाग शैली का प्रयोग भी हुआ है.
- मकबरे का निर्माण मूलरूप से पत्थरों को गारे-चूने से जोड़कर किया गया है और उसे लाल बलुआ पत्थर से ढका गया है. इस ईमारत में फर्श की सतह, झरोखों की जालियों, द्वार-चौखटों और छज्जों के लिये श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया है.

भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग :

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है.
- यह भारत की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्व अनुसंधान तथा संरक्षण के उद्देश्य से निर्मित है.
- इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्व स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है.
- यह विभाग प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है. तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्व गतिविधियों को विनियमित करता है.
- यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 का विनियमन भी करता है.

2 चारधाम यात्रा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चारधाम सड़क की चौड़ाई को बढ़ाना राष्ट्र की सुरक्षा प्राथमिकता है. साथ ही सड़क परियोजना के निर्माण के क्रम मे पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए.

चार धाम:

यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे महान हिमालय की ऊंचाइयों के बीच चार ती. र्थ-स्थल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से चार धाम के नाम से जाना जाता है। ये तीर्थ केंद्र हर साल अधि कतम संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं, इस प्रकार यह पूरे उत्तरी भारत में धार्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है. परंपरागत रूप से, तीर्थयात्रा पश्चिम से शुरू होती है और पूर्व में समाप्त होती है। इस प्रकार, चारधाम यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री तक जाती है और अंत में केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाती है.

चारधाम परियोजना:

चारधाम परियोजना का उद्देश्य सभी मौसम में पहाड़ी राज्य के चार पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ना है. इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद हर मौसम में चार धाम की यात्रा की जा सकेगी. इस परियोजना के तहत 900 किलोमीटर लम्बी सड़क परियोजना का निर्माण हो रहा है परियोजना निर्माण की अवधि 4 वर्ष है. इसके निर्माण पर 1119.69 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत आएगी. टनल के निर्माण से चारधाम यात्रा के एक धाम यमुनोत्री तक जाने के लिए हर तरह के मौसम में संपर्क मार्ग उपलब्ध होगा. इससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. इससे धारसू से यमुनोत्री के बीच सड़क मार्ग की दूरी करीब 20 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय भी करीब एक घंटा कम हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन दिसम्बर 2016 में किया गया था.

3 रेजांग ला का वॉर मेमोरियल

सन्दर्भ :-

हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा 'रेजांग ला' युद्ध (वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान) की वर्षगांठ पर पुनर्निर्मित 'रेजांग ला वॉर मेमो. रियल' का उद्घाटन किया गया.

रेजांग-ला युद्धः

1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग-ला दर्रे में भारत तथा चीन के सैनिको के मध्य मुठभेड़ हुई थी.

यह स्थान लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस युद्ध में 114 भारतीय सैनिकों ने 2000 चीनी सैनिको की एक टुकड़ी के साथ युद्ध किया तथा उन्हें भारी क्षति पहुंचाकर कैलाश पर्वतमाला और आसपास के क्षेत्रों की रक्षा की थी. इस युद्ध में कुमाऊ-रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने भाग लिया था जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे. इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह समेत भारत के 98 सैनिक शहीद हुए थे। इसके लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र दिया गया था.

रेजांग ला की लड़ाई को लद्दाख में भारत-चीन के बीच हुए युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से माना जाता है.

भारत के रक्षा मंत्री ने इसे विश्व के महत्वपूर्ण युद्धों में एक बताया है.

रेजांग-ला की अवस्थिति

यह भारत के लद्दाख क्षेत्र में चुशूल घाटी के दक्षिणपूर्व में स्थित पहाड़ी दर्रा है.

यह 2.7 किमी लम्बा है तथा इसकी औसत ऊँचाई 16000 फीट है.

यह स्पैंगुर गैप (जिसका 1960 की सीमा वार्ता के दौरान चीन ने अपनी 'पारंपरिक प्रथागत सीमा' के रूप में दावा किया था) के दक्षिण में 11 मील की दूरी पर है.

इसकी ऊंचाई 5,500 मीटर (18,000 फीट) है.

रेजांग ला के उत्तर-पश्चिम में लगभग 2-3 किमी की दूरी पर रेचिन ला है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति है.

वॉर मेमोरियल के विषय में :

यह वॉर मेमोरियल लद्दाख के 'चुशुल' में स्थित यह स्मारक 15,000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर मौजूद है और भारत-चीन सीमा के बहुत ही करीब स्थित है.

इसे जनता हेतु खोल दिया गया है.

यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब कि भारत तथा चीन सीमा पर तनाव का माहौल है। यह प्रदर्शित करता है कि भारत अपनी सम्प्रभुता की रक्षा हेतु सजग है तथा किसी के दबाव से भयभीत नहीं है.

4 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने एमपीएलएडीएस योजना को आंशिक रूप से वापस लेने की घोषणा की है। सांसदों को अब वार्षिक स्वीकृत 5 करोड़ के जगह 2 करोड़ मिलेंगे।इस योजना को दो वित्तीय वर्षों (2020-21 और 2021-22) के लिए निर्लंबित कर दिया गया था. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया है.

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस):

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है. इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने के लिए सांसदों को सक्षम बनाना है.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी। इस योजना के तहत पहले संसद सदस्य की वार्षिक निधि पात्रता रु.5 करोड़ थी, जो एमपीएलएडीएस दिशानिर्देशों के अनुसार शर्तों की पूर्ति के अधीन, रु.2.5 करोड़ की दो किस्तों में जारी की जाती थी.

इस योजना की वापसी स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में भी मदद करेगी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय योजना केक.ार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण, निधि जारी करने और निगरानी तंत्र निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है. भारत सरकार राज्य नोडल विभाग को जिले को जारी एमपीएलएडीएस निधियों के बारे में सू.चित करता है. जिला प्राधिकरण एमपीएलएडीएस कार्यान्वयन की स्थिति की रिपोर्ट करते हैं. जल संसाधन मंत्रालय से विशिष्ट मंजूरी अनिवार्य रूप से पहले आवश्यक होगी. यदि एमपीएलएडीएस योजना के तहत सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए किसी भी कार्य को स्वीकृति दी गई है.

अंतरराष्ट्रीय

1 अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग : संरचना और कार्य

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर बिमल पटेल को संयुक्त राष्ट्र में कड़े मुकाबले में पांच साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किया गया है. उनका कार्यकाल एक जनवरी, 2023 से शुरू होगा. वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के 34 सदस्यों का कार्यकाल 2022 के अंत तक खत्म हो जाएगा.

प्रोफेसर बिमल पटेल को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 192 मौजूदा सदस्यों में से 163 वोट मिले और वह एशिया-प्रशांत समूह में शीर्ष पर रहे जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के उम्मीदवार भी थे. चीन को 142 वोट ही मिल पाए। हिंद-प्रशांत समूह में आठ सीटों के लिए 11 बेहद मजबूत उम्मीदवार थे.

अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1947 में किया गया था जिससे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए गए मैंडेट (अधिदेश) को पूरा करने में मदद मिल सके. दरअसल संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 13 (1) में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय विधियों के प्रगतिशील विकास को बढ़ावा देने और इसके संहिताकरण यानी **codification** के लिए अध्ययन कराएं जाएं और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सिफारिशें दीं जाएं. यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासभा को पेश करती है.

कोविड-19 महामारी के चलते 12 अगस्त 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह फैसला लिया था कि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के 72वें सत्र का सम्मेलन स्थगित किया जाए और उसके बाद 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लिए गए फैसले के तहत संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा स्थित ऑफिस में 26 अप्रैल से 4 जून और 5 जुलाई से 6 अगस्त 2021 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का 72 वां सत्र आयोजित किया गया था.

1 जनवरी , 2023 से अगले 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्यों का निर्वाचन 12 नवंबर , 2021 को इस आयोग के 76 वें सत्र के दौरान किया गया.

18 नवंबर 1981 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव संख्या 36 बाई 39 में यह निर्धारित किया था की इंटरनेशनल लॉ कमिशन के 34 सदस्यों को निम्नलिखित पैटर्न पर निर्वाचित किया जाएगा-

1. 8 नागरिक अफ्रीकी देशों से
2. 7 नागरिक एशिया प्रशांत राष्ट्रों से
3. 3 नागरिक पूर्वी यूरोपीय देशों से
4. 6 नागरिक लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों से
5. 8 नागरिक पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों से और
6. एक नागरिक अफ्रीकी राज्यों अथवा पूर्वी यूरोपीय देशों से चक्रीय क्रम में
7. 1 नागरिक एशिया प्रशांत देशों अथवा लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों से (चक्रीय क्रम में)

2 अरब लीग द्वारा खाड़ी देशों और लेबनॉन में मध्यस्थता कराने का प्रयास

अरब लीग पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है यह खाड़ी देशों खासकर सऊदी अरब और बहरीन के लेबनान के साथ कूटनीतिक संबंधों के संकट का समाधान कराने का प्रयास कर रहा है. लेबनॉन और खाड़ी देशों के बीच वर्तमान विवाद के तार यमन के हूती विद्रोहियों से जुड़ा हुआ है. यमन के हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए सऊदी अरब ने कुछ वर्षों पूर्व ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म चलाया था जिसमें सऊदी अरब के साथ दर्जन भर देश हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान करते नजर आये.

अब हाल ही में सऊदी अरब की यमन में इस भूमिका की आलोचना लेबनान के एक मंत्री ने कर दी जिसके बाद सऊदी अरब और लेबनॉन के कूटनीतिक संबंधों में अत्यधिक तनाव आ गया.

सऊदी अरब ने हाल ही में लेबनान के सूचना मंत्री जॉर्ज कोर्दही का एक विवादित वीडियो सामने आने के बाद बेरूत से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था और लेबनान के राजदूत को भी 48 घंटों के अंदर सऊदी अरब छोड़ने के लिए कहा था. इससे दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही सऊदी अरब ने लेबनान के साथ अपने आयात पर रोक लगा दी है. सऊदी अरब सरकार के इस फैसले के कुछ घंटों बाद बहरीन ने भी लेबनान के राजदूत को दो दिनों के अंदर अपने देश वापस लौटने का आदेश दिया था. बहरीन के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी थी. लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने सऊदी सरकार के कदम पर खेद जताते हुए सऊदी अरब से अपने फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया था.

इसके अलावा अरब लीग एक अन्य कारण से भी चर्चा में बना रहा. अरब लीग ने मोरक्को और अल्जीरिया के बीच बढ़ते कूटनीतिक विवादों और उसके कारण खत्म हुए कूटनीतिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए दोनों देशों से आग्रह किया और इसके लिए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का हवाला दिया. विवाद गहराते ही अल्जीरिया ने मोरक्को के उड्डयन के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था. जब अल्जीरिया ने मोरक्को के साथ रा. जनयिक संबंधों को खत्म करने का फैसला किया

तब मोरक्को किंगडम से "शत्रुतापूर्ण कार्यों" का हवाला देते हुए, मुख्य रूप से अल्जीरिया में काबिली क्षेत्र के आत्मनिर्णय के पक्ष में न्यूयॉर्क में मोरक्को के दूत द्वारा की गई टिप्पणियों का जिक्र किया था. अल्जीरिया पश्चिमी सहारा क्षेत्र में अलगाववादियों का समर्थन करता रहा है। यह मोरक्को के लिए विवाद का मुख्य कारण है। इस विवाद को सुलझाने के लिए अरब लीग ने राजनीतिक कूटनीतिक प्रयास तेज किये हैं.

अरब लीग की संरचना और प्रकार्य :

अरब लीग एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसमें उत्तरी अफ्रीका , उत्तर पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण-पश्चिम एशिया जिसे मध्य पूर्व भी कहते हैं, के देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। अरब लीग का गठन शीत युद्ध कालीन समय में हुआ था । इसका गठन 22 मार्च, 1945 को मिस्र की राजधानी काहिरा में छह देशों- मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया ने मिलकर की थी। ये छः देश इसके संस्थापक सदस्य देश हैं और अब वर्तमान में, अरब लीग में कुल 22 सदस्य हैं. इसका मुख्यालय काहिरा , मिस्र में है.

सीरिया भी अरब लीग का सदस्य रहा है लेकिन सीरिया में कई वर्षों से चल रहे गृह-युद्ध के दौ. रान सरकार द्वारा किये गए अत्याचार, दमन, युद्ध अपराध के परिणामस्वरूप, सीरिया को वर्ष 2011 में अरब लीग से निलम्बित कर दिया गया था.

अरब लीग के उद्देश्यों की बात करें तो यह सदस्य देशों के मध्य संबंधों को और अधिक घनिष्ठ बनाने तथा उनकी राजनीतिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने ; उनकी स्वतंत्रता एवं सम्प्रभुता की रक्षा करने तथा अरब देशों के हितों को प्रोत्साहन देने की दिशा में प्रमुखता से काम करता है. उल्लेखनीय है कि संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजरायल के साथ अपने सम्बंधों को पिछले वर्ष सामान्य करने के लिए 'अब्राहम एकॉर्ड' नामक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था जिसके विरोध में, फिलिस्तीन ने अरब लीग काउंसिल की अध्यक्षता छोड़ दी थी. अब्राहम एकॉर्ड इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में होने वाला पहला शांति समझौता है, इससे पूर्व वर्ष 1994 में इजराइल और जॉर्डन ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते की मध्यस्थता करने वाले यू.एस.ए. के अनुसार यह समझौता सम्पूर्ण अरब क्षेत्र में शांति स्थापना के लिये मील का पत्थर साबित होगा.

NOTES

3 रूस बना इंडियन ओशेन रिम एसोसिएशन का नया डायलॉग पार्टनर

इंडियन ओशेन रिम एसोसिएशन के कॉउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स की 21 वीं वार्षिक बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी जिसमें भारत ने भाग लिया. इसे ढाका में आयोजित किया गया था.

इस बैठक की खास बात यह रही कि रूस को **IORA** का नया डायलॉग पार्टनर (संवाद साझेदार) बनाया गया है। इस बैठक में प्रमुख रूप से आपदा जोखिम प्रबंधन , कोविड 19 से निपटने के उपायों और उससे जुड़े सहयोगों पर चर्चा की गई.

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को गठित करने का विचार सबसे पहले नेल्सन मंडेला ने 1995 में अपने नई दिल्ली भ्रमण के दौरान दिया था.

इसमें कुल 23 सदस्य देश हैं. फ्रांस इसका नवीनतम सदस्य देश है. इसमें वर्तमान में कुल 9 डायलॉग पार्टनर भी हैं जिनमें शामिल हैं : चीन, अमेरिका, जापान, यूके, मिस्र, टर्की, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और अब रूस. **IORA** संयुक्त राष्ट्र महासभा, अफ्रीकन यूनियन , और अंकटाड का पर्यवेक्षक सदस्य भी है.

कॉउन्सिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स **IORA** का शीर्षस्थ निकाय है जिसकी बैठक का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है. 2019 से 2021 के लिए इसका अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात और 2021 से 2023 के लिए बांग्लादेश है.

गौरतलब है कि लगभग 2.7 बिलियन लोग हिंद महासागर की सीमा वाले देशों में रहते हैं. दुनिया के कंटेनर जहाजों का आधा हिस्सा, विश्व के थोक माल यातायात का एक-तिहाई और विश्व तेल यातायात का दो-तिहाई हिस्सा हिंद महासागर में समुद्री व्यापार मार्गों से होकर जाता है. भारत इस क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिये **IORA** के सदस्य देशों सहित सोमालिया, ओमान और अन्य वाणिज्यिक मत्स्य क्षेत्र में अपने कौशल को साझा कर रहा है.

भारत मालदीव, श्रीलंका, सेशेल्स और बांग्लादेश आदि देशों के साथ मजबूत समुद्री संबंधों को बढ़ावा देकर अपने सूचना तंत्र को विकसित कर रहा है. **IORA** भारत के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है यही वजह है कि न केवल तटीय देशों बल्कि इस क्षेत्र में अन्य देशों के साथ भी भारत अपने संबंधों को मजबूत करने के लिये प्रयासरत है.

भारत आईओआरए के संस्थापक सदस्यों में से एक है। आईओआरए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और स्थिर क्षेत्र की स्थापना के लिए संवाद आधारित दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने के लिए प्राथ. मिक मंचों में से एक है जो सभी को साझा समृद्धि प्रदान करता है.

यह भिन्ना-भिन्न आकार, आर्थिक मजबूती तथा भाषा एवं संस्कृति में व्यापक विविधता वाले तीन महाद्वीपों के देशों को एक मंच पर लाता है. इसका उद्देश्य हिंद महासागर के परिधि क्षेत्र में, जहाँ तक. रीबन दो बिलियन आबादी पाई जाती है, व्यापार, सामाजिक– आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक मंच का सृजन करना है. हिंद महासागर का परिधि क्षेत्र सामरिक एवं बहुमूल्य खनिजों, धातुओं एवं अन्यि प्राकृतिक संसाधनों, समुद्री संसाधनों एवं ऊर्जा की दृष्टि से समृद्ध है तथा इन सबको अनन्यं आर्थिक क्षेत्रों (ई.ई.जेड),महाद्वीपीय शेल्फ एवं गहन सीबेड से प्राप्त किया जा सकता है.

4 आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन दिल्ली में संपन्न

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन 24 नवंबर, 2021 को वर्चुली रूप से दिल्ली में किया . इस वर्ष आयोजन की थीम " टेक्नोलॉजी फाइनेंस एंड कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग रेसिलिएंस टू डिजास्टरस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19" थी.

सम्मेलन का सार :

- सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के बीच अंतर किए बिना भारत के भागीदारों की देखभाल की हैं.
- उन्होंने सागर (SAGAR – Security and Growth for All in the Region) अवधारणा के जरिए हिंद महासागर में भारत के दृष्टिकोण को बताया.
- 'सागर' भारत का एक विशिष्ट और अंतर-सं. बंधित कार्यक्रम है. जिसमें निम्न तत्व शामिल हैं

1. तटीय राज्यों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना.
2. भूमि और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए क्षमता बढ़ाना.
3. सतत क्षेत्रीय विकास और नीली अर्थव्यवस्था की दिशा में कार्य करना.
4. समुद्री डकैती, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं जैसे गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना.

हिन्द महासागर में भारत की भूमिका :

भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में आपदा राहत मिशनों में प्रमुख भूमिका निभाई है. भारत ने 2015 में "ऑपरेशन राहत" के जरिए यमन को मदद दी थी. इस ऑपरेशन के तहत भारत ने यमन में बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकालना था. इसी मिशन में 40 अन्य देशों के लगभग 2000 से अधिक नागरिकों को बचाया गया था. इसके अतिरिक्त भारत ने श्रीलंका में 2016, इंडोनेशिया में 2019 और मेडागास्कर में 2020 के विभिन्न आपदा में सहायता पहुंचाई थी.

पर्यावरण

1 भारत के पहले 'घास संरक्षण क्षेत्र' का उद्घाटन :

घासों की पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका हाती है. अफ्रीका की सवाना घासभूमियाँ हों या भारत की पश्चिमी घाट की शोला घासभूमियाँ या फिर तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी की समुद्री घासें सबका ही पारितंत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है. घासों और घासभूमियों के इसी महत्व को संज्ञान में लेते हुए अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में हाल ही में दो एकड़ में फैले भारत के पहले 'घास संरक्षण क्षेत्र' का उद्घाटन किया गया. उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान) द्वारा इस संबंध में घोषणा की गई थी और कहा गया था कि उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान इकाई ने केंद्र सरकार के क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण से तीन साल में संरक्षित क्षेत्र विकसित किया है. इस संरक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, पारिस्थितिक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व की लगभग 90 प्रजातियों की घास उगाई गई हैं. इस परियोजना का उद्देश्य घास की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण है. कई नवीनतम शोध में यह साबित हुआ है कि घास के मैदान वन भूमि की तुलना में 'कार्बन सोखने' में अधिक प्रभावी हैं.

घासों का भारत में बहुआयामी महत्व है. घासों को सुगंध, औषधीय, चारा, सजावटी, कृषि और धार्मिक उपयोगों के लिए जाना जाता है लेकिन आज जिस तरह से घास के मैदान विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना कर रहे हैं और उनका क्षेत्र सिकुड़ रहा है, जिससे कीड़ों, पक्षियों और उन पर निर्भर स्तनधारी जीवों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है.

इसी साल उत्तराखंड में वन मुख्यालय ने सभी वन संरक्षकों को एक खास निर्देश भी जारी किया था. इसके तहत पर्यावरण के लिए खतरनाक मानी जाने वाली झाड़ी प्रजाति लैंटाना (कुर्री) की फांस से उत्तराखंड के जंगल मुक्त होंगे। इसके लिए सभी संरक्षित, आरक्षित, सिविल सोयम और पंचायती वनों में लैंटाना उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा. वन क्षेत्रों से लैंटाना हटाकर इसकी जगह घास का रोपण किया जाएगा. दरअसल, लैंटाना ऐसी झाड़ी प्रजाति है, जो अपने इर्द-गिर्द दूसरी वनस्पतियों को नहीं पनपने देती. साथ ही वर्षभर खिलने के गुण के कारण इसका निरंतर फैलाव हो रहा है. उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा, जहां लैंटाना ने दस्तक न दी हो। इसलिए इस बार करीब 12 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैली लैंटाना घास को हटाकर इसकी जगह घास के मैदान तैयार करने के साथ ही वहां बांस समेत अन्य वृक्ष प्रजा. तियों का रोपण किये जाने का भी निर्णय हुआ है। मिशन मोड में चलने वाले इस अभियान में प्रतिपू. रक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैंपा) से 37 करोड़ की राशि उपलब्ध हुई है.

कैम्पा एक तरह का पर्यावरणीय कोष है जिसकी स्थापना 2006 में क्षतिपूरक वनीकरण के प्रबंधन के लिए की गई थी. इसे क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण स्कीम के नाम से जानते हैं. वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि वनीकरण के लिए राज्यों को दिए गये कोष का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि इन कोषों को केन्द्रीय स्तर पर समेकित करके एक क्षतिपूरक वनीकरण कोष बनाया जाए. इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था –क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण अधिनियम. इस अधिनियम का मुख्य ध्येय वन क्षेत्रों में होने वाली कमी के बदले प्राप्त राशि का प्रयोग और उसका वनीकरण में फिर से निवेश करना है.

2 अरुणाचल प्रदेश में राज्य तितली और पर्यावरण मंत्रालय को लेकर बड़ा निर्णय :

13 नवंबर, 2021 को अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के व्यापक जलवायु अनुकूल और समावेशी विकास में तेजी लाने के लिए और जलवायु अनुकूल विकास के उद्देश्य से टाइगर डिक्लेरेशन 2047 ऑन क्लाइमेट चेंज रिजिलियेन्ट एंड रेस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश को अपनाया है. एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यावरण और वन विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया है.

मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक पहली बार राज्य की राजधानी से बाहर 'पक्के टाइगर रिजर्व क्षेत्र' में आयोजित की गई. पक्के उद्घोषणा में अरुणाचल प्रदेश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने, वनों के संरक्षण को प्राथ. मिकता देने, सभी का स्वास्थ्य और कल्याण, आजीविका और अवसर सुनिश्चित करने की बात की गई है.

इसके तहत सरकार का उद्देश्य आर्थिक और पारि. स्थितिक दोनों खतरों से निपटने के लिये 'जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों और जैव विविधता पर इसके प्रभाव से लोगों की रक्षा' करने का हर संभव प्रयास करना है.

गौरतलब है कि कैबिनेट द्वारा इस अवसर पर तितली की दुर्लभ प्रजाति 'कैसर-ए-हिंद' को राज्य तितली के रूप में अपनाने को मंजूरी प्रदान की गई. इस तितली का वैज्ञानिक नाम टीनोपालपस इम्पीरियलिस है. यह चौड़ी पत्ती वाले समशीतोष्ण सदाबहार वनों में ऊँचाई पर पाई जाती है। समशीतोष्ण सदाबहार वन पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं.

90-120 मिलीमीटर के पंखों वाली यह तितली पूर्वी हिमालय के साथ (पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर) में भी पाई जाती है। यह तितली नेपाल, भूटान, म्याँमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन में भी पाई जाती है.

भारत में तितली प्रजाति की स्थिति :

भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार भारत में तितलियों की 1,318 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईसीयूएन)

के अनुसार भारत में तितलियों की 35 प्रजातियाँ अपने अस्तित्व के लिहाज से गंभीर रूप से संक. टग्रस्त हैं। आईसीयूएन ने भारत की तितलियों की 43 प्रजातियों को संकटग्रस्त और तीन तितली प्रज. ातियों को न्यूनतम रूप से विचारणीय संकटग्रस्त श्रेणियों में रखा है.

अगर तितलियां पृथ्वी से खत्म हो जाएं तो सेब से लेकर कॉफी तक कई खाद्य फसलों के स्वाद से हम वंचित हो जाएंगे. तितलियाँ जब फूलों का रस पीकर परागण करती हैं तो फूलों का रूपांतरण फल में संभव हो पाता है. संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया की 75 फीसदी खेती परागण पर निर्भर करती है. पर्यावरणविदों का मानना है कि तितलियों के खत्म होने का असर दूसरे जीवों पर भी पड़ सकता है क्योंकि उनके अंडे से बने लार्वा और प्यूपा कई दूसरे जीवों का भोजन होते हैं.

भारत में तितलियों की सुरक्षा के लिए उपाय : वर्ष 2020 में उपराष्ट्रपति ने पोर्ट ब्लेयर में हड्डो स्थित नेचर पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया था. उन्होंने तितलियां छोड़ी और पार्क में तितली कंजर्वेटरी का भ्रमण किया था अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में तितलियों की लगभग 300 प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से 207 इस क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं। जल निकायों को इंटर-कनेक्टिंग चौनलों के साथ इस कंजर्वेटरी से जोड़ा गया है, ताकि तितलियों को पनपने के लिए आवश्यक नमी और हवादार सूक्ष्म जलवायु उपलब्धक कराई जा सके.
तितलियों की संख्या में सुधार के लिए राज्य सरक. ारों को तितली पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद मध्यप्रदेश के इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में ऐसे पार्क बनाये गए हैं. भोपाल स्थित तितली पार्क में पहले ही साल तकरीबन तीन दर्जन तितलियों की प्रजातियाँ देखी गई हैं। इनमें कॉमन जेजवेल, ग्राम ब्लू, कॉमन बेंडेड ऑल, कॉमन इवनिंग ब्राउन, ब्लू टाइगर, प्लेन टाइगर, स्ट्रिप्ड टाइगर, कॉमन इंडियन क्रो और कॉमन ग्रास येलो जैसी प्रजातियाँ शामिल हैं। गौरतलब है कि देश की पहली राज्य तितली की घोषणा महाराष्ट्र में की गई थी. वहां सहयाद्रि की पहाड़ियों में मिलने वाली ब्लू मॉरमॉन प्रजाति की तितली को राजकीय तितली घोषित किया जा चुका है. मखमली कालेरंग की ब्लू मॉरमॉन तितली बर्डविंग के बाद आकार में सबसे बड़ी तितली है. देश में पाई जाने वाली कुल तितलियों में से 15 फीसदी तितलियां महाराष्ट्र में पाई जाती हैं. श्रीलंका के अलावा इस प्रजाति की तितली महाराष्ट्र के पश्चिम घाट, दक्षिण भारत व पूर्वी समुद्री किनारे वाले इलाके में पाई जाती है. इसके साथ ही बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में देश का पहला बटरफ्लाई पार्क भी खोला जा चुका है।

हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिमी पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई, जबकि 106 मिमी पंखों वाले नर गोल्डन बर्डविंग तितली शिलांग के वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है.

3 इथेनॉलः जीवाश्म ईंधनों का विकल्प

चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत सरकार ने 2025 तक गैसोलीन के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इथेनॉल मिश्रण करने से 2023 से चीनी में दी जाने वाली सब्सिडी में कमी करने में मदद मिलेगी.

इथेनॉल-
इथेनॉल एक जैव ईधन है जिसका उत्पादन गेंहूं, आलू, गन्ना आदि कृषि उत्पादों से होता है. भारत में इथेनॉल का उत्पादन गन्ने के शीरे के किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के रूप में भी किया जाता है.

सरकार द्वारा उठाये गये कदः
परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ उपाय किये गये है, जो निम्नलिखित है-

1. इथेनॉल ब्लेडिंग प्रोग्राम- हाल ही में भारत सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए एक रोडमैप जारी किया है। जिसमें इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को परिवर्तित करके (2030 के लक्ष्य को)2025 तक पूरा करने को कहा गया है. जिसके तहत पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल का मिश्रण किया जाना है. वर्तमान में यह मिश्रण 8.5% है.

2. हाइड्रोजन ईंधन- हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया है. इस मिशन के तहत हरित ऊर्जा संशोधनों से हाइड्रोजन उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। इस मिशन में भारत की बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था से जोड़ना भी शामिल है.

3- इलेक्ट्रिक वाहन नीति- भारत सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 का लक्ष्य 2024 तक कुल वाहनों में 25% इलेक्ट्रिक वाहन तथा बसों में 50% इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करना है। इलेक्ट्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य वायु प्रदूषण को कम करना हैक्योंकि बढ़ते वायु प्रदूषण ने दिल्ली जैसे शहरों में स्वास्थ्य चिंताओं को बढ़ा दिया है.

भारत को अन्य देशों से सीखने की जरूरत-
भारत में इथेनॉल मिश्रण का स्तर अन्य देशों की तुलना में कम है. आज दुनिया के अधिकांश देश जीवाश्म ईधन के प्रयोग को कम करने के लिए इथेनॉल मिश्रण के अनुपात को बढ़ा रहे हैं. उदा. हरण के लिए ब्राजील पेट्रोल में इथेनॉल 48% तक मिश्रित कर रहा है. इथेनॉल के मिश्रण से वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा.

इथेनॉल सम्मिश्रण के संभावित लाभः-
- फसल जलाने में कमी लाने और कृषि संबंधी अवशिष्ट को जैव ईधन में बदलकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी.
- फसलों के लिए वैकल्पिक बाजार उपलब्ध होगा जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकेगी.
- जीवाश्म ईधन के आयातनिर्भरता में कमी आयेगी.

बैटरी चालित वाहन और इथेनॉल ईधन से चलने वाले वाहनों में तुलनाः-
- इथेनॉल ईधन से चलने वाले वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में ज्यादा दक्ष किफायती व सुविधाजनक होते हैं.
- बैटरी चलित वाहनों में बैटरी को बिजली से

चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए ऊर्जा सामान्यतया कोयले से प्राप्त होती है अतः यह अप्रत्यक्ष रूप से अनवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देता है. जबकि इथेनॉल ईधन से चलने वाले वाहनों में अधिकांश में स्वच्छ ऊर्जा की खपत होती है.

- बैटरी चलित वाहन कम सुविधाजनक होते है क्योंकि चार्जिंग स्टेशन के लिए आधारभूत संरचना की समस्या विद्यमान है तथा यह ज्यादा दूरी की यात्रा के लिए दक्ष नहीं होते है। जबकि इथेनॉल ईधन में यह समस्या नहीं है.
- बैटरी वाहनों में बैटरी की जीवन अवधि 8 से 10 वर्ष की होती है जिससे लागत में बढ़ोतरी होती है.

नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त ऊर्जा से संबंधित सीमाएं-

- अभी भी नवीकरणीय स्रोत सेपर्याप्त मात्र में उत्पादन क्षमता प्राप्त नहीं हुई है.
- नवीकरणीय ऊर्जा सामान्यतया अविश्वसनीय होती है क्योंकि यह प्राकृतिक घटनाओं से अधिक प्रभावित होती है जैसे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा आदि.
- नवीकरणीय ऊर्जा में लागत खर्च ज्यादा है. इसके साथ ही रखरखाव का खर्च कुल खर्च को बढ़ा देता है.
- नवीकरणीय ऊर्जा के कारण परम्परागत इंजनों में भी बदलाव की आवश्यकता होगी जो वाहन के उत्पादन के खर्च को बढ़ा सकता है.

आगे की राह-

भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य पर्यावरण देना हमारा कर्तव्य है जिनके लिए आवश्यक है जीवाश्म ईंधनों के विकल्प की ओर अग्रसर होना. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग प्रदान कर सकता है. इसके लिए आवश्यकता है एक एकीकृत दृष्टिकोण और सुसंगत नीति की. सरकार को जीवाश्म ईंधन से अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा प्रणालियोंकी निभ्रता दूर करके टिकाऊ और लचीले भविष्य का निर्माण करना चाहिए.

विज्ञान एवं तकनीक

1 नोरोवायरस : केरल में वायनाड जिले में मिलने की हुई पुष्टि

चर्चा में क्यों?

केरल के वायनाड में नोरोवायरस नाम की एक और बीमारी के मामले की पुष्टि हुई है. दो सप्ताह पहले वायनाड जिले के विथिरी के पास पुकोडे में एक पशु चिकित्सा कॉलेज के 13 छात्रों में नोरोवायरस संक्रमण की जानकारी सामने आई थी. इसके मद्देनजर केरल सरकार ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है और साथ ही इस संबंध में कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए हैं.

संक्रामक है नोरोवायरस:

नोरोवायरस एक संक्रामक संक्रमण है. इसे पहले नोरवॉक वायरस के नाम से जाना जाता था. इसका एक अन्य नाम विंटर वॉमिटिंग डीजीज भी है. इस वायरस की उत्पति अमेरिका से हुई है. अमेरिका में इस वायरस से संक्रमण के मामले काफी अधिक आते हैं, लेकिन इसे जानलेवा नहीं माना जाता है.

नोरोवायरस के लक्षण :

इसी साल जुलाई में इंग्लैंड में इसके 154 नए मामले दर्ज किए गए थे. अचानक उल्टी और दस्त होना इस वायरस के संक्रमण के लक्षण हैं, इसके साथ-साथ तेज बुखार, बदन दर्द भी होता है. ये लक्षण संक्रमण के करीब एक से दो दिन के बाद नजर आते हैं. ये एक जूनोटिक बीमारी है यानी पशुओं के जरिए इंसानों में फैलता है. इसका प्रसार काफी तेजी से होता है. यह वायरस दूषित खाने और पानी से और संक्रमित व्यक्ति से फैलता है. एक पीड़ित व्यक्ति नोरो वायरस के करोड़ों कण फैला सकता है और संक्रमित होने के लिए इसके कुछ कण ही काफी हैं. हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि नोरोवायरस स्वस्थ लोगों को बहुत प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यह छोटे बच्चों, बुजुर्गों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी झेल रहे लोगों के लिए गंभीर हो सकता है.

केरल सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास:

केरल में अधिकारियों ने कहा है पानी को साफ करने के लिए 'सुपर क्लोरीनीकरण' किया जा रहा है. इसके अलावा, नोरोवायरस से संक्रमित लोगों को घर पर आराम करने की सलाह दी गई है. डाक्टरों की राय है कि ऐसे लोगों को ओआरएस और उबला हुआ पानी पीना चाहिए. लोगों को खाना खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। कपड़े और शौचालयों को साफ रखा जाना चाहिए और पानी में ब्लीच डालकर घर की जगहों की सफाई करनी चाहिए. ये वायरस कोरोना वायरस की तरह एल्कोहल से खत्म नहीं होता, बल्कि कपड़ों को 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर साफ किया जाए तो इससे फायदा होता है.

NOTES

2 “मेन-सीक्वेंस रेडियो पल्स एमिटर”

एनसीआरए ने आठ नए “मेन-सीक्वेंस रेडियो पल्स एमिटर” की खोज की है:

पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजि. क्स(एनसीआरए) के खगोलविदों ने आठ ऐसे सितारों की खोज की है जो एक दुर्लभ श्रेणी के हैं. जिन्हें मेन-सीक्वेंस रेडियो पल्स एमिटर (एमआरपी)कहा जाता है. इन एमआरपी की खोज ‘जाइंट मीटर-वेव रेडियो टेलीस्कोप (जीएमआ. रटी)’के द्वारा की गयी है. ये दुर्लभ श्रेणी के रेडियो सितारे सूर्य से भी अधिक गर्म होते हैं.इनके पास असामान्य रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं. जिसके कारण ये तारे चमकीले रेडियो स्पंदनों का उत्सर्जन करते हैं. इससे पूर्व भी जीएमआ. रटीका उपयोग करते हुए इसी तरह के तीन और एमआरपी सितारों की खोज की जा चुकी है.

कब हुई थी पहली MRP की खोज:

वर्ष 2000 में जीएमआरटी की उच्च संवेदनशीलता के कारण पहले एमआरपी सितारे को खोजा गया था.

जाने जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (जीएमआरटी) को:

पूर्णत: स्वदेश निर्मित जीएमआरटी पुणे के पास स्थित है. यह 45 मीटर व्यास के परवलयाकार रेडियो दूरबीन कि एक श्रृंखला है, जो मीटर तरंगदैर्घ्य का अवलोकन करती है.जी.एम.आर. टी. एक बहुमुखी उपकरण है जो सौरमंडल से लेकर अवलोकनीय ब्रह्मांड तक की विभिन्न रेडियो एस्ट्रोफिजिकल समस्याओं की जाँच करने में सक्षम है. इसका संचालन नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्सद्वारा किया जाता है. इसका निर्माण 1984 से 1996 के दौरान किया गया था. हाल में अपग्रेड किये गए रिसीवरों के कारण अब इसे अपग्रेडेड जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (यूजीएमआरटी) के रूप में जाना जाता है.

नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (एनसीआरए):

एनसीआरएएक शोध संस्थान है, जो रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है. यह पुणे विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है.एनसीआरएका खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के कई क्षेत्रों जैसे सूर्य, पल्सर, इंटरप्लेनेटरी स्किंटिलेशन, सक्रिय आकाशगंगा, इंटरस्टेलर माध्यम आदि के अध्ययन में सक्रिय अनुसंधान कार्यक्रम हैं.

आर्थिक

1 न्यूनतम समर्थन मूल्य

सन्दर्भ :-

प्रधानमंत्री द्वारा कृषि बिलों को वापस लिए जाने की घोषणा के उपरान्त भी कृषक संघो ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को नियमित तथा स्थायी किये जाने तक विरोध को जारी रखने की बात की है.

क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी):

- न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि बाजारों में हस्तक्षेप का एक माध्यम है जो कृषि बाजारों में आए हुए उतार चढ़ाव से किसानों का संरक्षण करता है.
- न्यूनतम समर्थन मूल्य को हरित क्रांति के दौरान 1966-67 में गेहूं के लिए आरंभ किया गया था.

न्यूनतम समर्थन मूल्य के उद्देश्य:

न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिद्धांत निम्न उद्देश्य से प्रेरित है:-

- किसान कृषि के क्षेत्र में निवेश को बढ़ा सकें.
- किसान उत्पादन को बढ़ाएं जिससे खाद्य सुरक्षा तथा कृषक आय सुनिश्चित हो सके.
- कृषक के पास उन्नत कृषि तकनीकों को स्वी. कारने की प्रेरणा तथा निवेश दोनों ही उपलब्ध हो.

कौन करता है एमएसपी का निर्धारण:

कृषि लागत तथा मूल्य आयोग के सिफारिशों के आधार पर फसलों की बुवाई के समय ही समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है. इससे किसानों की बारगेनिंग पावर में वृद्धि होती है. वर्तमान समय में यह 23 वस्तुओं पर जारी किया जाता है जिसमें सात अनाज (धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मकई, ज्वार तथा रागी) पांच दलहन (चना ,अरहर, मूंग उड़द तथा मसूर) तथा 8 तिलहन (मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुमद, नाइजर)इसके साथ नारियल कच्चा कपास कच्चा जूट तथा तंबाकू सम्मिलित है।

नोट- गन्ने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता। गन्ने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का निर्धारण करती है.

एमएसपी से लाभ:

- भारी उत्पादन की स्थिति में बाजार के नियमों के आधार पर अनाजों के मूल्य में गिरावट होनी चाहिए परंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार की अनिश्चितता से कृषकों की रक्षा करता है।
- एमएसपी में सम्मिलित फसलों में मुख्य रूप से अनाज तथा दलहन सम्मिलित हैं जो खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इससे किसानों को निवेश, वित्त की पहुंच तथा उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रेरणा प्राप्त होती है।
- कृषि में निरंतर घटते लाभ को ध्यान में रखते

हुए कृषको के लिए एमएसपी एक आशा की किरण है.

न्यूनतम समर्थन मूल्य से समस्याएं

- न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ ही फसलों को सम्मिलित किया गया है अत: एक निश्चित लाभ की आशा में कृषक मात्र उन्हीं फसलों को उत्पा. दित करता है जिससे फसल चक्र प्रभावित होता है तथा अन्य फसलों का उत्पादन रुक जाता है.
- एमएसपी का मुख्य लाभ हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में ही हुआ है तथा इन क्षेत्रों के किसानों ने अपनी जलवायु को ध्यान में न रख कर एमएसपी में सम्मिलित अनाजों का उत्पादन किया जिससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है. उदाहरण के लिए पंजाब में चावल के उत्पादन हेतु भूमिगत जल का दोहन.
- सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार, कठिन नियम, तथा किसानों में जागरूकता के अभाव के फल स्वरुप एमएसपी का लाभ मिडिलमैन को प्राप्त होता है जो किसानों से कम दाम में फसल ले लेते हैं तथा सरकार को एमएसपी के दाम पर विक्रय कर देते हैं.

कृषि में सुधार हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को युक्तिसंगत बनाना अनिवार्य है जिससे अधिकतम लाभ किसानों को प्राप्त हो तथा राजकोष पर कम से कम भार पड़े.

2 क्रिप्टो करेंसी का नियमन : आवश्यकता तथा सम्भावना

सन्दर्भ-

हाल ही में आयोजित सिडनी डायलॉग में हुए अपने वर्चुअल सम्बोधन में भारतीय प्रधानमंत्री द्व ारा क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक सहयोग की बात की गई.

क्या है क्रिप्टो करेंसी ?

क्रिप्टो करेंसी की वैश्विक स्तर पर स्पष्ट परिभ. षा नहीं है. वास्तव में क्रिप्टो करेंसी का आरम्भ बिटकॉइन नामक एक क्रिप्टोकरेंसी के उद्भव से हुआ जिसका जिसका संस्थापक सतोशी नाकामोतो को माना जाता है. यह करेंसी ब्लॉक चेन नामक तकनीकी पर आधारित है. यह क्रिप्टो करेंसी पूर्ण रूप से नियमन से परे है क्योंकि ब्लॉक चेन तकनीकी किसी भी ट्रांजैक्शन में तृतीय पक्ष का उन्मूलन करता है. ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित बिटकॉइन पूर्ण रूप से एक इलेक्ट्रॉ. निक ट्रांजैक्शन सिस्टम है जो अंतर्वैयक्तिक तथा विकेंद्रीकृत है. वर्तमान में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी प्रचलित हैं. बिटकॉइन के अतिरिक्त पिछले दिनों सोशल मीडिया कंप. नी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा, एथरियम, आदि क्रिप्टोकरेंसी के कुछ उदाहरण हैं.

क्रिप्टो करेंसी के लाभ:

- क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा लाभ इसकी गोपनीयता है. किसी भी तीसरे पक्ष की अनुपस्थि. ति में लोगों की निजी जानकारी सुरक्षित रहती है जो डेटा संरक्षण हेतु आवश्यक है.
- इसके अतिरिक्त क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन में किसी भी बैंक अथवा अन्य बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होती, जो ट्रांजैक्शन की क्षमता को बढ़ाता है तथा बहुत ही कम खर्च में लेनदेन को सक्षम करता है.
- क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विदेशी ट्रांजैक्शन भी संभव है.

क्रिप्टो करेंसी से जुडी चिंताएं:

एक उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सिस्टम होने के उपरांत भी क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग के साथ कई प्रकार की चिंताएं जुड़ी हुई हैं, जो इसे नियमन के अधीन लाए जाने की मांग करती हैं.

- विकेंद्रीकृत व्यवस्था होने के कारण क्रिप्टो करेंसी का नियमन नहीं हो सकता है.
- जिस प्रकार रुपए की गारंटी भारत में रिजर्व बैंक के द्वारा ली जाती है उस प्रकार क्रिप्टो करेंसी की कोई गारंटी नहीं होती है.
- क्रिप्टो करेंसी बहुत ही उच्च तकनीकी की मांग करती है जबकि भारत सहित संपूर्ण विश्व में इतनी उन्नत तकनीकी को प्रयोग करने वालों की संख्या नगण्य है.
- क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के उपरांत किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी फ्रॉड के लिए निवेशक अत्यंत सुभेद्य हो जाता है.
- यदि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन का प्रयोग किसी गैर कानूनी काम यथा हथियार, ड्रग सप्लाई, कालाबाजारी इत्यादि में हो तो ये अराजक तत्व राज्य की पहुंच से बाहर हो जाएंगे.
- यदि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन में आप से कोई भूल हो जाती है तो आप अपने पैसे का रिफंड नहीं प्राप्त कर सकते.

क्रिप्टोकरेंसी के नियमन हेतु प्रयास:

भारत सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी के नियमन हेतु कई कदम उठाए जा रहे हैं. कुछ महतवपूर्ण नियमन निम्न है:

- सरकार क्रिप्टोकरेंसी को नियमित करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में 'द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी बिल 2021' लाएगी. इस बिल में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर पाबन्दी लगायी जाएगी. क्रिप्टोकरेंसी तकनीक के इस्तेमाल में राहत देने के लिए ही सरकार इस बिल में भारतीय रि. जर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान रखेगी.

निष्कर्ष:

यद्यपि 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया था परंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस प्रतिबंध को निरस्त कर दिया गया है. क्रिप्टो करेंसी में भविष्य की मुद्रा बनने की क्षमताएं हैं अत: एक तकनीकी उन्मुख देश होने के कारण भारत इससे दूर नहीं भाग सकता. अत: आवश्यक है कि भारत की नियामक तंत्र क्रिप्टो करेंसी को नियमित करें जिससे जनता की भलाई तथा अराजक तत्वों का विरोध हो सके. सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है.

NOTES

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें

1. 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न

भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52 वां संस्करण 20 से 28 नवंबर के मध्य गोवा में संपन्न हुआ. महोत्सव में अमेरिकी निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसी और हंगरी के निर्देशक इस्तवान स्जाबो को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया. वहीं इस वर्ष जूरी के अध्यक्ष ईरानी फिल्म निर्माता सुश्री रक्शान बनिएतमाड थे.

2. भारत यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में निर्वाचित

भारत, यूनेस्को के (2021-25 के कार्यकाल) कार्यकारी बोर्ड के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है. इस बार भारत को 164 मत प्राप्त हुए है. बता दें की भारत, एशियाई और प्रशांत राज्यों के समूह IV के लिए निर्वाचित हुआ है. यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड संगठन के कार्यक्रम और संबंधित बजट अनुमानों की जांच करता है. यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल चार साल का होता है.

3. एशियाई तीरंदाजी चौंपियनशिप में भारत को सात पदक

इस वर्ष एशियाई तीरंदाजी चौंपियनशिप (2021) ढाका में आयोजित की गयी. इस चौंपियनशिप में भारत ने सात पदक जीते. एक स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किये. कोरियाई टीम ने महिला रिकर्व फाइनल में अंकिता भक्त, रिधि फोर और मधु वेदवान की भारतीय तिकड़ी को हराया.

4. फुटबॉल कमेंटेटर नोवी कपाड़िया का निधन

प्रसिद्ध फुटबॉल कमेंटेटर और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर नोवी कपाड़िया, का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे. नोवी कपाड़िया मोटर न्यूरॉन रोग से पीड़ित थे, यह एक दुर्लभ विकार है, जिसमें रीढ़ और मस्तिष्क में न्यूरॉन्स धीरे-धीरे काम करना बंद कर देते हैं. फुटबॉल कमेंटेटर के अतिरिक्त कपाड़िया ने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है,जिनमें प्रमुख हैं- बेयरफुट टू बूट्स, द मेनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल.

5. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशनप्रकाश पादुकोण को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित करेगा

बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेगा. प्रकाश पादुकोण का नाम बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नामित किया था. जिसके बाद बीडब्ल्यूएफ के पुरस्कार आयोग के प्रस्ताव पर बीडब्ल्यूएफ परिषद द्वारा भारतीय दिग्गज को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है. इससे पूर्व 2018 में बीएआई का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है.

6. स्मृति ईरानी का पहला उपन्यास 'लाल सलाम' प्रकाशित

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 'लाल सलाम' के नाम से अपना पहला उपन्यास लिखा है. यह उपन्यास एक सच्ची घटना से प्रेरित है. इस उपन्यास में अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या को आधार बनाया गया है. स्मृति ईरानी ने कहा की यह उपन्यास उन असाधारण व्यक्तियों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने रेड कॉरिडोर में चुनौतियों का सामना करने में सेवा दी है.

7. उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर लगाया गया

उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में राज्य का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर लगाया गया है. यह वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर (एपीसीटी) डीएनडी एक्सप्रेसवे की ग्रीन बेल्ट पर सेक्टर 16 के पास बनाया गया है. टॉवर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है. बता दें कि नोएडा में नवंबर से जनवरी तक, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 320 से 400 के निचले स्तर तक गिर जाता है. दावा है की यह टावर गंदी हवा को सोख लेने के साथ-साथ इस पर लगाए गए फिल्टर पार्टिकुलेट मैटर का भी निदान करेंगे.

8. स्वदेश निर्मित आईएनएस विशाखापत्तनम को कमीशन किया गया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 नवम्बर 2021 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित आईएनएस विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना में शामिल किया. प्रोजेक्ट 15बी के तहत बना पहला जहाज, आईएनएस विशाखापत्तनम स्टील्थ-निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाज है. इसका डिजाइन नेवल डिजाइन निदेशालय द्वारा तथा निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई द्वारा किया गया है.7,400 टन के विस्थापन क्षमता के साथ इसकी लंबाई में 163 मीटर, चौड़ाई में 17 मीटर है. इसे भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा सकता है। आईएनएस विशाखापत्तनम का डिजाइन इस तरह किया गया है कि यह परमाणु, जैविक और रासायनिक (एनबीसी) युद्ध स्थितियों में लड़ने के लिए सक्षम है.

9. सशस्त्र बल कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए गए

राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा मैडल प्रदान किए. कोर ऑफ इंजीनियर्स सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. जबकि मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल और नायब सूबेदार सोमबीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है. वहीं इस वर्ष वीर चक्र ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्थमान को दिया गया.

10. भारतीय पुलिस फाउंडेशन की स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान

भारतीय पुलिस फाउंडेशन की स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स की सूची में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है. वहीं तेलंगाना और असम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. इस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पुलिस (5.81 अंक के साथ) ने 28वीं रैंक हासिल की है. बता दें कि 2014 में गुवाहाटी में हुए राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों के डीजीपी के सम्मेलन में पीएम मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग का विचार पेश किया था.

संक्षेप में आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग सर्वे 2021:

- इंडियन पुलिस फाउंडेशन के इस सर्वे में भारत के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है.
- सर्वे में आईपीएफ द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग के लगभग 10 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था. इसमें क्षमता के 6 संकेतक, मूल्यों के 3 संकेतक और सार्वजनिक विश्वास का 1 संकेतक शामिल था.
- इस सर्वे में 1 से 10 तक का स्कोर दिया गया है. 10 के स्कोर का मतलब उच्चतम संतुष्टि स्तर था.
- सर्वेक्षण में आईआईटी-कानपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल थे.

11. मणिपुर में स्थापित होगा हथकरघा गांव

कपड़ा मंत्रालय ने मणिपुर के मोइरंग में एक हथकरघा गांव स्थापित करने का निर्णय लिया है. बता दें की मणिपुर का मोइरंग शहर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध के इंफाल अभियान के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) ने तिरंगा झंडा फहराया था. इतिहास के इसी घटना की याद में मोइरंग में एक आईएनए संग्रहालय स्थित है.

12. एबीयू-यूनेस्को पीस मीडिया अवाड्र्स

'टुगेदर फॉर पीस' पहल के तहत, यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से मलेशिया के कुआलालंपुर में एबीयू-यूनेस्को पीस मीडिया अवाड्र्स 2021 का आयोजन किया. इस आयोजन में दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित शो को कई पुरस्कार मिले हैं दूरदर्शन के कार्यक्रम 'डेफिनिटली लीडिंग द वे' ने 'लिविंग वेल विद सुपर डायवर्सिटी' श्रेणी के तहत एक पुरस्कार जीता. वहीं आकाशवाणी के कार्यक्रम 'लिविंग ऑन द एज- द कोस्टल लाइफ' ने 'नैतिक और प्रकृति के साथ सतत संबंध' की श्रेणी में पुरस्कार जीता है.

13. समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पांचवां ईएएस कॉन्फ्रेंस कोलकाता में

समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पांचवां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोलकाता में किया गया. यह कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया. सम्मेलन में, विशेषज्ञों ने चार विषयगत सत्रों के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की.

- समुद्री सुरक्षा.
- संसाधन और सूचना साझा करना.
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग.
- महामारी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन.

ऐसा पहला कॉन्फ्रेंस नवंबर 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. जबकि समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथा ईएएस कॉन्फ्रेंस चेन्नई में आयोजित किया गया था.

14. एनजीओ प्रथम को मिला वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार

वर्ष 2021 का शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार एनजीओ प्रथम को दिया जायेगा. प्रथम को यह पुरस्कार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए दिया गया है. बता दें की इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रतिवर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है. यह पुरस्कार 1968 से शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है. पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाती है

15. नीति आयोग द्वारा एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 जारी

नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) शहरी सूचकांक 2021-22 जारी किया गया है. सूचकांक के लिए कुल 56 शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया था. 56 शहरी क्षेत्र में से 44 क्षत्रों की कुल आबादी 1 मिलियन से अधिक है. इस सूचकांक में शिमला (हिमाचल प्रदेश) को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है. वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: कोयंबटूर (तमिलनाडु) और चंडीगढ़ का स्थान है. सूचकांक में अंतिम स्थान के तीन शहरी क्षेत्र क्रमश: धनबाद (झारखण्ड) , मेरठ (उत्तर प्रदेश) और ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) हैं. नीति आयोग का मानना है कि ऐसे सूचकांक, एसडीजी के स्थानीयकरण को मजबूत करेंगे

16. मत्स्य पालन क्षेत्र में आंध्रप्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य

'विश्व मत्स्य दिवस' के अवसर पर,मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया है. वहीं मत्स्य पालन क्षेत्र में बालासोर को भारत का ष्सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला समुद्री जिला" नामित किया गया है. यह पहला अवसर है जब ओडिशा के किसी जिले को यह पुरस्कार मिला है. जबकि अंतर्देशीय राज्य और जिला का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्रमशः तेलंगाना और बलाघाट (मध्य प्रदेश) को मिला है. इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी राज्य का पुरस्कार त्रिपुरा को मिला है.

17. अल साल्वाडोर बनाएगा दुनिया का पहला बिटकॉइन शहर

अल साल्वाडोर ने अधिकारिक घोषणा की है कि वह दुनिया का पहला संप्रभु बिटकॉइन बांड जारी करने साथ बिटकॉइन सिटी की स्थापना भी करेगा, जो आय, संपत्ति और पूंजीगत लाभ से मुक्त होगा. बिटकिन शहर कि स्थापना ला यूनियन शहर के पूर्वी भाग में की जाएगी. घोषणा में कहा गया है कि वैट को छोड़कर, शहर पर कोई अन्य कर नहीं लगाया जायेगा. अनुमान है कि शहर के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कुल लागत लगभग 300,000 बिटकॉइन है.

18. कामधेनु हितकारी मंच को 'गोपाल रत्न' पुरस्कार

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कामधेनु हितकारी मंच को केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय ने 'गोपाल रत्न' पुरस्कार दिया है. यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति की श्रेणी में दिया गया है. साथ ही 'सर्वश्रेष्ठ दुग्ध सहकारी समिति' का पुरस्कार भी कामधेनु हितकारी मंच को दिया गया है. कामधेनु हितकारी मंच राज्य की अग्रणी डेयरी सहकारी संस्थाओं में से एक है.

19. मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी

मैग्डेलेना एंडरसन को स्वीडन की संसद ने देश की पहली महिला प्रधान मंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है. बता दें की यह पहला अवसर है जब स्वीडन का नेत्रित्व कोई महिला करेगी. संसद की मंजूरी मिलने साथ ही मैग्डेलेना एंडरसन, सेंटर-लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स के नेता स्टीफन लोफवेन का स्थान लेंगी.

20. एनएफएचएस-5 के रिपोर्ट : महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक

2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -5)की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हो गयी है.इस रिपोर्ट कहा गया गया है की भारत में लिंगानुपात बढ़कर 1,020 हो गया है. इसका अर्थ हुआ है कि भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएं हैं. रिपोर्ट में पिछले वर्षों की तुलना करते हुए बताया गया है कि वर्ष 2005-06 में लिंगानुपात 1,000 से गिरकर 2015-16 में 991 हो गया था. बता दें की एनएफएचएस-5 लिंगानुपात के आंकड़े जनगणना के आंकड़ों से भिन्न होते हैं.उदाहरण से समझे तो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 940 है, जबकि 2015-16 के एनएफएचएस-4 सर्वेक्षण के अनुसार लिंगानुपात 991था. एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण में सबसे खराब शहरी लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में पाया गया. यंहा प्रति 1000 पुरुषों पर 775 महिलाएं हैं.

21. 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है.1949 में इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया तथा अधिनियमित किया गया था. बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2015 से 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया था. संविधान दिवस मानाने का उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है. बता दें की भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु राष्ट्र का सबसे लम्बा लिखित संविधान है.

22. नासा ने ग्रह रक्षा प्रणाली डार्ट लॉन्च की

नासा ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली डबल एस्टोरॉएइड रिडायरेक्शन टेस्ट (डार्ट) लॉन्च किया है. नासा का यह अन्तरिक्ष यान कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है. प्रयोग के लिए यह मिशन डाइमोरफोस एस्टोरॉएइड से टकराएगा. बता दें ही यह इस एस्टोरॉएइड से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है यह सिर्फ भविष्य के खतरों को ध्यान में रखते हुए मात्र एक प्रयोग है. नासा का अनुमान है कि डार्ट 26 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 के बीच डार्ट डाइमोरफोस से टकराएगा.

23. 2025 में एशियाई यूथ पैरा खेलों की मेजबानी ताशकंद को मिली

एशियाई पैरालंपिक समिति (एपीसी) की अनुशंषा पर, 2025 के एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी ताशकंद को मिली है. उज्बेकिस्तान के पर्यटन और खेल मंत्रालय के समर्थन से इन खेलों का आयोजन 2025 के सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में ताशकंद में आयोजित किये जायेंगे. बता दें कि वर्ष 2021 के एशियन यूथ पैरा गेम्स का चौथा संस्करण (दिसंबर में) बहरीन में आयोजित होगा.

24. पांच दिवसीय त्रिपक्षीय अभ्यास 'दोस्ती' संपन्न

भारत, मालदीव, और श्रीलंका के त्रिपक्षीय अभ्यास 'दोस्ती' का 15वां संस्करण मालदीव में 24 नवम्बर को संपन्न हुआ है. अभ्यास 'दोस्ती' का यह 30वां संस्करण है. इस तरह का पहला अभ्यास वर्ष 1991 में भरता और मालदीव के बीच आयोजित हुआ था. आगे वर्ष 2012 में श्रीलंका भी इस अभ्यास में शामिल हो गया था. मालदीव में पांच दिवसीय अभ्यास के लिए भारत की तरफ से आईसीजीएस वज्र और आईसीजीएस अपूर्व ने भाग लिया है.

25. बान की मून की आत्मकथा "रिजॉल्व्ड: यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड" प्रकाशित

बान की-मून (संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव) ने अपनी आत्मकथा "रिजॉल्व्ड: यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड" को प्रकाशित किया है. बता दें कि बान की-मून वर्ष 2007-2016 के बीच दो कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव रहे हैं. बान की-मून के बारे में रोचक तथ्य यह है की एक राजनयिक तौर पर उनकी पहली नियुक्ति भारत में ही थी. उन्होंने दो 5 साल के कार्यकाल (2007-2016) के लिए संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव के रूप में कार्य किया है. उनकी इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किया जा रहा है. इस आत्मकथा में उन्होंने खुद के वक्तित्व में परिवर्तन के क्रम को बताया है.

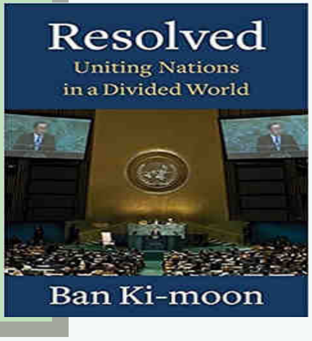

ब्रेन बूस्टर

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर, 2021 को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की. इन कानूनों का एक साल से अधिक समय से किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा था.

कानून को निरस्त करने का अर्थ:-

- कानून को रद्द करना कई तरीकों से किया जा सकता है, निरसन उनमे से एक तरीका है.
- कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान एक "सूर्यास्त" खंड जोड़ा जा सकता है, जिस तारीख के बाद इसका अस्तित्व स्वत समाप्त हो जाता है.
- जिस कानून के लिए कोई सूर्यास्त खंड नहीं होता है,संसद उस कानून को निरस्त करने के लिए एक और कानून पारित करती है.

सरकार किसी कानून को कैसे निरस्त करती है?

- अनुच्छेद 245 के अनुसार, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और राज्य का विधानमंडल पूरे या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है.
- संसद को इसी अनुछेद से कानून को निरस्त करने की शक्ति मिलती है.
- संसद किसी कानून को पूरी तरह से, आंशिक रूप से या यहां तक कि उस हद तक निरस्त कर सकती है, जब तक कि वह अन्य कानूनों के उल्लंघन में करती हो.

निरस्त कृषि कानून

- कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण)अधिनियम, 2020. इस अधिनियम ने मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडियों के बाहर कृषि उपज में व्यापार की अनुमति दी.
- कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020. इसने अनुबंध खेती के लिए एक ढांचा प्रदान किया.
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020. इस अधिनियम का उद्देश्य कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू आदि के भंडारण पर प्रतिबंध को हटाना था.

कृषि कानून निरस्त

एक कानून को निरस्त करने की प्रक्रिया:-

- कानून को दो तरह से निरस्त किया जा सकता है
  - o एक अध्यादेश के माध्यम से
  - o कानून के माध्यम से
- जब एक कानून को अध्यादेश के माध्यम से निरस्त किया जाता है, तो संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा 6 महीने के भीतर बदलना होता है.
- अध्यादेश जारी करने के बाद,यदि 6 महीने में संसद द्वारा कानून पारित नहीं किया जाता है, तो निरसित कानून पुनर्जीवित हो जाता है.
- किसी कानून को निरस्त करने के लिए विधेयक को दोनों सदनों से गुजरना पड़ता है और इसके लागू होने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी होती है.

अधिनियमों की आवश्यकता

- कृषि विपणन में सुधार लंबे समय से लंबित मांग है. यह राज्य सरकारों के दायरे में आता है.
- 2000 के शुरुआती दशक में केंद्र सरकार ने राज्य के कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीसी) अधिनियमों में सुधार के लिए जोर दिया.
- 2019 के आम चुनावों में भारी बहुमत की पृष्ठभूमि में, वर्तमान सरकार ने इन कानूनों को पारित करके सुधारों को लागू करने का प्रयास किया.

निरसन का प्रभाव

- इन 3 कृषि कानूनों के डिजाइन और तंत्र में कुछ कमियां हो सकता हैं लेकिन सुधार के समर्थकों का कहना है कि वे सही दिशा में थे.
- सरकार द्वारा कई हितधारकों से परामर्श किए बिना सुधारों को लागू करने के फलस्वरूप यह प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई.
- निरसन व्यापक परामर्श और सुधारों के बेहतर डिजाइन की आवश्यकता की पुष्टि करता है.
- यह सरकार को स्टील्थ मोड में सुधारों को आगे बढ़ाने से भी रोकेगा.

परिस्थितियाँ:- जब कानून पारित किए गये

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन सुधारों की घोषणा की थी.
- केंद्रीय कैबिनेट ने इन तीन कानूनों को मंजूरी दी और जून 2020 में इन्हें अध्यादेश के रूप में मंजूरी दी.
- सितंबर 2020 में मानसून सत्र में सरकार ने उन्हें विधेयक के रूप में पेश किया.
- न केवल विपक्ष बल्कि एनडीए के सहयोगियों ने भी बिलों का विरोध किया.

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कारण तीन बड़े परिवर्तन हुए:-

- संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई.
- अब संविधान सभा को दो कार्य करने थे

संविधान निर्माण:- इसकी अध्यक्षता डॉ राजेंद्र प्रसाद ने की थी. बाद में डॉ राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने.

प्रांतीय विधानमंडल:- इसकी अध्यक्षता जी वी मावलंकर ने की थी. बाद में वे भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने.

- मुस्लिम लीग के सदस्य(पाकिस्तान क्षेत्रों सेसम्बद्ध) भारत के लिए संविधान सभा से हट गए. अब संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिनमें से 229 सदस्य भारतीय प्रांतों से थे और 70 देसी रियासतों से थे.

संविधान सभा की मांग

- पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय ने भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग की।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा की मांग की.
- 1940 में "अगस्त प्रस्ताव" द्वारा, ब्रिटिश सरकार ने अंतत: सैद्धांतिक रूप से मांग को स्वीकार कर लिया.
- क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद डो. मिनियन राज्य स्थिति की पेशकश की. गांधी ने क्रिप्स की पेशकश को "पोस्टडेटेड चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला है" कहा था.
- 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया; इसने संविधान सभा के लिए एक योजना प्रस्तुत की.

संविधान सभा की समितियाँ

- संघ शक्ति कमेटी - जवाहरलाल नेहरू
- संघीय संविधान समिति - जवाहरलाल नेहरू
- प्रांतीय संविधान समिति - सरदार पटेल
- प्रारूप समिति - डॉ बी आर अम्बेडकर
- मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीयोंतथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति - सरदार पटेल

खसंचालन समिति - डॉ राजेंद्र प्रसाद

- प्रक्रिया समिति - डॉ राजेंद्र प्रसाद

प्रारूप समिति

- 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। इसके 7 सदस्य थे:-

1. डॉ बी आर अम्बेडकर (अध्यक्ष)
2. एन गोपालस्वामी अय्यंगार
3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यार
4. सैयद मोहम्मद सादुल्ला
5. डॉ के एम मुंशी
6. एन माधव राव (बी एल मित्तर की जगह)
7. टी टी कृष्णमाचारी (डीपी खेतान की जगह)

- 21 फरवरी, 1948 को भारत के संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था.

संविधान सभा की संरचना

संविधान सभा में 389 सदस्य थे. इनमें से 296सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93सदस्य देशी रियासतों से थे.

संविधान बनाने की प्रक्रिया

संविधान सभा की पहली बैठके

- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी.
- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया.
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था.

उद्देश्य प्रस्ताव

- 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया.
- इसने संवैधानिक संरचना के मौलिक और दर्शन को निर्धारित किया.

संविधान का प्रवर्तन

- 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था.
- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया.
- 26 जनवरी 1950 को शेष लेख लागू हुए.
- "संविधान का प्रारंभ" 26 जनवरी 1950 को हुआ.

संविधान का प्रभाव में आना

- भारत के संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर, 1948 को पेश किया गया था और पहली बार वाचन हुआ था.
- दूसरा वाचन 15 नवंबर, 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ.
- तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ.

26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने "भारत के संविधान" को अपनाया. इसमें एक प्रस्तावना , 22 भागों में 395 अनुछेद और 8 अनुसूचियां थी.

कोविड 19 से लड़ाई के दौरान भूख पर अंकुश

खबरों में क्यों

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का उद्देश्य कोविड-19 से राहत के रूप में 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना है, जो योजना नवंबर, 2021 के महीने में समाप्त हो रही थी.

योजना की पहुंच

- पहले लॉकडाउन के दौरान केवल राशन कार्ड धारक परिवार ही पात्र थे.
- आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मई और जून 2020 के दौरान, 8 लाख टन खाद्यान्न राज्यों को बिना राशन कार्ड के फंसे हुए प्रवासियों और अन्य को वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया था.
- 2011 की जनगणना के आंकड़ों से 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों की सीमा तय की गई है.

वाद-विवाद

1. **पक्ष में**

- सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बेरोजगारी का रिकॉर्ड स्तर और कमजोर वर्गों के बीच व्यापक भूख न केवल पीएमजीकेएवाई के विस्तार के लिए बल्कि सार्वभौमिक सार्व. जनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए भी एक आदर्श स्थिती है. ताकि सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके.
- खुले बाजार में ऊंची कीमतों को देखते हुए दालें और खाना पकाने का तेल भी मिलाना चाहिए

2. **विपक्ष में**

- अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो रही है और खुली बाजार बिक्री प्रणाली (ओएमएसएस) अच्छा काम कर रही है
- संबंधित राज्य प्रवासी श्रमिकों और कम. जोर वर्गों की आवश्यकता के अनुसार खुले बाजार से खाद्यान्न खरीद सकते हैं.

पीएमजीकेएवाई के बारे में

- मार्च 2020 में, जब सरकार ने पहले देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की, पीएमजीकेएवाई केंद्र के प्रारंभिक कोविड -19 राहत पैकेज का हिस्सा था.
- योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है.
- यह राशन कार्ड धारकों को रियायती दर पर उपलब्ध 5 किलो अनाज से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है.
- जब महामारी के कारण नौकरियां चली गईं और आजीविका नष्ट हो गई, इस योजना ने खाद्यान्न उपलब्धता में मदद की.

एफसीआई के पास खाद्य भंडार

- पीएमजीकेएवाई के कारण अधिक निर्गमन के बावजूद, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास वर्तमान में खाद्यान्न भंडार रिकॉर्ड 616 लाख टन है.
- रबी सीजन की खरीद के बाद जून 2022 तक स्टॉक 942 लाख टन होने की उम्मीद है

योजना की विशालता

- यह योजना शुरू में अप्रैल से जून, 2020 के लिए लागू की गई थी. फिर जुलाई से नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई.
- इस चरण में लाभार्थियों को 320 लाख टन अनाज आवंटित किया गया था.
- महामारी की दूसरी लहर के दौरान, योजना मई और जून 2021 के लिए शुरू की गई थी। इसे फिर से जुलाई से नवंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था.
- इस अवधि के दौरान 278 लाख टन अनाज आवंटित किया गया था.

वर्तमान स्थिति

- 24 नवंबर 2021 को केंद्र ने इस योजना को और चार महीने यानी मार्च 2022 तक जारी रखने का फैसला किया.
- केंद्र ने स्वीकार किया कि अर्थव्यवस्था में सुधार के बीच गरीब परिवारों को अभी भी खाद्य सुरक्षा सहायता की आवश्यकता है.
- केंद्र ने आंकड़ेके माध्यम से अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की बात कही.

भारत पर अमेरिका की उच्च मुद्रास्फीति दर का प्रभाव

खबरों में क्यों

- भारत में और विश्व स्तर पर बढ़ती कीमतों ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है.10 नवंबर, 2021 को, संयुक्त राज्य के श्रम विभाग ने अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 6.2% दर्ज की.
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में बढ़कर 4.5% हो गई है.

अमेरिकी मुद्रास्फीति चिंता का विषय क्यों है

- पिछले तीन दशकों में 6.2% साल दर साल की सबसे बड़ी वृद्धि दर है.
- फेडरल बैंक 2% तक मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य रखता है.
- अमेरिका में खुदरा मुद्रास्फीति मई 2020 से लगभग हर महीने तेजी से बढ़ रही है
- अधिकांश अर्थशास्त्री और नीति निर्माताओं के लिए यह आश्चर्य की बात है, जो की लंबे समय तक मंदी से बचने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे.

अमेरिका में उच्च मुद्रास्फीति का कारण

- अमेरिका में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तेजी से शुरू होने के कारण, अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ.
- अमेरिकी सरकार ने उपभोक्ताओं और अपनी नौकरी गंवाने वालों को राहत देने के लिए अरबों डॉलर जरुरतमंदों को दिए
- इनके कारण, मांग में सुधार हुआ है लेकिन आपूर्ति सुचारु रूप से ना हो सकी है.
- सामान्य समय के दौरान भी, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सामान्य रूप से काम करना शुरू करने और मांग को पूरा करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है.
- आर्थिक सुधार की गति और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के बीच असामंजस्य के कारण मांग और आपूर्ति में अंतर आया है.

मुद्रास्फीतिः- मूल्य में वृद्धि

- मुद्रास्फीति एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है.
- मुद्रास्फीति एक व्यापक पैमाना है, जिसमे दैनिक या सामान्य उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की लागत में समग्र वृद्धि, जैसे कि भोजन, कपड़े, आवास या देश में रहना आदि सम्मलित है.
- मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में गिरावट का संकेत है
- उच्च मुद्रास्फीति लोगों की क्रय शक्ति को नष्ट कर देती है.

अन्य अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति

दुनिया की अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि का सामना कर रही हैं.

मुद्रास्फीति की माप

भारत में मुद्रास्फीति को दो मुख्य सूचकांकों द्वारा मापा जाता है:-

- **थोक मूल्य सूचकांक(डब्ल्यूपीआई):-** बड़े व्यवसायों द्वारा छोटे व्यवसायों को आगे बेचने के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अंतर की गणना डब्ल्यूपीआई द्वारा की जाती है.
- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआई):-** वस्तुओं और सेवाओं जैसे भोजन, चिकित्सा देखभाल, परिवहन आदि की कीमतों में अंतर की गणना सीपीआई द्वारा की जाती है.

भारत में स्थिति

- भारत में, उच्च मुद्रास्फीति महामारी से पहले से उपस्थित है.
- 2019 के अंत से, मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 2% से 6% के लक्ष्य क्षेत्र से ऊपर रही है.
- महामारी ने आपूर्ति पक्ष पर ब्रेक लगा दिया है, हालांकि मांग का स्थिति अभी भी पूर्व-कोविड स्तरों से नीचे है.

मंहगाई :- कारण

- उच्च मांग और कम उत्पादन मांग आपूर्ति अंतर पैदा करते हैं, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है.
- अधिक संचलन के कारण धन अपनी क्रय शक्ति खो देता है और इससे मुद्रास्फीति में वृद्धिहोती है
- जब लोगों के पास अधिक पैसा होता है, तो वे अधिक खर्च करते हैं और इससे मांग में वृद्धि होती है.
- माल की उत्पादन लागत में वृद्धि भी मुद्रास्फीति का कारण बनती है क्योंकि अंतिम उत्पाद की लागत बढ़ जाती है.

भारत पर प्रभाव

- उच्च आयातित मुद्रास्फीति
- उच्च मुद्रास्फीति के कारण, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं ढीली मौद्रिक नीति को छोड़ देंगी.
- भारत पर दो बड़े प्रभाव

1. बाहर पैसे जुटाने का खर्चा ज्यादा रहेगा
2. मुद्रास्फीति और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए आरबीआई को धक्का दिया जाएगा.

भारत में मुद्रास्फीति की आगामी स्थिति

- मुद्रास्फीति और बढ़ेगी क्योंकि मांग बढ़ रही है परन्तु आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ है.
- कोर मुद्रास्फीति दर 6% से ऊपर है.
- कीमतों में वैश्विक वृद्धि से भारत की महंगाई और बढ़ेगी.

शहरी बाढ़

खबरों में क्यों

हाल ही में चेन्नई और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों के शहरों में भारी बारिश, बड़े पैमाने पर शहरी बाढ़ का कारण बनी है. भारत में, हाल के वर्षों में शहरी बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जिसने पूरे भारत को प्रभावित किया है

परिभाषा

बाढ़ को "प्रायः शुष्क क्षेत्र के जलमग्न होने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां पानी की बड़ी मात्रा अचानक अत्यधिक वर्षा, एक बहती नदी या झील, पिघलने वाली बर्फ या एक असाधारण उच्च ज्वार से आती है"

शहरी बाढ़ के प्रभाव

- **प्राथमिक:**– हताहत और संपत्ति का नुकसान
- **माध्यमिक:**– जल का दूषित होना, पूरी फसल का नुकसान, जलजनित रोगों का फैलाव
- **तृतीयक:**– आर्थिक कठिनाई, पर्यटन की हानि, भोजन की कमी, पुनर्निर्माण लागत, मूल्य वृद्धि

शहरों के प्रकार

- **तटीय शहर:**– तटीय शहरों में बाढ़, उच्च ज्वार के कारण जटिल होती है
- **अंतर्देशीय शहर:**– अंतर्देशीय शहरों में तत्काल जल निकासी और जल भराव की रोकथाम एक चुनौती है
- **पहाड़ी शहर:**– बहुत अधिक अपवाह,कम प्रवाह की अवधि और ढलान के कारण उत्पन्न उच्च परिशोध,बाढ़ के साथ मिट्टी के प्रवाह और भूस्खलन को ट्रिगर कर सकते है
- **नदियों के किनारे बसे शहर:**– मध्य और निचले गंगा के मैदानों में पानी के प्रवाह के बदलने की चुनौती

भविष्य के विकल्प

- समुदायों के लचीलेपन और बुनियादी ढांचे की अनुकूली क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दें.
- कार्यान्वयन के संदर्भ में जल संवेदनशील शहरी डिजाइन और योजना तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं
- सुभेद्यता विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन को सिटी मास्टर प्लान का अभिन्न अंग होना चाहिए
- शख्त भूमि उपयोग नियंत्रण, ईआईए और प्रवर्तन, नाजुक आर्द्रभूमि और बाढ़ के मैदानों कोकंक्रीट के जंगल बनने से बचाने हेतु महत्वपूर्ण है.

भारत में शहरी बाढ़ का खतरा

- भारत में शहरी बाढ़ आपदाओं की घटनाए बढ़ती जा रही है
- भारत में एक विशेषता यह है कि हमारे यहाँ मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है
- अन्य मौसम प्रणालियाँ भी बहुत अधिक वर्षा लाती हैं
- तूफान की लहरें तटीय शहरों/कस्बों को भी प्रभावित कर सकती हैं
- बांधों द्वारा अचानक छोड़े जाने या पानी छोड़ने में विफलता का भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है
- शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि हुई है
- वैश्विक जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप बदलते मौसम के पैटर्न और समय की छोटी अवधि में होने वाली उच्च–तीव्रता वाली वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हुई है
- समुद्र का जलस्तर बढ़ने का खतरा सभी तटीय शहरों पर मंडरा रहा है

शहरी बाढ़

- ईओसी की संरचना

1. अध्यक्ष :– जिला आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/नगर आयुक्त
2. शहरी परियोजनाओं के प्रबंधन में लाइन एजेंसियों के सदस्यजैसे किनगर निगम, नगर स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग, शहरी विकास प्राधिकरण, फायर ब्रिगेड, सार्वजनिक परिवहन, पुलिस आयुक्तालय, यातायात पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा, भारतीय मेट्रोलॉजिकल विभाग (क्षेत्रीय कार्यालय), लोक निर्माण विभाग, बिजली आपूर्ति विभाग, रेलवे, दूरसंचार , खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और अन्य

सर्वाधिक प्रभावित

- हमारे शहरों में गरीबों की सुभेद्यता बहुत गहरी और बनी हुई है.
- बाढ़ का पानी अनुपचारित ठोस अपशिष्ट और मल पदार्थों को अवैध बस्तियों के आसपास प्रसारित करता है, जिससे मलेरिया, डेंगू, डायरिया आदि का प्रकोप वर्षा के मौसम की तुलना में अधिक लंबे समय तक बना रहता है.

जिम्मेदारी

- हमारे शहर प्राकृतिक स्थलाकृति के संबंध में बहुत कम या बिना किसी जानकारी के बनाए गए हैं और समग्र कार्रवाई कागंभीर रूप से अभाव है.
- नियामक तंत्र में , पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए), भवन उपनियम जैसे वर्षा जल संचयन, टिकाऊ शहरी जल निकासी आदि का आभाव है.
- उपयोगकर्ता द्वारा इन्हें न अपनाना तथा प्रवर्तन एजेंसियों का कमजोर होना भी प्रमुख कारण हैं.
- नदी तलों, प्रवाह चैनलों पर अतिक्रमण, जल निकायों की गाद बाढ़ की गंभीरता को बढ़ाती हैं.

शहर स्तर की कार्रवाई

- आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) की स्थापना:–

ईओसी की अध्यक्षता जिला आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/नगरपालिका आयुक्त करेंगे. ईओसी सभी आपात स्थितियों के समन्वय और प्रबंधन के लिए मस्तिष्क और तंत्रिका के रूप में कार्य करता है

- ईओसी का कार्य

1. लाइन एजेंसियों के साथ समन्वय
2. नीति निर्माण और एसओपी के अनुसार संयंत्र तैयार करना
3. संचालन प्रबंधन की दिशा और निगरानी
4. सूचना एकत्र करना और रिकॉर्ड रखना
5. सार्वजनिक सूचना और नागरिक अद्यतन
6. संसाधन प्रबंधन
7. रिपोर्टिंग

एक बहु स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली:- खरीद और निहितार्थ

खबरों में क्यों

एक रूसी अधिकारी ने भारत को **S-400** वायु रक्षा प्रणाली की डिलीवरी के बारे में खबर दी. वायु रक्षा प्रणाली की पहली इकाई को भारत की पश्चिमी सीमा में लगाया जा रहा है.

कार्यप्रणाली

- **S-400** एक रक्षा क्षेत्र के निकट एक हवाई खतरे का पता लगाता है. यह अपने प्रक्षेपवक्र की गणना करता है और इसका मुकाबला करने के लिए मिसाइल दागता है.
- **S-400** में लंबी दूरी के निगरानी रडार हैं जो कमांड वाहन को सूचना भेजते हैं जो मिसाइल लॉन्च का आदेश देता है.

भारत के लिए सौदे का महत्व

- चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से खतरों को लेकर **S-400** एक 'गेम चेंजर' है
- **S-400** ने **IAF** की घटती लड़ाकू स्क्वाड्रन ताकत को ऑफसेट किया है.
- राष्ट्रीय वायु रक्षा प्रणाली संगठन में **S-400** का एकीकरण आसान होगा क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में रूसी वायु रक्षा प्रणालियाँ हैं.
- **S-400** को खरीदकर भारत ने अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' बनाए रखी है.

S-400 के बारे में

- **S-400** को दुनिया की सबसे उन्नत और शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली में से एक माना जाता है.
- **S-400 Triumf** में रॉकेट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई हमलों से बचाने की क्षमता है
- नाटो ने इसे **SA-21** ग्रोलर नाम दिया है
- **S-400** एक विशेष क्षेत्र में एक ढाल के रूप में कार्य करता है और यह सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली है
- यह एक "एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल" (**A2/AD**) एसेट है.
- यह सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक संपत्तियों को हवाई हमलों से बचाने के लिए बनाया गया है.
- **S-400** में से प्रत्येक में दो बैटरी होती हैं, प्रत्येक में एक कमांड और नियंत्रण प्रणाली होती है.
- **S-400** 4 तरह की मिसाइलों के साथ आता है.

1. छोटी दूरी40 किमी तक
2. मध्यम दूरी 120 किमी
3. लंबी दूरी2 50 किमी
4. बहुत लंबी दूरी 400 किमी

- **S-400** एक साथ 600 किमी रेंज में 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है और 400 किमी रेंज में 72 ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकता है.

वितरण की स्थिति

- उच्च रैंकिंग रूसी अधिकारी के अनुसार, रूस ने भारत को एस-400 की आपूर्ति शुरू कर दी है और 2021 के अंत तक पहला डिवीजन दे दिया जाएगा.
- भारत ने अक्टूबर 2018 में पांच यूनिट का ऑर्डर दिया है.
- भारत सरकार ने संसद में बताया था कि सभी इकाइयों की अंतिम डिलीवरी अप्रैल,2023 तक पूरी होने की संभावना है.

S-400 के ग्राहक

- बेलारूस, अल्जीरिया, तुर्की और चीन ने रूस से वायु रक्षा प्रणाली खरीदी है.
- सऊदी अरब, मिस्र और कतर ने वायु रक्षा प्रणाली में रुचि दिखाई है.

CAATSA के अंतर्गत प्रतिबन्ध

- **चीन:-** रूस से एस-400 औररूसी फर्म रोसोबोर्नएक्सपोर्ट से सुखोई-35 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए.
- **तुर्की:-** 2020 में एस-400 की खरीद के लिए अंकारा को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा **F-35** जेट्स की बिक्री भी रद्द कर दी गई है.

क्यों परेशान है अमेरिका

- अमेरिका चाहता है कि भारत रूस पर अपनी सैन्य हार्डवेयर निर्भरता कम करे.
- काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन्स एक्ट (सीएएटीएसए) के माध्यम से अमेरिका के यूएसए रूसी रक्षा उपकरण खरीदने के लिए देशों को प्रतिबंधित कर सकता है.
- **S-400** के शामिल होने से बलों की 'अंतर-संचालन' में बाधा उत्पन्न होती है.

भारत का पक्ष

- अमेरिका के दबाव में भारत पीछे नहीं हटा है.
- एक प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय ने माना कि यह मुद्दा कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच "चर्चा में" था."इसे उठाया गया था और हमने इस पर चर्चा की है और अपना दृष्टिकोण समझाया है और इस पर चर्चा जारी है"

ईओडीबी रैंकिंग का प्रकाशन रोका गया

खबरों में क्यों

वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक समूह ने 16 सितंबर, 2021 को कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) रैंकिंग के प्रकाशन को रोका जा रहा है.

ईओडीबी रैंकिंग क्या है

- रैंकिंग 190देशो की आर्थिक व्यवस्था में नियमों के स्तर को रेखांकित करती है
- यह एक व्यवसाय को शुरू करने, बनाए रखने और बंद करने के लिए आवश्यक 12 मापदंडों की तुलना करता है
- एक व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट, बिजली कनेक्शन प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण, ऋण प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करना, करों का भुगतान करना, सीमाओं के पार व्यापार करना, अनुबंधों को लागू करना और दिवाला का समाधान करना पैरामीटर हैं.
- डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की सफलता के लिए "एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिकेटर" आवश्यक है
- समय, लागत औरन्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता तीन चर हैं जिन्हें विश्व बैंक ने देशों की रैंकिंग के लिए ध्यान में रखा है.

रिपोर्ट का महत्व

- दुनिया भर के राष्ट्र इस सूचकांक को विशेष महत्व देते हैं.
- यह सूचकांक सबसे व्यापार-अनुकूल से सबसे कम व्यापार-अनुकूल देशों की रैंकिंग को दर्शाता है.
- यह रिपोर्ट बहुत प्रतिस्पर्धी और गतिशील है.
- भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील और नाइजीरिया जैसे विकासशील देशों ने अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तलाश में सूचकांक पर विशेष ध्यान दिया है.

गलत कृत्य

- विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष जिम योंग किम और पूर्व सीईओ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने डूइंग बिजनेस टीम को चीन के डेटा का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया ताकि वह अपनी 78 रैंक बनाए रख सके.
- डेटा हेरफेर के आरोपों के साथ जून 2020 में आंतरिक ऑडिट को सक्रिय किया गया था.
- विश्व बैंक पर चीन के अनुचित प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई.

इतनी बुरी हालत में क्यों

- जनवरी 2018 में, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने घोषणा की कि पिछले चार वर्षों की रैंकिंग को सही किया जाएगा और पुनर्गणना की जाएगी.
- चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट के प्रशासन के दौरान,चिली को गलत तरीके से दंडित किया गया था.
- पिछली समीक्षाओं और ऑडिट के निष्कर्षों के बाद, विश्व बैंक के प्रबंधन ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है.

सरकार का रुख

- केंद्र ने इस मामले पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है.
- कुछ अधिकारियों को डर है कि इससे भारत के कारोबारी सुगमता के प्रयासों को बदनामी होगी.
- अधिकारियों का मानना है कि यह चीन की गैर-नैतिक प्रथाओं को उजागर करने में मदद करेगा
- भारत को उम्मीद है की वैश्विक व्यापार में महवपूर्ण भूमिका निभानेवाली संस्थाए चीन से भारत में अपनी आपूर्ति श्रृंखला स्थानांतरित करेंगी.

रैंकिंग की विश्वसनीयता

- इस विवाद से पहले भी ये बात सार्वज. निक थी कि इसमें कई खामियां हैं.
- डेटा केवल भारत से दिल्ली और मुंबई; चीन से बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों को ध्यान में रखता है.
- इन शहरों में से बाहर , 'व्यापार करने में आसानी' उल्लेखनीय रूप से भिन्न होती है. चीन की रैंकिंग में इन लूप-होल का शोषण किया गया था.

कार्यप्रणाली में सुधार

विश्व बैंक के एक बाहरी पैनल ने निम्न सुझाव दिया

- 'वास्तविक' व्यापार मालिकों से अधिक डेटा संग्रह
- आवश्यक सार्वजनिक सुविधाए जैसे परिवहन, संचार, कौशल कार्यबल, कानून और व्यवस्था आदि प्रदान करने के लिए सरकारी कार्यों को महत्व दें
- व्यापार करने की पारदर्शिता और निगरानी में सुधार करें
- 'सरकार के साथ अनुबंध' संकेतक को और अधिक प्रासंगिक बनाएं
- 'रोजगार कामगार' संकेतक को पुनर्स्थापित और सुधारें लेकिन देशों को रैंक न करें
- 'अल्पसंख्यक शेयरधारकों की रक्षा' और 'दिवालियापन का समाधान' संकेतकों को हटा दें
- देशों की कर दरें संकेतक नहीं होनी चाहिए

भारत के लिए ईओडीबी का महत्व

- भारत की स्थिति 2014 में 142 के निचले स्तर से उछलकर 2019 में 63वें स्थान पर पहुंच गई, जो एक अद्वितीय उपलब्धि है.
- भारत का जल्द से जल्द टॉप 50 क्लब में शामिल होने का लक्ष्य.
- स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर व्यापार करने की स्थितियों में सुधार के लिए सरकार द्वारा व्यापक सुधार शुरू किए गए.
- सरकार ने घरेलू और विदेशी दर्शकों के सामने बड़े पैमाने पर रैंकिंग की मार्केटिंग की.

इतिहास से जुड़े 50 बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल, 1916 में महाराष्ट्र में होमरूल लीग की स्थापना की.
2. होमरूल आन्दोलन से एन सी केलकर नहीं जुड़े थे.

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित में से कौन थीओसॉफिकल सोसायटी की गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं था?

(a) मैडम एच पी ब्लावैत्सकी
(b) मि. ए ओ ह्यूम
(c) कर्नल एच एस ओल्कॉट
(d) श्रीमती एनी बेसेण्ट

3. निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 'स्वराज' शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में किया और हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया?

(a) राजा राममोहन राय
(b) स्वामी विवेकानन्द
(c) महात्मा गाँधी
(d) बाल गंगाधर तिलक

4. निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सामान्यत: मराठा शासन ने और विशेषत: शिवाजी ने भारत में आद्य राष्ट्रवादी चेतना को निरूपित किया?

(a) पण्डित रमाबाई
(b) एमजी रानाडे
(c) विपिन चन्द्र पाल
(d) गोपाल कृष्ण गोखले

5. कथन 1**:** भारत में जाति के सामाजिक संस्थानों में उपनिवेशी काल में बड़े परिवर्तन हुए.

कथन 2**:** समकालीन समाज में जाति, उपनिवेशवाद की अपेक्षा प्राचीन भारतीय परम्परा का कहीं अधिक परिणाम है.

कूट

(a) दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1, का सही स्पष्टीकरण है
(b) दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1, का सही स्पष्टीकरण नही है
(c) कथन 1 सत्य है, किन्तु कथन 2 असत्य है
(d) कथन 1 असत्य है, किन्तु कथन 2 सत्य है

6. कथन 1**:** भारत में उन्नीसवी शताब्दी के जनजातीय आन्दोलन, भूमि विस्थापनों और वनविधियों के लागू होने के परिणाम हैं.

कथन 2**:** भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ने जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को सुलझाया.

कूट

(a) दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1, का सही स्पष्टीकरण है
(b) दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1, का सही स्पष्टीकरण नही है
(c) कथन 1 सत्य है, किन्तु कथन 2 असत्य है
(d) कथन 1 असत्य है, किन्तु कथन 2 सत्य है

7. कथन 1**:** उन्नीसवीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन भारत की अर्थव्यवस्था बर्बादी की दशा तक पहुँच गई.

कथन 2**:** इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दीवानी अधिकार प्राप्त करने के परिणामस्वरूप कृषकों की और साथ ही भारत के परम्परागत हस्त-शिल्प उद्योग से जुड़े हुए लोगों की, दुर्दशा हुई.

कूट

(a) दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1, का सही स्पष्टीकरण है.
(b) दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1, का सही स्पष्टीकरण नही है
(c) कथन 1 सत्य है, किन्तु कथन 2 असत्य है
(d) कथन 1 असत्य है, किन्तु कथन 2 सत्य है

8. निम्नलिखित पर विचार कीजिए

"भारत संक्रियाओं के लिए एक बेस के रूप में कहीं अधिक विश्वसनीय होगा तथापि व्यवस्थापन की सम्भावना गाँधीजी के विलोपन से बहुत अधिक बढ़ जाएगी जिन्होंने व्यवस्थापन के प्रत्येक प्रयास को वर्षों से ध्वस्त किया है."

उपरोक्त कथन अंग्रेजों द्वारा किस संदर्भ में कहा गया है?

(a) खेड़ा सत्याग्रह
(b) सविनय अवज्ञा आन्दोलन
(c) भारत छोड़ो आन्दोलन
(d) असहयोग आन्दोलन

9. 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबन्दी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना?

(a) बड़े पैमाने पर ब्रिटिश व्यापार की वृद्धि
(b) अपनी संप्रभुता पर आक्रमण
(c) भारत में ब्रिटिश की असुरक्षा
(d) बंगाल पर ब्रिटिश नियन्त्रण

10. भारत में उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दियों में अनेक सामाजिक-राजनीतिक संगठन बने। 1914 में स्थापित 'अंजुमन-ए-खवातीन-ए-इस्लाम' क्या था?

(a) अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन
(b) अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उग्र पक्ष
(c) अखिल भारतीय मुस्लिम विद्यार्थी सम्मेलन
(d) अखिल भारतीय इस्लामी सम्मेलन

11. निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ था?
(a) नागपुर
(b) इलाहाबाद
(c) सूरत
(d) कोलकाता

12. भारतीय राष्ट्रवाद के नैतिक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत में कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवद्गीता पर टीकाएँ लिखी। इनमें से कौन इसका अपवाद है?
(a) श्री अरविन्द
(b) महात्मा गाँधी
(c) बाल गंगाधर तिलक
(d) राममनोहर लोहिया

13. निम्नलिखित में से कौन-सा एक, स्वराजवादी नेताओं के प्रति गाँधीजी की मनोवृत्ति को ठीक-ठीक वर्णित करता है?
(a) वे काउन्सिल में उनके प्रवेश के विरोधी नहीं थे
(b) वे उनकी नेकनीयती में पूरा भरोसा रखते थे और उन्हें अत्यन्त मूल्यवान और सम्मानित नेता मानते थे
(c) वे उनसे हार्दिक व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाए रखने के पक्ष में नहीं थे.
(d) वे स्वराजवादियों के विरूद्ध सरकार के अपमानजनक रवैये के प्रति तटस्थ थे और उनका बचाव नहीं करते थे.

14. भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. सर टॉमस रो, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रतिनिधि को जहाँगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई.
2. पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया.
3. कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मॉनसेरेट ने अकबर के साथ यात्रा की.

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 2 और 3 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) 1 और 3

15. 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार-पत्रों का दमन किस आलोचना की वजह से हुआ था?
(a) अंग्रेजी अधिकारियों की खर्चीली जीवन-शैली
(b) अंग्रेजी मालिकों द्वारा नील के कामगारों के साथ बुरा व्यवहार
(c) 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजी अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण
(d) अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा भारत के धार्मिक स्थानों का दुरूपयोग

16. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक, बाल गंगाधर तिलक के सम्बन्ध में सही नहीं है?
(a) उन्होंने आर्यों के उत्तरध्रुवीय आवास के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया
(b) उन्होंने गोवध-विरोधी समाज की स्थापना की
(c) उन्होंने पूना में होमरूल लीग की स्थापना की
(d) उन्होंने सहमति की उम्र विधेयक का समर्थन किया

17. निम्नलिखित सिद्धान्तों में से कौन-सा एक, थियोसॉफिकल सोसायटी द्वारा प्रचारित नहीं किया गया?
(a) कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास
(b) सार्वभौमिक भाईचारे एवं मानवता में विश्वास
(c) वेदान्त दर्शन में विश्वास
(d) अस्पृश्यता-उन्मूलन में विश्वास

18. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है?
(a) 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित नहीं था
(b) अनहैप्पी इण्डिया पुस्तक के लेखक दीनबन्धु मित्र थे
(c) झाँसी की रानी को ग्वालियर के सिन्धिया घराने ने शरण दी थी
(d) मंगल पाण्डे ने दिल्ली की ओर सिपाही अभियान का नेतृत्व किया.

19. निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड किया था?
(a) वॉरेन हेस्टिंग्ज
(b) लॉर्ड कार्नवालिस
(c) लॉर्ड वेलेजली
(d) लॉर्ड विलियम बैण्टिक

20. भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने किस पर विचार किया?
(a) महासंघ (फेडरेशन)
(b) परिसंघ (कनफेडरेशन)
(c) एकात्मक स्वरूप की सरकार
(d) राज्यों का संघ

21. निम्नलिखित राज्यों में से कौन-सा एक, राज्य व्यपगत नीति के अन्तर्गत लॉर्ड डलहौजी द्वारा सर्वप्रथम मिला लिया गया था?
(a) नागपुर
(b) झाँसी
(c) सम्बलपुर
(d) सतारा

22. भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में पहचानिए (सबसे प्रारम्भ से शुरूआत कीजिए)

1. व्यपगत नीति
2. सहायक सन्धि (सब्सिडियरी अलायंस)
3. लाहौर की सन्धि
4. पिट्स इण्डिया एक्ट

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए.

(a) 4, 2, 3, 1 (b) 1, 2, 3, 4
(c) 2, 1, 4, 3 (d) 3, 2, 1, 4

23. सुमेलित कीजिए

सूची I	सूची II
A. आयोथी थास	1. सत्यशोधक समाज
B. ज्योतिबा फूले	2. पूना सार्वजनिक सभा
C. महादेव जी. रानाडे	3. सेल्फ-रेस्पेक्ट मूवमेण्ट
D. ई वी रामास्वामी	4. द्रविड़ महाजन सभा

कूट

	A	B	C	D
(a)	4	2	1	3
(b)	3	1	2	4
(c)	4	1	2	3
(d)	3	2	1	4

24. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

सूची I (युद्ध)	सूची II (सन्धि)
A. तृतीय कर्नाटक युद्ध	1. सालबाई की सन्धि
B. तृतीय मैसूर युद्ध	2. लाहौर की सन्धि
C. प्रथम मराठा युद्ध	3. पेरिस की सन्धि
D. प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध	4. श्रीरंगपट्नम की संधि

कूट

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	2	4	1	2
(c)	3	4	1	2
(d)	3	1	4	2

25. रामप्रसाद विस्मिल का नाम किससे सम्बद्ध है?

(a) कानपुर षड्यन्त्र केस
(b) अलीपुर षड्यन्त्र केस
(c) काकोरी षड्यन्त्र केस
(d) मेरठ षड्यन्त्र केस

26. निम्नलिखित में से कौन-सी एक, 'प्रार्थना समाज' की माँग नहीं थी?

(a) स्त्री-शिक्षा
(b) विधवा-पुनर्विवाह
(c) लड़कों एवं लड़कियों की विवाह-आयु में वृद्धि करना
(d) अस्पृश्यता की समाप्ति

27. निम्नलिखित में से कौन-से कथन स्थायी बन्दोबस्त के सम्बन्ध में सही हैं?

1. इसने कृषकों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया.
2. जमींदारों को भूमि के स्वामियों के रूप में मान्यता मिली.
3. सरकार ने भूमि लगान माँग को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया.
4. जमींदार, कृषकों और सरकार के बीच मध्यस्थों की भूमिका निभाने लगे.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) 2, 3 और 4
(b) 3 और 4
(c) 1 और 4
(d) 1 और 3

28. शिमला का वायसरीगल लॉज एक सुविख्यात प्राचीन स्मारक है. इस स्मारक के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही हैं?

1. यह लॉज सत्रहवें वायसराय, अर्ल डफरिन द्वारा बनवाया गया था.
2. भवन का वर्तमान आकार लैंसडाउन के अर्ल ऑफ मारकिस द्वारा दिया गया था.
3. यह भारत की स्वतन्त्रता के पहले की तीन बैठकें, जिनमें कैबिनेट मिशन भी सम्मिलित है, आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए.

(a) 1, 2 और 3 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1 और 2

29. कथन 1: एनी बेसेण्ट ने होमरूल आन्दोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ-साथ काम किया.
कथन 2: एनी बेसेण्ट ने महसूस किया कि होमरूल आन्दोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था.

कूट

(a) दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1, का सही स्पष्टी करण है
(b) दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1, का सही स्पष्टी करण नही है
(c) कथन 1 सत्य है, किन्तु कथन 2 असत्य है
(d) कथन 1 असत्य है, किन्तु कथन 2 सत्य है

30. भारत की संविधान सभा, 1946 के प्रान्तीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी. संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे. उसपरिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया?

(a) विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों से स्वतन्त्र सदस्यों को मनोनीत

करने के द्वारा

(b) विभिन्न जाति तथा धार्मिक समूहों से स्वतन्त्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा

(c) भिन्न जाति, धार्मिक समूहों तथा महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा और देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और जनता से लिखित निवेदन माँगने के द्वारा

(d) देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन माँगने के द्वारा

31. भारत के लिए डोमिनियन स्थिति संविधान के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था?

(a) मॉर्ले-मिण्टो सुधार

(b) मॉण्टेग्यू-चैम्सफोर्ड सुधार

(c) दसाइमन कमीशन

(d) पहला गोलमेज सम्मेलन

32. आधुनिक भारत के सन्दर्भ में 'शाही थैली' क्या थी?

(a) एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को निजी तौर पर दी जाने वाली थैली

(b) भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सेवाओं के उपलक्ष्य में दी गई थैली

(c) भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान

(d) भारत के किसी पूर्व देशी राजा द्वारा भारत सरकार को दिया गया उपहार

33. केरल के राजा मार्तण्ड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सत्य नहीं है?

(a) उसने त्रावणकोर पर शासन किया

(b) उसने सामन्तों का दमन किया

(c) उसने शान्ति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी

(d) उसने मजबूत आधुनिक सेना संगठित की

34. 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसिसियों के सफल न होने का, निम्नलिखित में से कौन-सा एक कारण था?

(a) उन्होंने चन्दा साहिब तथा मुजफ्फर जंग जैसे कमजोर भारतीय पक्षों की तरफदारी की

(b) डूप्ले को निर्णायक समय पर वापस बुला लिया गया

(c) उन्होंने भारतीय शक्तियों के खिलाफ षड्यन्त्र किए

(d) उनकी व्यापार कम्पनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी

35. निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल था?

(a) लॉर्ड एमहर्स्ट

(b) लॉर्ड विलियम बेंटिक

(c) सर चार्ल्स मेटकाफ

(d) रॉबर्ट क्लाइव

36. व्यपगत के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी

(b) शासक की मृत्यु के पश्चात् इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासक की अनुमति नहीं दी

(c) किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात्, इसने भारतीय राज्य का संयोजन अनिवार्य बना दिया

(d) इसने भारतीय राज्य का संयोजन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिये जाने का ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन न हुआ हो

37. वर्ष 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया गया होता, यदि

(a) अवध के नवाब ने ब्रिटिश के साथ गठजोड़ कर लिया होता

(b) अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता

(c) अवध का नवाब ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा होता

(d) अवध के नवाब का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी होता

38. स्वामी विवेकानन्द के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही है?

1. उनका विश्वास था कि वेदान्त पूर्ण रूप से तर्कसंगत था.
2. उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की, कि उन्होंने बाहरी विश्व से सम्पर्क छोड़ दिया है.
3. उन्होंने जाति व्यवस्था की निन्दा की.
4. उन्होंने वेद को अमोघ माना.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4

(c) 1, 3 और 4 (d) केवल 1 और 2

39. चम्पारण सत्याग्रह के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यह नील की खेती से सम्बन्धित था.
2. इसकी शुरूआत इसलिए हुई क्योंकि यूरोपीय बागान मालिकों ने जमींदारों का दमन किया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

40. वर्ष 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. यह कार्य घण्टों के सम्बन्ध में कामगारों एवं यूरोपीय मिल मालिकों के बीच विवाद से सम्बन्धित था.
2. गाँधीजी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी.

उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

41. दादाभाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति 'पॉवर्टी एण्ड अन-ब्रिटिश रूल इन इण्डिया' में प्रस्तुत किए गए 'अपवहन सिद्धान्त' शब्द को निम्न लिखित कथनों में से कौन-सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है?
(a) कि भारत की राष्ट्रीय सम्पत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई प्रतिफल नहीं मिलता था.
(b) कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था.
(c) कि ब्रिटिश उद्योगपतियों को साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे.
(d) कि ब्रिटिश वस्तुएँ भारत में आयातित की जा रही थीं जिससे देश दिनों-दिन अधिकाधिक गरीब होता जा रहा था.

42. अन्तिम शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी माल के प्रसार और विदेशी माल के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सर्वाधिक तात्कालिक कारण था?
(a) स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र को कम करने का कर्जन का अभिकल्प
(b) विश्वविद्यालयों को नियन्त्रित करने का कर्जन का प्रयास
(c) कर्जन का बंगाल विभाजन
(d) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता को नियन्त्रित करने की कर्जन की योजना

43. स्थायी बन्दोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. स्थायी बन्दोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसीडेन्सियों के हिस्सों में लागू किया गया.
2. स्थायी बन्दोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाया.
3. स्थायी बन्दोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते थे.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए.
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

44. गाँधीजी ने भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलन का अग्रपंक्ति से नेतृत्व किया और उनका नेतृत्व उस अधिक व्यापक दर्शन से प्रेरित हुआ जिसे उन्होंने पूरे आन्दोलन के दौरान पोषित किया.
निम्नलिखित में से कौन-सा एक, इस दर्शन पर आधारित अनवरत आन्दोलन था, तथा एक विशिष्ट आन्दोलन नहीं था?
(a) असहयोग आन्दोलन
(b) स्वदेशी आन्दोलन
(c) भारत छोड़ो आन्दोलन
(d) सविनय अवज्ञा आन्दोलन

45. चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-से सही हैं?
1. मद्रास परिषद ने मैसूर पर कठोर एवं तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव दिया.
2. लॉर्ड वेलेजली ने त्रिराष्ट्रीय सन्धि को पुनर्जीवित करने की कोशिश की.
3. अंग्रेजों के विरूद्ध समर्थन प्राप्त करने हेतु टीपू ने अरब, वर्साय, मॉरीशस तथा काबुल में दूत भेजे.
4. युद्ध बहुत ही थोड़े समय का था तथापि निर्णायक था.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए.
(a) 2, 3 और 4 (b) 1, 3 और 4
(c) 2 और 4 (d) 1 और 3

46. शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त, एक अन्य महत्त्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी उनको दिया गया है. निम्नलिखित में से उस मसौदे को पहचानिए.
(a) भारतीय दण्ड-संहिता का मसौदा
(b) भारतीय वन नीति का मसौदा
(c) जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का मसौदा
(d) समुद्री व्यापार नीति का मसौदा

47. निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जिसका यह कथन है 'कुछ सौ अंग्रेजों द्वारा सारी राजनीतिक चेतनायुक्त जनसंख्या के सक्रिय विरोध को देखते हुए उस पर शासन करना काफी असम्भव होगा.'
(a) लखनऊ में अप्रैल 1947 में काँग्रेस जनों के मध्य भाषण में जवाहरलाल नेहरू
(b) जनवरी 1947 में अर्नेस्ट बेविन को लिखे एक निजी पत्र में क्लीमेण्ट एटली
(c) दिसम्बर 1946 में ब्रिटिश संसद को दिए गए नोट में लॉर्ड माउण्टबेटन
(d) जनवरी 1946 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखे गए पत्र में वायसराय वेवेल

48. कथन 1: गाँधीजी यह महसूस करने में विफल रहे कि खिलाफत एक अपर देशीय मुद्दा था.
कथन 2: खिलाफत आन्दोलन 1923 ई. तक अपनी साख खो बैठा, क्योंकि मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में एक धर्मनिरपक्ष गणतन्त्रीय सरकार की स्थापना कर दी.
कूट:
(a) दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1, का सही स्पष्टीकरण है

(b) दोनों कथन सत्य हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) कथन 1 सत्य है, किन्तु कथन 2 असत्य है
(d) कथन 1 असत्य है, किन्तु कथन 2 सत्य है

49. कथन 1: पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन ने खान अब्दुल गफ्फार खाँ के नेतृत्व में लोक चरित्र ग्रहण कर लिया.
कथन 2: नेहरू रिपोर्ट (1928) ने तर्क दिया कि भारत के लिए 'अगला तात्कालिक कदम' डोमिनियन स्टेटस ही होगा.
कूट:
(a) दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 कथन 1, का सही स्पष्टीकरण है
(b) दोनों कथन सत्य हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) कथन 1 सत्य है, किन्तु कथन 2 असत्य है
(d) कथन 1 असत्य है, किन्तु कथन 2 सत्य है

50. निम्नलिखित में से कौन-सा एक, 1931 के गाँधी-इर्विन समझौते का अंश था?
(a) सत्याग्रहियों पर बर्बर हमला करने के दोषी पुलिसवालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई
(b) नेहरू का 1931 ई. के गोलमेज सम्मेलन में काँग्रेस का प्रतिनिधित्व करना
(c) सम्मेलन की विषय-सूची से साम्प्रदायिक प्रश्न को हटाना
(d) आगजनी और हिंसा के दोषियों को छोड़कर बाकी राजनीतिक बन्दियों की रिहाई

उत्तर

1.	(a)	18.	(a)	35.	(b)
2.	(b)	19.	(b)	36.	(d)
3.	(d)	20.	(d)	37.	(a)
4.	(d)	21.	(d)	38.	(c)
5.	(b)	22.	(a)	39.	(c)
6.	(c)	23.	(c)	40.	(b)
7.	(b)	24.	(c)	41.	(a)
8.	(c)	25.	(c)	42.	(c)
9.	(b)	26.	(d)	43.	(b)
10.	(a)	27.	(a)	44.	(b)
11.	(c)	28.	(c)	45.	(a)
12.	(c)	29.	(a)	46.	(a)
13.	(a)	30.	(c)	47.	(b)
14.	(b)	31.	(b)	48.	(d)
15.	(c)	32.	(c)	49.	(b)
16.	(d)	33.	(c)	50.	(d)
17.	(d)	34.	(d)		

दिसम्बर के महत्वपूर्ण दिवस

दिनांक	महत्त्व
1 दिसम्बर	• नागालैंड राज्य दिवस
	• विश्व एड्स दिवस
	• **BSF** स्थापना दिवस
2 दिसम्बर	• विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस
	• राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस
3 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस
4 दिसम्बर	भारतीय नौसेना दिवस
5 दिसम्बर	विश्व मृदा दिवस
7 दिसम्बर	सशस्त्र सेना झंडा दिवस
9 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस
10 दिसम्बर	मानवाधिकार दिवस
11 दिसम्बर	यूनिसेफ दिवस
16 दिसम्बर	विजय दिवस
18 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस
20 दिसम्बर	अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस
24 दिसम्बर	राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस
25 दिसम्बर	सुशासन दिवस

समसामायिक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न

1. हाल ही में प्रकाशित 'लाल सलाम' उपन्यास किसने लिखा ?
   (a) स्मृति ईरानी
   (b) हेमा मालिनी
   (c) ममता बनर्जी
   (d) वैकया नायडू
   उत्तर- (a)

2. 'वीर चक्र' सम्मान इसमें से किसे दिया गया है ?
   (a) मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल
   (b) ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान
   (c) नायब सूबेदार सोमबीर
   (d) कोर ऑफ इंजीनियर्स सैपर प्रकाश जाधव
   उत्तर– (b)

3. वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किस संस्था को मिला है ?
   (a) स्माइल
   (b) आई.सी.टी.
   (c) गूँज
   (d) प्रथम
   उत्तर- (d)

4. नीति आयोग द्वारा एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 के सन्दर्भ में सही कूट का चयन कीजिये
   1. सूचकांक के लिए कुल 56 शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया था.
   2. इस सूचकांक में शिमला (हिमाचल प्रदेश) को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है.
   3. अंतिम स्थान के तीन शहरी क्षेत्र क्रमश: धनबाद (झारखण्ड), मेरठ (उत्तर प्रदेश) और ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) हैं

   (a) केवल 1 असत्य है. **(b)** 1 और 2 दोनों असत्य है.
   (c) 2 और 3 असत्य है. **(d)** तीनों सत्य हैं.
   उत्तर- (d)

5. 'विश्व मत्स्य दिवस' के अवसर पर,मत्स्य पालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया है.
   (a) आंध्र प्रदेश
   (b) उत्तर प्रदेश
   (c) गोवा
   (d) तमिलनाडु
   उत्तर- (a)

6. मैग्डेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी?
   (a) स्वीडन
   (b) फ्रांस
   (c) इटली
   (d) नॉर्वे
   उत्तर- (a)

7. ग्रह रक्षा प्रणाली डार्ट लॉन्च के विषय में सही कथन का चयन करें
   1. यह दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली डबल एस्टेरॉएड रिडायरेक्शन टेस्ट (डार्ट) है
   2. नासा ने इस मिशन को लांच नहीं किया है

   इसमें से कौन सा कथन है ?
   (a) केवल 1 सत्य है. **(b)** 1 और 2 दोनों सत्य है.
   (c) 1और 2 दोनों असत्य है. **(d)** केवल 2 सत्य है.
   उत्तर- (a)

8. सही कथन का चयन करें
   1. मुगल कालीन सब्ज बुर्ज अजमेर में स्थित है जिसका निर्माण 1530 में हुआ था.
   2. यह सब्ज बुर्ज, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल एक ईमारत है.
   3. यह इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है.

   (a) केवल 1 सत्य है. **(b)** 1 और 2 दोनों सत्य है.
   (c) 2 और 3 सत्य है. **(d)** तीनों सत्य हैं.
   उत्तर- (c)

9. निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें
   1. नोरोवायरस को पहले नोरवॉक वायरस के नाम से जाना जाता था. इसका एक अन्य नाम विंटर वॉमिटिंग डीजीज भी है.
   2. इस वायरस की उत्पति अमेरिका से हुई है.

   (a) केवल 1 सत्य है. **(b)** 1 और 2 दोनों सत्य है.
   (c) 1और 2 दोनों असत्य है. **(d)** केवल 2 सत्य है.
   उत्तर- (b)

10. निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें
    1. भारत सरकार ने 2025 तक गैसोलीन के साथ 10% इथेनॉल मिश्रण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
    2. इथेनॉल एक जैव ईधन है जिसका उत्पादन गेंहूं, आलू, गन्ना आदि कृषि उत्पादों से होता है.

    (a) केवल 1 सत्य है. **(b)** 1 और 2 दोनों सत्य है.
    (c) 1और 2 दोनों असत्य है. **(d)** केवल 2 सत्य है.
    उत्तर- (d)

Paper IV केस स्टडी

आप कोलकता के जिलाधिकारी हैं. अभी हाल ही में एक भारतीय दवा कंपनी ने कोरोना का टीका विकसित किया है. इसने 92 प्रतिशत सफलता दर के साथ, परीक्षण के सभी चरणों को उत्तीर्ण कर लिया है. इस टीके की लागत कम है और इसका कोई दुष्प्रभाव भी सामने नहीं आया है. सरकार ने इसके प्रयोग की स्वीकृति दे दी है। किस्मत से पहले चरण के टीकाकरण के लिए आपके जिले को चुन लिया गया है। सरकार ने प्रथम चरण में केवल बुजुर्गों (जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है) के टीकाकरण के लिए निर्देश दिए है.

लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने टीके के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में अफवाह फैला दी। विदेशों से सोशल मीडिया में कई छद्म वीडियो चस्पा किए गए, जिनमें दावा किया गया कि ये टीका महत्वपूर्ण मानव अंगों को क्षति पहुंचा सकता है.

इससे बुजुर्गो में डर व्याप्त हो गया, और उन्होंने टीका लगवाने से मना कर दिया.

(a) आपके पास क्या-क्या विकल्प उपलब्ध है.

(b) प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करके बताइए कि आप कौन-सा विकल्प चुनेंगे.

उसके कारण भी बताइए.

दिए गए मामले में मैं कोलकाता का जिलाधिकारी हूं. मुझे बुजुर्गों को कोरोना टीका लगवाने के लिए सहमत करना है. इस मामले में वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, करुणा और सेवा भावना जैसे मूल्य निहित हैं.

विकल्प (1)- टीकाकरण का अवसर जिले के युवा लोगों को हस्तांतरित कर देंगे.

गुण- अधिकांश युवा शिक्षित होते हैं. वे तर्क का प्रयोग करते हैं. इसलिए उन्हें समझाना आसान होता है. एक बार ये प्रक्रिया आरम्भ कर देंगे तो द्वितीय चरण में बुजुर्ग भी टीकाकरण के लिए सहमत हो जाएंगे.

दोष- सरकार अपने निर्देशों के विपरीत युवाओं को टीका देने की मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर सकती है. कुछ वृद्ध व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है.

विकल्प (2)- टीकाकरण का अवसर दूसरे जिले को हस्तांतरित कर दें।

गुण- दूसरे जिले के साथी नागरिकों को लाभ मिलेगा.

दोष- वृद्ध लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। यह अवसर की हानि है. इससे दूसरे जिलों के नागरिकों के आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

विकल्प (3)- बुजुर्गों के टीकाकरण के लिए बल-प्रयोग करेंगे.

गुण- इससे बुजुर्ग कोरोना संक्रमण से सुरक्षित हो जायेंगे.

दोष- वृद्ध लोगों के प्रति बल-प्रयोग पूर्णत: अनैतिक होगा. यह टीका न लगवाने की उनकी इच्छा को ही बल प्रदान करेगा. वे न्यायालय की शरण में जा सकते हैं.

विकल्प (4)-सर्वप्रथम मैं मुख्य सचिव से अनुरोध करूँगा कि वे साइबर सेल को इंटरनेट से भ्रामक वीडियो हटाने के लिए निर्देश दें। तत्पश्चात् मैं टीका बनाने वाली कम्पनी के प्रबंधन से अनुरोध करूँगा कि वे द्वितीय और तृतीय चरण के टीका परीक्षण में शामिल व्यक्तियों की जानकारी (नाम, पता और फोन नम्बर) अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए। मैं इनमें से कुछ लोगों से सम्पर्क करके अपने जिले में आमंत्रित करूँगा.

हम इन व्यक्तियों के साथ पूरे जिले में सार्वजनिक बैठक (2 गज की दूरी के साथ) आयोजित करेंगे। जहाँ ये व्यक्ति जनता के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे और उनके संदेहों का समाधान करेंगे। हम इन सार्वजनिक बैठकों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रचारित कर देंगे. इसके अतिरिक्त मैं प्रत्येक वार्ड और ग्राम सभा में चिकित्सा परामर्शदाताओं की नियुक्ति करूँगा जो घर-घर जाकर बुजुर्ग व्यक्तियों एवं उनके परिवारी जनों को टीका के प्रति आश्वस्त करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया का सहयोग लूँगा और लोगों के संदेहों एवं प्रश्नों के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन भी स्थापित करूँगा. ये सारे प्रयास एक सकारात्मक वातावरण बनाएँगे। अन्त में टीकाकरण वाले दिन एक सार्वजनिक समारोह (2 गज की दूरी के साथ) में, मैं सर्वप्रथम स्वयं टीकाकरण कराऊँगा (उच्च अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति से). इससे बुजुर्ग लोगों में आत्मविश्वास आ जाएगा और वे टीकाकरण करा लेंगे.

इससे जनता के सभी संदेह दूर हो जायेंगे और टीकाकरण की प्रक्रिया सफलता के साथ पूर्ण हो जाएगी. बुजुर्ग लोगों को आवश्यक सुरक्षा कवच मिल जाएगा.

मैं इसी विकल्प का चयन करूँगा.

NOTES

जगदीश चंद्र बोस : जयंती विशेष

भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर, 1858 को मेमनसिंह गाँव (वर्तमान बांग्लादेश) में हुआ था. भारत के प्रसिद्ध भौतिकविद् तथा पादपक्रिया वैज्ञानिक बोस ने अपने किताबों में अपने अनुभव वअनुसंध ान को व्यक्त किया है.कुछ प्रमुख किताब हैं - सजीव तथा निर्जीव की अभिक्रियाएँ (1902), वनस्पतियों की अभिक्रिया (1906), पौधों की प्रेरक यांत्रिकी (1926) इत्यादि.

जगदीश चंद्र बोस रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर अध्ययन करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे,जिन्होंने भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपने ज्ञान और आविष्कार से सिद्ध कर दिया कि भारत के पास भी स्वदेशी वैज्ञानिक शोध और आविष्कार की क्षमता है. बोस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने केस्कोग्राफ जैसे यंत्र को विकसित कर प्लांट रिसर्च में एक रिवोलुशन ला दिया.इन्होने वैज्ञानिक मार्कोनी से पहले रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था.विभिन्न संचार माध्यमों, जैसे- रेडियो, टेलीविजन, रडार, सुदूर संवदेन यानी रिमोट सेंसिंग सहित माइक्रोवेव ओवन की कार्यप्रणाली में बसु का योगदान अहम है. आज पूरी दुनिया बोस को मार्कोनी के साथ बेतार संचार के पथप्रर्दशक कार्य के लिए रेडियो का सह-आविष्कारक मानती है. एक ओर जहां बोस ने बहुत छोटी तरंगें उत्पन्न करने का तरीका दिखाया,वहीं दूसरी तरफ हेनरिक हट्र्ज के रिसीवर को उन्होंने एक उन्नत रूप दिया. कुछ समय बाद जब यह साबित हुआ कि मार्कोनी के वायरलेस या बेतार रिसीवर का आविष्कार जगदीश चन्द्र बोस ने किया था तो यह जानकर सभी हैरान थे.मार्कोनी के प्रदर्शन से पहले ही वर्ष 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था.

बोस ने ऐसे यंत्र का निर्माण किया,जिससे 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न की जा सकती थीं. यह यंत्र इतना छोटा था कि उसे एक छोटे बक्से में कहीं भी ले जाया जा सकता था. उन्होंने दुनिया को उस समय एक बिल्कुल नई तरह की रेडियो तरंग दिखाई, जो एक सेंटीमीटर से पांच मिलिमीटर की थी, जिसे आज माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग कहा जाता है. बोस ने ही सबसे पहले दर्शाया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी सुदूर स्थल तक हवा के सहारे पहुंच सकती हैं. ये तरंगें किसी क्रिया को दूसरे स्थान से नियंत्रित भी कर सकती हैं. उनकी यही धारणा बाद में रिमोट कंट्रोल सिस्टम का सैद्धांतिक आधार बनीं.

आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण जैसे वेव गाईड, ध्रुवक, परावैद्युत लैंस, विद्युतचुम्बकीय विकिरण के लिये अर्धचालक संसूचक, इन सभी उपकरणों का उन्नींसवी सदी के अंतिम दशक में बोस ने अविष्कार किया और उपयोग किया था.बोस ने ही सूर्य से आने वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था जिसकी पुष्टि 1944 में हुई. बोस को उनके कार्यों के लिए 'इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स' ने जगदीश चन्द्र बोस को अपने 'वायरलेस हॉल ऑफ फेम' में सम्मिलित किया है.

बोस ने पादप विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया था. बोस ने पादप कोशिकाओं पर विद्युतीय संकेतों के प्रभाव का अध्ययन किया.उनके प्रयोग इस तथ्य की ओर संकेत कर रहे थे कि संभवत: सभी पादप कोशिकाओं में उत्तेजित होने की क्षमता होती है. ठंडक, गर्मी, काटे जाने, स्पर्श और विद्युत उद्दीपन के साथ-साथ बाहरी नमी के कारण भी पौधों में एक्शन पोटेंशल उत्पन्न हो सकता है.उन्होंने ऐसे संवेदनशील यंत्र बनाए, जो पौधों में भौतिक, रासायनिक,यांत्रिक या विद्युतीय स्तर की अति सूक्ष्म जैविक क्रियायों को भी दर्ज कर सकते थे.

वर्ष 1901 से बोस ने अपने प्रयोग के लिए छुई-मुई यानी मिमोसा पुडिका और शालपर्णी यानी डेस्मोंडियम गाइरेंस का उपयोग किया. छुई-मुई की पत्तियों को छुएं तो वे एक दूसरे की ओर झुकने लगतीं हैं. बोस ने डिसमोडियम गायरेन्स के विद्युतीय स्पंदन को जीवों की रिकॉर्ड की गई हृदय गति से तुलना करने के लिए स्पन्दन रिकॉर्डर का प्रयोग किया.

पौधों में धीमी गति से हो रही वृद्धि को मापने के लिए बोस ने खुद ही एक अत्यन्त संवेदी यंत्र बनाया. उन्होंने इस यंत्र को क्रेस्कोग्राफ नाम दिया. यह उपकरण पौधे की वृद्धि को स्वत: दस हजार गुना बढ़ाकर दर्ज करने की क्षमता रखता था.

बसु ने दर्शाया कि पौधों में हमारी तरह ही दर्द का एहसास होता है. अगर पौधों को काटा जाए या फिर उनमें जहर डाल दिया जाए तो उन्हें भी तकलीफ होती है और वह मर भी सकते हैं.एक अन्य अध्ययन क्षेत्र,जिसने बसु को आकर्षित किया, वह था पौधों में जड़ों से तने और पत्ते तक पानी का ऊपर चढ़ना. पौधे जो पानी सोखते हैं, उसमें अनेक प्रकार के कार्बन तथा अकार्बनिक तत्व भी होते हैं. यह जलीय मिश्रण का पौधों में ऊपर चढ़ना "असेन्ट ऑफ सैप" कहलाता है. पौधों की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं पर समय के प्रभाव के अध्ययन की बुनियाद जगदीश चंद्र बसु ने डाली थी, जो आज विज्ञान की एक शाखा क्रोनोबायोलॉजी के नाम से प्रसिद्ध है.

राजव्यवस्था शब्दावली

राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य

77(1) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी.

77(2) राष्ट्रपति अधिप्रमाणन के नियम व रीति बना सकेगा जिसके आधार पर उसके नाम से निष्पादित आदेश तथा अन्य लिखत की वैधता प्रदर्शित हो। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केन्द्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों के मध्य कार्य सहजता से वितरित हो सके.

वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है. वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। वह भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयेग के अध्यक्ष एवं सदस्यों राज्यों के राज्रूपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है.

वह केन्द्र के प्रशासनिक कार्यो और विधायिका के प्रस्तावों से सम्बंधित सूचना की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है.

राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रतिवेदन की मांग कर सकता है जिसका निर्णय किसी मंत्री ने लिया हो किन्तु पूरी मंत्रीपरिषद ने इसका अनुमोदन नही किया हो.

वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है.

वह स्वयं द्वारा नियुक्ति प्रशासकों के द्वारा केन्द्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है.

वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त है.

वह केन्द्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अन्तर्राज्यीय परिषद, की नियुक्ति करता है.

विधायी शक्तियां:

धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

वह केंन्द्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है.

अनुदान की कोई मांग उसकी सिफारिश के बिना नही की जा सकती है.

वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है.

वह राज्य व केन्द्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है.

कूटनीतिक शक्तियां:

अन्तर्राराष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते है यद्यपि इनके लिए संसद की अनुमति आवश्यक है. वह अन्तर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों भारत का प्रतिनिधित्व करता है. भारतीय कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों व उच्च चायुक्तों को भेजता है तथा उनका स्वागत करता है.

आपात कालीन शक्तियां:

- अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात में शक्तियां
- अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन में शक्तियां
- अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात में शक्तियां

सैन्य शक्तियां:

वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है. राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा. स्थगन तथा लोकसभा का विघटन भी करेगा.

- वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करेगा.
- वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है.
- वह लोक सभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर लोकसभा के किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है.
- वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुडे व्यक्तियों में से 12 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है.
- अनुच्छेद 111 के अनुसार- राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला विधेयक पर राष्ट्रपति-
- अनुमति देगा या पुर्नविचार के लिए लौटा देगा.
- अनुच्छेद 200 के अनुसार -

राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है। तब-

- राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देता है.
- विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित करता है.
- राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक (यदि धन विधेयक नही है तो) को राज्य विधायिका को पुर्नविचार हेतु लौटा दे. यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुन: राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नही है.
- अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है. यह अध्यादेश जारी कर सकता है संसद की पुन: बैठक के 6 सप्ताह के भीतर वापस ले लिया जाना चाहिए. राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है.
- वह महानियंत्रक लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है.

न्यायिक शक्तियां:

राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां व कार्य निम्नलिखित है:

- वह भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है.
- वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह मांग सकता है परन्तु यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्य कारी नही है.
- अनुच्छेद 72 के अनुसार किसी अपराध के लिए दोषासिद्ध व्यक्ति के दण्डादेश का निलम्बन, क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार की शक्ति प्राप्त है.
- दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति उन सभी मामलों में प्राप्त है जहां-

दण्ड या दण्डादेश ऐसे विषय सम्बंधी किसी विधि के विरूद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है.

Achievers of Dhyeya IAS who made us proud.

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

पिछले 18 वर्षों में हमारे संस्थान से IAS में 1650+ एवं PCS में 2500+ चयन हुए हैं

KANISHAK KATARIA RANK 1
JUNAID AHMED RANK 3
SAUMYA PANDEY RANK 4
LOK BANDHU RANK 7
SURYAPAL GANGWAR RANK 8
JAIPRAKSH MAURYA RANK 9
MAHESH KUMAR RANK 14

SHIVANI GOYAL RANK 15
SHWETA SINGHAL RANK 17
SRIMAN SHUKLA RANK 18
PRIYANKA NIRANJAN RANK 20
ADESH TITARMARE RANK 21
NEHA PRAKASH RANK 22
ANURAJ JAIN RANK 24

AJIT RANK 26
DIBYA JYOTI PARIDA RANK 26
KARMVEER SHARMA RANK 28
ANJNAY KUMAR SINGH RANK 29
PARI BISHNOI RANK 30
GANGA SINGH RANK 33
ARUN RAJ RANK 34

GAURAV KUMAR RANK 34
KANCHAN RANK 35
BRAHMADEV TIWARI RANK 37
SHAILENDRA SINGH RANK 38
POOJA GUPTA RANK 42
DIVYANSHU NIGAM RANK 44
ASHWIN MUDGAL RANK 45

SAURABH GAHARWAR RANK 46
DEEPAK KUMAR DUBEY RANK 46
ABHISHEK SINGH RANK 48
RENJINA MARY V. RANK 49
RANGASHREE RANK 50
ILA TRIPATHI RANK 51
ASHISH MISHRA RANK 52

5 times Rank 1 in last 8 years of UPPCS

1st RANK Vaibhav Mishra
1st RANK Arvind K. Singh
1st RANK Himanshu Gupta
1st RANK Abhinav R. Shriwastava
1st RANK Anuj Nehra

MPPCS TOPPER
1st RANK Sampada Saraf

BPSC TOPPER
1st RANK Sanjeev Kumar Sajjan

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DhyeyaIAS, one and half decade old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4000 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 | **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 | **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 | **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 | **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 | **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow , UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 | **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha - 751024, Ph: 9818244644/7656949029

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

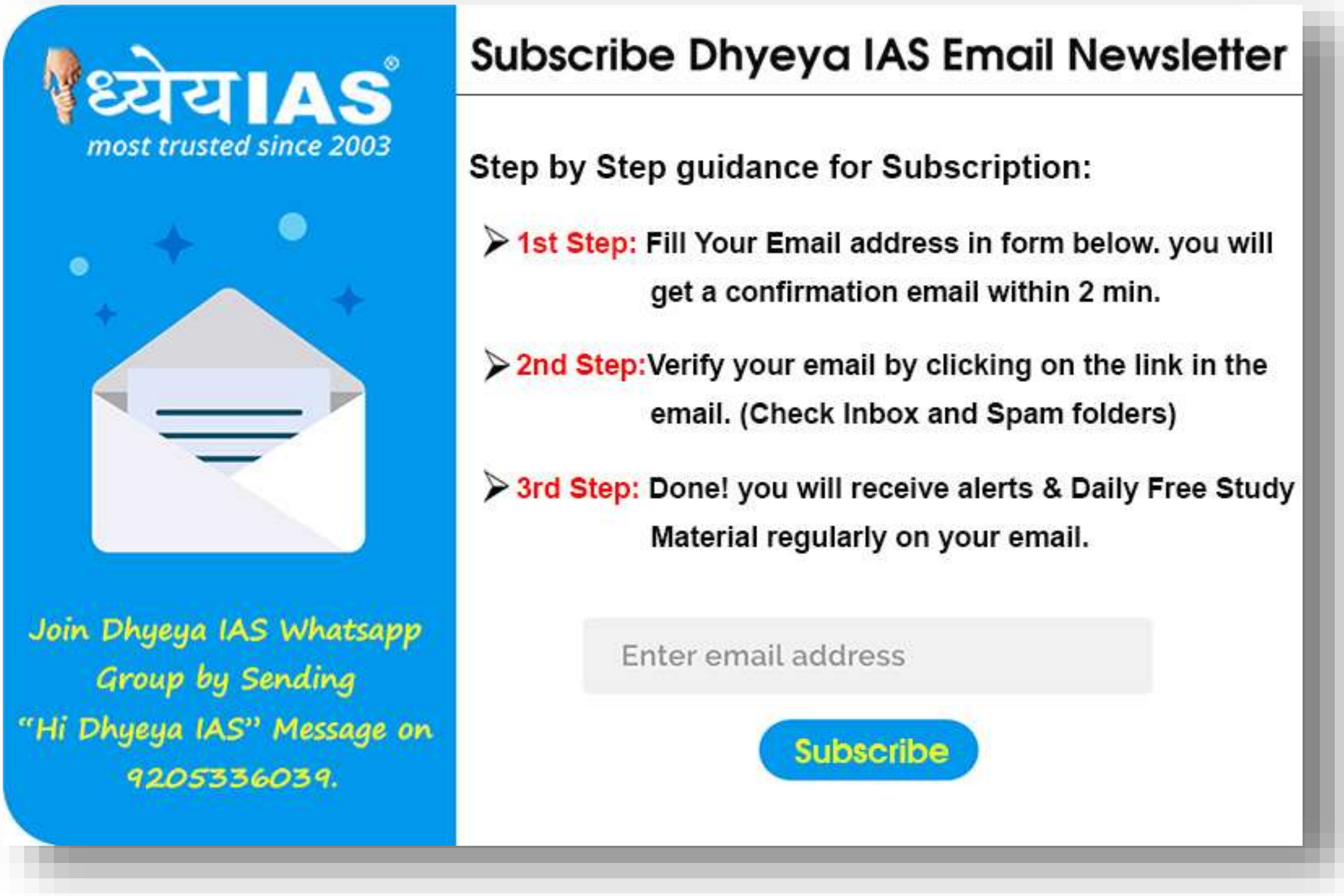

ध्येयIAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744